राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का चतुर्थ दिवस [संख्या ३

गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११'१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७०

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ७१

श्री पी० के० चौधरी।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री हज़ारीलाल बकोलिया।

चम्बल बांध से पैदा होने वाली बिजली

७३. श्री हज़ारीलाल बकोलिया (केकड़ी) : क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) चम्बल बांध से पैदा होने वाली बिजली कब तक दी जायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि चम्बल बांध से पैदा होने वाली बिजली कुओं से सिंचाई के लिये पानी निकालने के लिये भी दी जावेगी ?

(३) यह बिजली अजमेर ज़िले के किन किन स्थान में किस किस उपयोग में लाई जायेगी ?

उप मन्त्री, विद्युत विभाग : (श्री भीखा भाई)

(१) चम्बल से बिजली दो स्टेजों में तैयार की जावेगी। पहली स्टेज में गांधी सागर डैम पर पॉवर हाउस बन रहा है। दूसरी स्टेज में राणा प्रताप सागर डैम पर पॉवर हाउस बनेगा। पहली स्टेज में कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर को १९६० के आखिर तक और उदयपुर, अजमेर को १९६१ के आखिर तक बिजली दी जा सकेगी।

(२) जी हां।

Page No.2

(श्री भीखा भाई)

(३) अजमेर ज़िले में नीचे लिखी जगहों को बिजली दी जावेगी :

अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़, विजय नगर। यह बिजली हर काम के लिए दी जा सकेगी।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : गांधी सागर से बिजली देने का काम कब तक शुरु कर दिया जावेगा ?

गृह मन्त्री "श्री रामकिशोर व्यास" : १६६० के आखिर तक।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): रास्ते में पड़ने वाले छोटे-छोटे स्थानों को भी बिजली दी जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सम्भव होगा तो वहां भी दे देंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या वहां पर खम्भे और वायरिंग का काम शुरु कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये.... काम शुरु कर दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : यह कब तक हो जाएगा।

श्री रामकिशोर व्यास : टोवर्स के लिये (अश्रव्य)

श्री रामेश्वरदयाल : प्रताप सागर का काम कब तक शुरु होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये प्लानिंग कमीशन को लिखा गया है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सवाई माधोपुर से जयपुर जाने वाली बिजली नवाई होकर जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा ही है। रूट उधर से ही है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मुझे ऐसी सूचना मिली है कि १६६२ तक प्रताप सागर से बिजली नहीं मिल सकेगी। कुछ ऐसा मालूम हुआ कि ६२ तक बिजली नहीं मिल सकेगी। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमको बिजली कब तक मिल जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : प्लानिंग कमीशन को लिखा गया है।

श्री दलीपसिंह (बांरा) : क्या यह सही है कि इससे झालावाड़ को बिजली नहीं मिलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सोच रहे हैं।

श्री हज़ारीलाल बकोलिया : अजमेर से विजयनगर किस तरफ होती हुई लाइन जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए आप अलग प्रश्न पूछें इसकी मुफिस्सल लिस्ट नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : ऐसी स्थिति में जब कि राणा प्रतापसागर डैम से बिजली जल्दी नहीं मिलने वाली है उस समय तक मावली जंक्शन पर कोई बिजली के लिये इन्जिन लगा कर बिजली की व्यवस्था करने को सरकार तैयार है ?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास : राणा प्रताप सागर की स्कीम प्लानिंग कमीशन के पास एप्रुवल के लिये गई हुई है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट खुद इस बारे में डेफिनेट नहीं है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से या चौथी पंच वर्षीय योजना तक यह स्कीम आवे, तो ऐसी हालत में मावली स्टेशन पर जो जंक्शन स्टेशन है वहां पर छोटा स्केलेट पॉवर हाउस सरकार बनाने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट इस बात पर डेफिनेट है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : झालावाड़ जिले के बारे में कब तक डेफिनेट हो जावेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : इसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : कब बिजली मिलेगी और कब लाइन पहुँचेगी ?

श्री अध्यक्ष : हमें आशा रखनी चाहिये।

प्रश्न संख्या ७४

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

जयपुर भरतपुर सड़क को नेशनल हाई वे की कोटि में लाना

७५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर भरतपुर सड़क उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगर आगरा तथा राजस्थान के भरतपुर और जयपुर नगरों को सीधा मिलाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सड़क पर प्रतिदिन अनेक देशी और विदेशी प्रर्यटकों का आवागमन होता रहता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इसको शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाई वे) की कोटि में लाने तथा उसका तदनुसार विकास करने का विचार करती है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह विषय भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, की हैं।

प्रश्न संख्या ७६

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ७७

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील देवली और उनियारा में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालयों की मांग -

७८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील देवली और तहसील उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टौंक में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ और दवाखाने किस किस ग्राम में खोले गये हैं ?

(२) क्या उपरोक्त तहसीलों की जनता द्वारा सरकार से ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग की गई थी ? अगर हां, तो किस किस कस्बा और ग्राम वालों द्वारा ?

(३) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त तहसीलों में कहीं ऐलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाखाने खोले गये हैं ? अगर हां, तो कहां-कहां ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) कोई नहीं खोली गई।

(२) ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी के लिये तो किसी भी ग्राम वाले की मांग प्राप्त नहीं हुई परन्तु आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए ग्राम सोप, तहसील उनियारा की जनता ने मांग की है।

(३) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि दूणी ग्राम की जनता ने, वहां एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के लिए सरकार के पास प्रार्थना की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास तो तहसील उनियारा के ग्राम सोप की ओर से औषधालय खोलने की मांग आई थी डिस्पेन्सरी की नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां से प्रार्थना आई थी और सेक्रेटरी से चिट्ठी भी चली गई थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूणी में एक डिस्पेन्सरी खोल दी जावेगी, लेकिन जब तहसील वहां से हट गई तो नहीं खोली गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप आयुर्वेदिक और ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी किस की मांग पर स्थापित करते हैं, जनता की मांग पर या सरकार की मर्ज़ी पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयुर्वेदिक औषधालय तो ब्लॉक की रिकमन्डेशन्स पर और ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी की सिफारिश पर।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या कोई आबादी की संख्या इसके लिए निश्चित की गई है, जैसा कि स्कूल के लिए रखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हर एक जगह सेन्टर और एवरेज़ आता है वह ३·४ में से एक होता है।

रावाराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि सोप की दरख्वास्त आई थी वहां आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोल दी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी की सिफारिश पर ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोली जाती है और..

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने नीति क्या है ? डिस्पेन्सरीज़ खोलने के लिए सरकार के सामने नीति जन्य कोई चीज़ है या केवल मांग पर खोल दी जाती है। हम सरकार की नीति जानना चाहते हैं और यह नीति जानने का प्रश्न भी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की नीति स्पष्ट है कि हर गांव में डिस्पेन्सरी खुलनी चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर : नीति सरकार की दृष्टि से स्पष्ट है लेकिन हमें वह नीति मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हर ब्लॉक में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हों और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी सुविधा के अनुसार हो।

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो नीति नहीं हुई। यह तो एक वितरण का नमूना हुआ। गवर्नमेन्ट ने स्पष्ट कहा कि गवर्नमेन्ट की स्पष्ट नीति है लेकिन नीति तो मालूम नहीं होती, क्या स्पष्ट है ? वे केटर कर देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि हर ब्लॉक में ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोली जावेगी लेकिन जहां ब्लाक ही नहीं खुले हैं और न ही बनेंगे तो, क्या वहां लोग बिना इलाज के ही मर जावेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ब्लॉक्स सब जगह बनेंगे।

प्रश्न संख्या ७९

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थिति—कृपया आगे देखिए)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

देवली तहसील की ग्राम पंचायत आवां के गलत वार्ड होने के बावजूद चुनाव

८०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही कि देवली तहसील, ज़िला टौंक की ग्राम पंचायत आवां के वार्ड गलत थे ?

(ख) अगर हां, तो क्या उस पंचायत का चुनाव गलत वार्ड होते हुए भी करवा दिया गया ? अगर नहीं, तो क्या सरकार को विदित है कि ग्राम गुलाबपुरा इस पंचायत में होते हुए भी वार्ड में नहीं लिये जाने के कारण अपने हक से वंचित रख दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि ग्राम गुलाबपुरा के निवासियों ने सरकार के पास अर्से से वार्ड में नहीं रखे जाने की प्रार्थना कर रखी थी ?

(घ) क्या यह सही है कि ग्राम डिकला और टोकरियावास वार्ड से पंच श्री बरधा पुत्र बकता चुनकर आ चुका है ? यदि हां, तो क्या शपथ ग्रहण करवा दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) गुलाबपुरा गांव इस पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इस ग्राम को वार्डों में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। केवल चुनाव के समय निर्वाचनाधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया था।

(घ) जी हां। इस पंचायत के वार्ड डिकला टोकरियावास से श्री बरधा पुत्र बकता निर्वाचित हुआ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया कि क्या जो मेम्बर चुनकर आया था, उसको शपथ ग्रहण करायी गई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शपथ ग्रहण करने के बारे में सूचना नहीं आयी है। हो तो गई, लेकिन किस तारीख को हुई इसकी सूचना नहीं आयी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शपथ ग्रहण ही नहीं कराई है। साल भर का अर्सा

(हंसी)

हो गया उसको चुनकर आये हुए। पंचायत में उसको सपथ ग्रहण नहीं कराई इसलिए जाने नहीं देते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां से ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। रूल्स के मुताबिक शपथ हो जानी चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चुने हुए पंच आये, उनके नाम यहां से गये, उसमें उसका नाम ही गायब था।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि चुनावों के बाद कितनी अवधि में शपथ ग्रहण कराना लाज़मी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स बने हुए हैं, निवाचन अधिकारी चुनाव के बाद ही शपथ दिलाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब शपथ दिला कर उसको पंच माना जावेगा या दुबारा चुनाव होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बारे में, शपथ नही दिलाई इस सम्बन्ध में, मैं कार्यवाही करूंगा।

श्रीजनार्दनराय नागर : शपथ दिलाने के बाद भी पंच को पंच नहीं माना जाता, शपथ दिलाने के बाद भी पंच को पंचायत का चार्ज नहीं दिलाया जाता क्या ऐसी शिकायतें सरकार के समक्ष आई हैं, और आई है तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न हों।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी शिकायतें आई है और हमने हिदायतें जारी कर दी हैं कि फौरन ही चार्ज दिला दिया जावे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गुलाबपुरा को उसमें शामिल नहीं किया तो फिर किस वार्ड में शामिल किया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले उसमें था

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसीलिए तो मैंने प्रश्न उठाया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी):

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या ऐसी पंचायतें हैं जहां शपथ पंच ने ले ली, लेकिन चार्ज नहीं दिलाया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां-जहां से मेरे पास शिकायत आई हैं उसके ऊपर मैंने खास तौर पर हिदायतें दे दीं है कि चार्ज दिला दिया जाय और कलेक्टर्स को भी इस सम्बन्ध में कह दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : कानोड़ में छः साल हो चुके हैं,चुनाव हो गया और सब कुछ हो गया लेकिन चार्ज नहीं दिया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो मेरे खयाल से मियाद ही निकल गई । मियाद तीन साल तक ही होती है ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण बात है । मैं गवर्नमेंन्ट से आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युशन्स में चुनावों के बाद शपथ शीघ्र से शीघ्र दिला देनी चाहिये, गवर्नमेन्ट को, मैं यह नहीं कहूंगा कि सुरक्षा करनी चाहिये, सम्मान करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं है तो यह एक चिन्ता का विषय है चुनाव होते ही शपथ दिला कर चार्ज दिलाना चाहिये, यह गवर्नमेंन्ट का जिम्मा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो चार्ज लेने गये उनके खिलाफ मुकदमा बना दिया गया ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे प्रश्न जबाब नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा उस पंचायत और वार्ड में था लेकिन आप कहते हैं कि नहीं था तो फिर गुलाबपुरा को किस वार्ड और पंचायत में रखा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस पंचायत में मौजूद है, वह उसी में है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब मौजूद है तो फिर चुनाव में क्यों नहीं भाग लेने दिया गया ? इसका कारण क्या है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अलग नहीं है । हमेशा से उसी पंचायत में है, पहले भी चुनाव हुए थे, पहले भी शामिल किया गया था और अब नहीं किया गया, उस गांव को बिलकुल ही भूल गये । यह गलती चीफ़ पंचायत ऑफिसर की है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका सवाल यह है कि देवली तहसील ज़िला टौंक की ग्राम पंचायत आवां के वार्ड गलत थे ? मैंने उत्तर दिया 'जी नहीं' । दूसरा आपने पूछा कि गुलाबपुरा के निवासियों ने सरकार के पास असें वार्ड में नहीं रखे जाने की प्रार्थना कर रखीथी। मैंने जबाब दिया कि शामिल नहीं किया गया ।

श्रीअध्यक्ष : अब मंत्री महोदय इसकी और जांच कर लेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ठीक है ।

ठा० मदनसिंह (दांता रामगढ़) : चूकि श्री भैरोंसिंहजी नहीं है और प्रश्न ८१ के बारे में हम जानना चाहते हैं ।

पुलिस हैड क्वार्टर में परेड ग्राउण्ड के निर्माण में अनियमितता

८१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री मदनसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(श्री भैरोंसिंह)

(१) क्या यह सही है कि पुलिस हेड क्वार्टर्स में एक परेड ग्राउन्ड तैयार कराया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्चा हुआ

(२) क्या यह सही है कि इसमें सामान ढोने के लिए पुलिस के सिपाहियों तथा लाइन के ट्रक्स को भी काम में लिया गया तथा झूंठे बिल (वाउचर) बना कर पेमेन्ट लिया गया ?

(३) इस परेड ग्राउन्ड का काम किन किन अधिकारियों द्वारा कराया गया ? इस सम्बन्ध का पेमेन्ट किस-किस अधिकारी ने किस-किस व्यक्ति को किस-किस कार्य के लिये किया ? कृपया इसकी एक तालिका विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां। एक परेड ग्राउन्ड पुलिस लाइन जयपुर में तैयार किया गया है परन्तु इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस कॉन्स्टिेबलों ने श्रमदान में किया है।

(१) पुलिस कॉन्स्टेबलों ने अवश्य काम किया है परन्तु मोटर गाड़ी काम में नहीं लाई गई और उस पर कोई खर्चा नहीं किया गया।

(३) यह कार्य पी. डब्ल्यू. डी के अधिकारियों की निगरानी में किया गया। इसमें किसी को भी किसी प्रकार का चुकारा इस विभाग से नहीं किया गया और इसलिये इसका हिसाब समर्पित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

ठा० मदनसिंह (दांता रामगढ़) :इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आयी है ?

श्री रामकिशोर व्यासः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

टौंक से उनियारा एवं सवाई माधोपुर से उनियारा तक सड़क की पुलियाओं का निर्माण

८१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या टौंक से उनियारा और सवाई माधोपुर से उनियारा तक सड़क की पुलियाओं का ठेका दिया जा चुका है ?

(२) अगर हां, तो किस को और इनमें कौन-कौन सी पुलियां तैयार हो चुकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि चन्दलाई, घास नयागांव, डिकोल्या वगैरह की सड़क और पुलियाएं बरसात में बन्द रहती है। अगर हां, तो इनका निर्माण कब तक होजावेगा ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) सवाई माधोपुर से उनियारा वाली सड़क पर मील ६ व ६ में पुलिया बनाने का ठेका दिया जा चुका है और टौंक से उनियारा वाली सड़क पर पुलिया बनाने का ठेका अब दिया जा रहा है।

(ख) सवाई माधोपुर से उनियारा वाली सड़क पर मील ६ में श्री श्यामजी एन्ड क. व मील ६ में श्री मनमोहनलाल को ठेका दिया गया है और कार्य ज़ारी है।

(ग) नहीं, केवल कुछ घंटों के लिये पानी अधिक आने के कारण क्योंकि चन्दलाई और

Page No.9

(श्री नाथूराम मिर्धा)

घास के नाले पर पक्के खुर्रे बने हुए हैं। नयागांव व डिकोल्या पर अब पुलिया बनने का कार्य ज़ारी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मिनिस्टर साहब उधर तशरीफ लाये नहीं। पक्के पुल नहीं बने, इस कारण चौमासे में पानी भरा रहता है क्या जिन पुलों के निर्माण के लिये ठेका दिया जा चुका है क्या वे चौमासे के पहले बन जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेका दे दिया है काम जिन पर चालू है वह चौमासे के पहले बन जायेंगे।

प्रश्न संख्या ८३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

टौंक डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के तालबों की मरम्मत

८४. रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५८-५९ में टौंक डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के तालाबों की मरम्मत के लिये बजट में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई तथा कितनी व्यय हुई ?

(२) तहसील उनियारा और देवली के तालाबों की मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(३) उपरोक्त तहसीलों में कितने तालाब अभी टूटे पड़े हैं ?

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई): (१) छोटे सिंचाई तालाबों की मरम्मत के लिये बजट में कुल जमा रकम स्वीकृत होती है उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट के बांधों के लिए आवश्यकतानुसार रकम का वितरण सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है सन् १९५८। ५९ में टौंक डिस्ट्रिक्ट के बांधोंकी मरम्मत के लिए १, ३४, ५७० रुपये मंजूर हुए हैं जिसमें से ३१ जनवरी १९५८ तक ९७६७६ रुपये व्यय हो चुके हैं।

(२) तहसील उनियारा व देवली के तालाबों की मरम्मत में क्रमशः ३,००० रु० व २१,००० रु० की धनराशि जनवरी १९५९ तक व्यय हुई है।

(३) : सिर्फ एक मोहम्मदगंज का तालाब टूटा हुआ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने सिर्फ एक ही तालाब के टूटने का बताया। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि तहसील उनियारा में कम से कम दो साल से चार तालाब टूटे हुए पड़े हैं, आपने एक कैसे बतलाया ?

श्री भीखाभाई : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। रुपया जो अलॉट किया हुआ है उसमें कुछ बाकी रकमें है अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो उनकी मरम्मत में रुपया खर्च कर दिया जायगा।

Page No.10

रावराजा श्री सरदारसिंह: आप यह बता सकते हैं कितने तालाब जो टूटे हुए थे उनकी मरम्मत में कितना रुपया लगा। इसके अलावा सिंचाई के ऐसे कितने तालाब हैं जो टूटे पड़े हैं ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास इसकी तालिका नहीं है। नहीं, लेकिन जिन तालाबों की मरम्मत हो गई है वे इस प्रकार है जैसे विजयगढ़ पाड़ा, चन्दलाई, नगर सागर, ये तालाब हैं जिनकी मरम्मत हो चुकी है।

प्रश्न संख्या ८५

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

पंचायत पीलीबंगा, तहसील सूरतगढ़ के सरपंच का अवैध चुनाव

८६. **डॉ० चन्द्रकला :** (किशनपोल बाजार, जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि पंचायत पीलीबंगा, तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर के सरपंच का चुनाव, चुनाव की मूल पत्रावली न होने पर भी कराया गया ?

(२) क्या उक्त पंचायत का चुनाव नियमानुकूल हुआ है ? यदि हां, तो चुनाव की मिसल सदन की मेज़ पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(३) क्या इस संबन्ध में चीफ़ पंचायत ऑफिसर द्वारा दिनांक ३. १०.५५. को दिया हुआ आदेश नियम विरुद्ध नहीं था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी नहीं।

(२) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(सूची अनुपलब्ध)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

डॉ० चन्द्रकला : मुझे सप्लीमेन्टरी करना है। क्या सरकार के पास पीलीबंगा पंचायत चुनाव की मिसल के नाम पर वही कागज़ है जिसकी प्रमाणित सूची मुझे मिली है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिटर्निंग ऑफिसर ने जो भेजी है, वही मिसल है।

डॉ० चन्द्रकला : मुझे जो सूची मिली है प्रामाणिक प्रतिलिपि की तौर पर, उसमें मतदाताओं की संख्या नहीं दी हुई है तो बिना मतदाताओं के चुनाव कैसे होगया ? मूल प्रति भी में मतदाताओं की सूची नहीं दी हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको जो कापी दी गई है वह हुबहु ओरीजिनल की कापी है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जो सूची मुझे मिली है उसमें मतदाताओं की कितनी संख्या है वह नहीं दी हुई है। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जो इसकी मूल पत्रावली है उसी के आधार पर पंचायत के चुनाव हुए हैं तो क्या उसमें मतदाताओं की संख्या नहीं दी हुई है।

श्री अध्यक्ष : यही मानना चाहिये।

डॉ चन्द्रकला : तो मेरा प्रश्न यह था कि पंचायतों के नियमानुसार बिना मतदाताओं की संख्या के चुनाव हो जाते हैं।

Page No.11

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव नियमानुसार हुए हैं, मतदाताओं की संख्या लिखी हुई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपको इस चुनाव के बारे में एतराज हो तो याचिका कर सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला: बिना मतदाताओं की संख्या के किस प्रकार चुनाव होगये ?.

श्री अध्यक्ष : चुनाव तो होगए अगर आपको किसी प्रकार की खामी नजर आय तो पीटिशन करने का कानून है, आप कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल: (नोखा) अब पिटीशन का क्या मतलब हैं ?

श्री अध्यक्ष : पीटिशन नहीं कर सकते तो इनका दायरा नहीं है कि ये उसका कुछ उत्तर दे सके। आप किसी प्रकार की ओपीनियन व्यस्त करे उसका कोई वक्त नहीं है।

बीकानेर जिले में सड़कों का निर्माण

८७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर ज़िले में सन् ५७.५८ में बनने वाली सड़कों में से अब तक कौन कौन-सी सड़कें बनी तथा किन सड़कों का काम अब तक पूरा नहीं हुआ और क्यों ?

(२) पोकरण से जैसलमेर की सड़क का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब तक समाप्त हो जाना था ? वह सड़क अब तक पूरी हुई या नहीं ?

(३) सन् ५८.५६ में बीकानेर जिले में कौन कौन सी नई सड़कें बनाने की योजना सरकार ने बनाई है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) सन् ५७.५८ में २ निम्न लिखित सड़कें पूरी होनी थीं जो पूरी बन चुकी हैं। १. सुजानदेसर सड़क से बाबा सालमनाथजी का बोरा। २. बीकानेर देहली सड़क से जाम्भाजी मन्दिर, गांव मुकाम। इसके अलावा बीकानेर लूणकरणसर की सड़क प्लान के अनुसार बनाई जा रही है, काम चालू है।

(२) मार्च १६५४ से शुरू हुआ और १६५८.५६ में समाप्त होगा। कार्य चालू है।

(३) कोई योजना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस लूणकरणसर वाली सड़क पर कितना कितना काम हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बीकानेर से लूणकरणसर पर जाने वाली सड़क हमने ५६.५७ में हाथ में ली थी। अब तक मेरे ख्याल से उस पर ६ मील का कार्य हो गया है, इसको ६०.६१ में पूरा करने का विचार है।

श्री मुरलीधर व्यास : कुल कितने मील का टुकड़ा है यह ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन यह ५६.५७ से कार्य शुरू हुआ है और ६०.६१ में हम खत्म कर देंगे।

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : अब तक यह कितने मील तक बन चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से ६ मील का। इसके अलावा आप उधर ज्यादा फिरते हैं, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : सन् ५८.५६ में कितने मील बननी थी और कितनी बन चुकी है? और केवल सन् ५६ में कितनी हो चुकी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तक जितना प्लान में प्रोविज़न है उसको हम बराबर खर्च करते जा रहे हैं और यह ६०.६१ के साल तक यह पूर्ण हो सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पूछना था कि इन सालों में कितना काम होना था, आपके प्लान के मुताबिक और कितना हुआ!

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् ५७.५८ में दो सड़कें बनानी थीं, दो पूरी कर दीं गई और तीसरी जो सड़क है, जिसको हमने ५६.५७ से लिया है और जिसको हम ६०.६१ तक खत्म करने का ख्याल रखते हैं।

श्री गिरधारी लाल : खैर यह बतला दीजिये, वह कितनी लम्बी सड़क है?

श्री नाथूराम मिर्धा : माईलेज़ मेरे पास नहीं लिखा हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : पोकरण से जैसलमैर सड़क का काम किस साल पूरा होना था?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी साल में पूरा होना था और इसी साल में कर देंगें।

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम का लागू होना

८८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम को अब तक लागू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा वह कब तक लागू हो जायगा?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम जिसमें राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक २४ जुलाई, सन् १६५८ को प्राप्त हो चुकी है, को अभी तक लागू नहीं किये जाने का यह कारण है कि इसके अन्तर्गत नियम व उपनियमों को दिनांक १५-१-५६ के राजस्थान राजपत्र में उन व्यक्तियों की सूचनार्थ हेतु प्रकाशित किये गये हैं जो इस कानून के अन्तर्गत प्रभावित होंगे। साथ ही उनसे आवश्यक आपत्तियां एवं संशोधन अगर कोई हों तो दिनांक २८-२-५६ से पहले पहले तक मागे गये हैं। निर्धारित समय के पूर्ण होने से पूर्व जो आपत्तियां एवं संशोधन आवेंगे उन पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा। नियमों व उपनियमों के लागू होने पर ही मूल एक्ट को कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिये एक्ट व रूल्स साथ ही लागू किये जावेंगे। आशा है कि यह कार्य दिनांक १-४-५६ तक पूर्ण हो जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उसको गजट में प्रकाशित करने में देरी क्यों हुई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिफ्रेन्ट स्टेजेज़

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पर देरी हुई है पहले ड्राफट बना उसको लॉ डिपार्टमेन्ट ने देखा उसके बाद गज़ट में पब्लिश हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्थान के कुछ स्थानों पर यह नियम लागू कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एक्ट तो कोई लागू नहीं हो सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : ब्यावर में मेरे खयाल से लागू है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह अजमेर का कानून है ।

जसरासर से सूड़सर तक सड़क

८६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील नोखा के गांव जसरासर से सूड़सर तक सड़क बनाने के लिये क्या स्थानीय पंचायतों व जनता की ओर से कोई आवेदन पत्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, विचाराधीन है ।

श्री गिरधारीलाल : इसका फैसला कब तक कर देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फैसला अभी थोड़ा होता है प्लान में पैसा है नहीं आप फैसला हुआ मानिये ।

श्री गिरधारीलाल : तो माननीय मंत्री महोदय के विचाराधीन क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचाराधीन अर्जी पड़ी है तीसरी प्लान में हम सोचेंगे ।

श्री गिरधारीलाल : वे अर्जियां किस किस तारीख की हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चीफ मिनिस्टर महोदय उधर दौरे में गये थे वहां की पंचायत के सरपंच ने एक अर्जी उनको दी थी वह हमारे दफ्तर में १८-६-५८ को आई है ।

श्री गिरधारीलाल : क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खत्म कर दी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो इसके शुरू करने तक का नाम नहीं है ।

प्रश्न संख्या ६०

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

बीकानेर टाउन हॉल का सार्वजनिक उपयोग

६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर टाउन हॉल का उ[illegible] किस कार्य के लिए किया जाता है । [illegible]

(२) क्या इसे सार्वजनिक[illegible] निमित्त विशेष अवसरों पर [illegible]

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाता है ? यदि हां, तो अब तक यह पिछले तीन वर्षों में किन-किन संस्थाओं को दिया गया तथा उससे सरकार को क्या आमदनी हुई ?

(३) क्या इसी प्रकार सामाजिक व राजनैतिक संस्थाओं को टाउन हॉल का उपयोग लेने पर कोई प्रतिबन्ध सरकार की ओर से है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) टाउन हॉल का उपयोग सांस्कृतिक कार्यों के लिये किया जाता है।

(२) जी हां। सूची संलग्न है।

(३) राजनैतिक कार्यों के लिए देने को निषिद्ध है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राजनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में सभा का आयोजन हो तो उपयोग नहीं किया जा सकता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि निषिद्ध है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कैसे आप ...ते हैं कि यह राजनैतिक सभा है ...या ...

...र्धा : मौके पर ज़ज कर ...क है या नहीं।

...र इस का ...रने देते?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई पार्टियां एक साथ लड़ पड़ती हैं। एक मांगता है तो दूसरा भी मांगता है। इसलिये मेरी राय में नहीं देना ही ठीक है। उनके लिये और बहुत सी जगहें हैं। कोई कमी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें झगड़े की क्या बात है ? तीन दिन पहले मांगते हैं पहले जिसको मिल जावे बाद में आने वाले को दूसरी जगह जाना पड़े तो इसमें क्या हानि है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपकी राय है। मेरी राय से मेल नहीं खाती। और बहुत सी जगहें हैं, वहां जाकर कर सकते हैं। इसलिये इसे अलग ही रक्खा जावे तो ठीक है। अब आपकी राय अलग है तो इसका क्या किया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : कारण तो समझ में आवे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कारण यही है, जो मैंने बताया बस।

जयपुर शहर की सफाई की योजना

६२. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर में कहां—कहां सीवेज़ लाइन डली हुई है ? क्या शहर के शेष हिस्सों में भी श्युरेज़ लाइन डालने की योजना है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायगी ?

(२) क्या बनी पार्क क्षेत्र के लिये स्थाई सफाई की कोई योजना है ? यदि हां,

(डॉ० चन्द्रकला)

तो क्या तथा वह योजना कब से शुरू होकर कब तक पूरी हो जायगी ?

(३) क्या शहर के विभिन्न भागों में जब तक स्थाई सफाई योजना लागू नहीं होती तब तक अस्थाई सफाई की कुछ व्यवस्था सोची जा रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जयपुर शहर में चौकड़ी तोपखाना देश, विश्वेश्वरजी, और घाट दरवाजा के रास्तों और गलियों में पहले से ही श्युरेज़ लाइन मौजूद है । चौकड़ी रामचन्द्रजी, गंगापोल और पुरानी बस्ती के कुछ प्रमुख रास्तों में सीवेज़ लाइन डाली गई है । चौकड़ी मोदीखाना में आधे से ज्यादा रास्तों व गलियों में श्युरेज लाइन डाली जा चुकी है । शहर की चार दीवारी में हरिजन बस्ती, चौकड़ी पुरानी बस्ती में रास्ता बालानन्द व चौकड़ी रामचन्द्र में घोड़ा-निकास में श्युरेज लाइन डालने की योजना है ।

(२) जी नहीं ।

(३) शहर के अन्य विभिन्न भागों में सफाई की कोई स्थाई योजना नहीं है । अभी सफाई विशेष हरिजन गैंग द्वारा कराई जा रही है ।

डॉक्टर चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि बिना श्युरेज लाइन के सफाई योजना और नगर के विकास में बाधा पड़ती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विकास तो शहर का हो रहा है उसके बिना भी ।

डॉ० चन्द्रकला : बनीपार्क और सी स्कीम में सेप्टिक टैंक कुछ अर्से में अन्डर ग्राउन्ड वाटर में स्पोइल हो जावेंगे, क्या आप यह महसूस नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : महसूस तो कर लीजिये ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : महसूस तो करना चाहिये पर फण्ड नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : इसका इलाज भी सोचते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगर विकास मण्डल अपना काम कर रहा है ।

डॉ० चन्द्रकला : पर आगे आने वालों के लिये क्या होने वाला है ?

श्री अध्यक्ष : यह बाद की बात है, यह जुदा बात है ।

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज, बीकानेर

६३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५७.५८ में बीकानेर एम्प्लॉय-मेन्ट एक्सचेन्ज में कुल कितने प्रार्थना पत्र आये तथा इनमें से कितने आदमियों को काम दिलाया गया ?

(२) इस विभाग में ऐसे कितने ना... दर्ज हैं जिनको गत ३ वर्षों से काम नहीं मि...

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद ...

(१) बीकानेर एम्प्लॉयमे...

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

विभाग में सन् १६५७.५८ अर्थात् अप्रेल सन् १६५७ से मार्च सन् १६५८ तक ४६०४ आदमियों के प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किये गये और उनमें से ५७६ को काम दिलाया गया।

(२) गत तीन वर्षों के रिकॉर्ड में एक व्यक्ति के अलावा ऐसा कोई नाम लाइव रजिस्ट्री में अंकित नहीं है जिसको अभी तक काम नहीं मिला हो।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो तीन साल से नाम लिखाने के बाद इन्तज़ार करता रहा पर नौकरी नहीं मिली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया न कि एक आदमी था। पर वह भी कई बार बुलाने के बावजूद नहीं आया। इसलिये रह गया।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर इस तरह तीन साल तक नौकरी न मिलने से ओवर एज़ हो जावे तो क्या उसको बाद में सरकारी सर्विस मिल सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओवर एज के बाद नहीं। इसका सम्बन्ध एम्प्लॉयमेन्ट ... नहीं है। ये तो विभाग के

... से

... कार के

... रेट हैं।

... र्फ इतना

है कि क्वालिफाइड आदमियों के नाम नोट करके विभाग को जरूरत होती है, तो सूचना दे देता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर ऐसी व्यवस्था न हो तो सरकार विचार करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो जी. ए. डी. से सम्बन्धित है।

शहर विकास कमेटी की सदस्यता

६४. **श्री मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर सिटी) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी में सदस्य किस आधार पर लिये जाते हैं ?

(२) बीकानेर शहर विकास कमेटी के लिये कलेक्टर ने किन-किन नामों की सिफारिश की थी ?

स्वायत्तशासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (१) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें कलेक्टर की सिफारिश के आधार पर सदस्य लिये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार को नियुक्त करने का अधिकार है। बिना किसी की सिफारिश के भी कर देती है।

श्री मुरलीधर व्यास : गत वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि कलेक्टर की सिफारिश के ऊपर आमतौर से नियुक्ति की जाती है। क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर अब सरकार ने सिफारिश मानना छोड़ दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : नाम प्रपोज़ तो किये जाते होंगे, क्या ऐसे नाम प्रपोज़ किये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो कमिश्नर साहब से डिसकस कर लिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपने किसी प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा था कि अक्सर उस क्षेत्र के एम० एल० ए० को उस कमेटी में लिया जाता है। इस तरह की बात आपके ज़रिये कही गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कहां सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी में। आम तौर पर ले लेते हैं पर जवाब में कहा हो ऐसा याद नहीं।

श्री अध्यक्ष : शायद, गलती से कह दिया हो।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान नहर पर काम की प्रगति

६५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान नहर के उद्घाटन के बाद से आज तक यह नहर कितनी खुद चुकी है ?

(२) इस नहर का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(३) क्या इस नहर से बीकानेर शहर को भी पानी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक मिल जावेगा ?

मंउपत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई): (१) खुदाई का कार्य अभी तक चल रहा है।

(२) राजस्थान नहर का कार्य दस वर्ष में पूरा होगा।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : सारी योजना तो बन चुकी होगी उसमें बीकानेर शहर तक भी पानी लाने की बात उस योजना के अन्तर्गत है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या राजस्थान कैनाल में नेवीगेशन की भी व्यवस्था है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसी को कन्सीडर कर रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बार, जयपुर) जब से काम शुरू किया तब से दस वर्ष में या अब से दस वर्ष में।

श्री रामकिशोर व्यास : जब से शुरू किया तब से।

प्रश्न संख्या ६६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

Page No.18

बीकानेर जिले में मर्डर केसेज की बढ़ोत्तरी

१७. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १६५५ से १६५८ तक बीकानेर ज़िले में कितने मर्डर केसेज़ किस किस स्थान पर किस किस वर्ष में हुए ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सूचना इस प्रकार है -

		१६५५	५६	५७	५८
बीकानेर सिटी	बीकानेर सिटी	२	—	१	२
महाजन	गेगरा कुम्भारा	१	—	—	—
नोखा		२	२	१	५
नापासर		६	—	—	१
गंगाशहर		१	—	—	—
गज़नेर		—	३	—	—

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, इसकी तालिका मिलनी चाहिए वरना याद नहीं रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही है।

देशनोक	—	—	१	३
लूणकरणसर	—	—	—	१
जामसर	—	—	—	—
बांसलपुर	—	—	—	२

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, तालिका मिलनी चाहिए क्योंकि सूची बहुत लम्बी है और साथ ही इसके अन्दर कुछ गलत आंकड़े भी हैं और जब तक मेरे पास सूची नहीं होगी तब तक मैं इस पर कोई सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : जो आपने सूचना मांगी थी, वह मैंने दे दी है।

श्री गिरधारीलाल : साथ ही मैंने तालिका भी तो मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न का उत्तर पढ़ दिया है।

श्री गिरधारीलाल : सूची बहुत लम्बी है, इसी कारण मैंने अपने प्रश्न में भी लिखा था सूची सदन की मेज पर रक्खें।

श्री अध्यक्ष : ऐसी लम्बी तालिका नहीं है। आपने १६५५ से ५८ तक के मर्डर केसेज़ मांगे हैं और उसकी सूचना देदी है।

श्री गिरधारीलाल : मगर बिना तालिका के सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) ये सारे केसेज़ कन्विक्ट हैं या चल रहे हैं, क्या बात है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका प्रश्न है कि मर्डर केसेज़ कितने हुए हैं, सन् ५५ से ५८ तक, जिसके बारे में मैंने सूचना दे दी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

Page No.19

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, इसका क्या निर्णय हुआ ? मैंने तालिका मांगी है और बिना तालिका मांगे मैं सप्लीमेन्टरी किस तरह पूछूं ?

श्री अध्यक्ष : निर्णय यही है कि मंत्री महोदय ने वह सूचना दे दी है जो आपने मांगी ।

श्री गिरधारीलाल : पर तालिका के बिना और सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल : मगर तालिका मैंने मांगी है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष :पर उसका विवरण आपको मिल गया है । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री गिरधीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने तालिका मांगी है, और वह नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न देने के बाद उसकी प्रतिलिपि लाईब्रेरी में रहती है, आप चाहें तो वहां से मिल सकती है ।

प्रश्न संख्या ६८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

समाचार पत्रों को मान्यता

६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा कुल कितने समाचार-पत्रों को इस समय मान्यता दी गई है ?

(२) उक्त पत्रों में से कितनों को सरकारी विज्ञापन सन् ५७–५८ में मिला है ? कृपया अलग-अलग पत्रों की रकम के विवरण की एक प्रति सदन की मेज पर रक्खें ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान के ८४ पत्र इस समय सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्य हैं ।

(२) सन् ५७–५८ में जिन-जिन पत्रों को विज्ञापन दिए गए, उनकी सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ठ ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो विज्ञापन दिये जाते हैं तो क्या इनका कोई आधार है । लोकवाणी के लिए १२ हज़ार और नवयुग के लिए २६ हज़ार का विज्ञापन दिया गया, राष्ट्रदूत के लिए १४ हज़ार का दिया गया तो यह जो विज्ञापन पत्रों को दिया जाता है इसका कोई आधार भी है कि किस आधार पर दिये जाते हैं या किसी को १० हज़ार का, किसी को २६ हज़ार का और किसी को १४ हज़ार का विज्ञापन दिया जाये । किसी को बहुत ज्यादा और किसी को बहुत कम, क्या आधार है आखिर ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में मैं तीन चार दफा सदन में निवेदन कर चुका हूं...

श्रीअध्यक्ष : फिर भी शंका रह जाती है ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में कोई रूल्स नहीं हैं और न ही इसके बारे

(श्री रामकिशोर व्यास

में किसी और दूसरी स्टेट्स ने रूल्स बनाये हैं। बाकी अब केन्द्रीय सरकार ऐसे रूल्स बना रही है और उनका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और जब वह रूल्स बन जायेंगे तो उसी आधार को हम मानेंगे। अभी तक यह डिस्क्रिशनरी है और यह अधिकार हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट के पास रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह ठीक समझती है कि जिस पत्र का ज्यादा सक्युलेशन है उन्हीं पत्रों को विज्ञापन दिया जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं ऐसी कोई बात नहीं है...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि नवयुग पर कुछ मर्जी ज्यादा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह जो सरकार से मान्य पत्र हैं तो यह बीकानेर जेल के अन्दर कैदियों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, वैसे वहां एक पेपर ही आता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर कोई अपने खर्चे से मंगाकर कोई व्यक्ति अखबार मंगाना चाहे तो ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जो जेल के रूल्स हैं उससे डिटरमिन होगा।

श्री भानसिंह (बयाना) : तो क्या आपके रूल्स से जेल के रूल्स अलग हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, जेल मैन्युअल अलग है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब सरकार से मान्य यह पत्र हैं तो क्या कारण है कि कैदियों को पत्र पढ़ने के लिए नहीं दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि यह एक अलग प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब मैं बीकानेर जेल में था तो मुझे पत्र पढ़ने के लिए नहीं दिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह प्रश्न अलग से पूछें कि किस-किस को अलॉउ किया जाना चाहिए और किस-किस को नहीं, मुझे खुद को आपकी इत्तला लेने की जरूरत है। एप्रुव का मतलब है कि एडवार्टाइज़मेन्ट के लिए एप्रुव हों।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पत्र मंगाये तो फिर क्यों नहीं दिया जाता है.?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जेल रूल्स अलग हैं। अगर आप दूसरा प्रश्न इस बारे में पूछें तो मैं उसका जबाब दे दूंगा।

श्री मदनसिंह : क्या पत्र पढ़ने के लिए भी कैदियों को पाबंदी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.21

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह जरूरी है कि जब तक भारत सरकार इस मामले में नियम नहीं बनाये तब तक राज्य सरकार इस बारे में नियम नहीं बना सकती ? क्या यह ऐसा विषय है कि जो भारत सरकार के निर्णय के अधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : न अधीन है और न जरूरी है, लेकिन मुनासिब है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): क्या जो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया, तो क्या यह माना जाये कि विज्ञापन उन्हीं को मिलता है जो कि कृपापात्र हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो वही मर्जी वाली बात हो गई।

प्रश्न संख्या १००–१०१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

काम दिलाऊ विभाग

७०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग): क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान सरकार ने काम दिलाऊ विभाग किस उद्देश्य से स्थापित किया था ?

(२) क्या उक्त विभाग उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हुआ है ?

(३) सम्बधित विभाग नौकरी चाहनेवाले के नामों की छांट किस आधार पर करता है और उनको किस क्रम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के पास भेजता है ?

(४) क्या उक्त विभाग के द्वारा नाम भेजने में विलम्ब करने, योग्य उम्मीदवारों को छोड़कर अयोग्यों के नाम पहले भेजने तथा पक्षपात करने और रिश्वत तक लेने की शिकायतें सरकार के समक्ष आई हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) काम दिलाऊ विभाग का स्थापन भारत सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने एवं नियोजकों को योग्य कर्मचारी दिलाने में सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। राजस्थान सरकार को इस संगठन का प्रशासन १–११–१६५६ को सौंपा गया था।

(२) जी हां, काफी हद तक।

(३) नियोजकों द्वारा सूचित की हुई शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, विशेष योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के आधार पर छांटा जाता है। सम योग्यतावाले उम्मीदवारों में से उनको जिनका रजिस्ट्रेशन पुराना होता है प्राथमिकता दी जाती है।

(४) जी, नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यदि एक ही क्वालिफिकेशन के और एक ही पोस्ट के लिए १० एप्लीकेशन्स में से दो तीन साल तक बराबर नाम रजिस्टर्ड हुआ है और हर तीन महिने में एक को नहीं लिया जाता है और दूसरे को दो-तीन महीने में ही ले लिया जाता है तो इसको क्या माना जाये ?

Page No.22

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यदि सूचना आपको दी जायं तो आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जांच करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों की जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

आयुर्वेदिक औषधियों का बजट

७२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधियों का पिछले तीन वर्षों में कितना बजट रहा ?

(२) राजस्थान के प्रत्येक डिवीज़न में औषधालयों की इन तीन वर्षों में क्या संख्या रही ?

(३) क्या प्रत्येक डिवीज़न को उसी अनुपात से औषधियों के लिए रकम निर्धारित की गई है, जिस प्रकार कि उनमें औषधालयों तथा रोगियों की संख्या रही है ?

(४) यदि हां, तो क्या भरतपुर डिवीज़न में भी औषधालयों और रोगियों की संख्या के अनुपात से ही औषधियों की रकम दी गई है !

(५) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधियों का पिछले तीक वर्षों में जो बजट रहा है उसकी तालिका निम्न लिखित है :

वर्ष १९५६–५७	२,१५,३०० रु०
वर्ष १९५७–५८	३,२०,००० रु०
वर्ष १९५८–५९	४,३३,४०० रु०

(२) राजस्थान में प्रत्येक डिवीज़न में औषधालयों की जो इन तीन वर्षों में संख्या रही उसकी तालिका निम्नलिखित है :

क.सं.	डिवीज़न	वर्ष १९५६-५७	५७-५८	५८-५९
१.	अजमेर:जयपुर	१८८	२१०	२१७
२.	कोटा	६२	६५	६८
३.	उदयपुर	१४८	१५४	१६०
४.	जोधपुर	१२३	१३०	१३७
५.	बीकानेर	५७	६१	६४

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जहां पर रोगियों की संख्या ज्यादा है और औषधालयों की संख्या ज्यादा है वहां पर औषधी कम मिली है और जहां पर रोगियों की संख्या कम है वहा पर औषधी ज्यादा मिली है, यह क्या बात है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप यह सूचना दे रहे हैं। आप कोई डेफीनेट सूचना देंगे तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर,

(अनुपस्थित)

श्री किसनाराम।

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध शिकायत

७६. श्री किसनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ म्यूनिसिपल बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन श्री मोहनलाल के खिलाफ बहुत शिकायतें आई थीं ?

(ख) अगर हां, तो उनमें से कितनी शिकायतें ऐसी हैं जिनकी अब तक कोई जांच नहीं की गई है ?

(ग) क्या दक्षिणी दरवाज़ा (साउथगेट) के तोड़ने के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायत चेयरमैन के खिलाफ एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में की गई थी ? अगर हां, तो अब तक उसकी जांच क्यों नहीं की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) श्री मोहनलाल सारस्वत को अध्यक्ष पद से हटाये जाने के बाद प्राप्त शिकायतों की कोई जांच नहीं कराई गई ।

(ग) जी हां । इसकी सूचना एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट से प्राप्त हो सकती है ।

श्री किसनाराम : तीसरा क्या बतलाया आपने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टी—करप्शन डिपार्टमेन्ट में शिकायत की है । वहां क्या कार्यवाही हो रही है वह वही विभाग सूचना दे सकता है । इस विभाग को सूचना नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें थीं । उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप के अर्से में करप्शन किया है तो उसकी जांच होकर उन पर केस दायर किये हैं या नहीं विभाग ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस बिना पर हटाये गये हैं वह थी यह कि उन्होंने एक डुप्लीकेट बिल बनाया था, लेकिन रुपये ड्रा नहीं किये थे । उस बिना पर उनको हटाया गया है । वह केस भी हाई कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स में जाना नहीं चाहूंगा । यहां पर जो प्रश्न किया गया है कि दरवाजे के बारे में एन्टी-करप्शन में शिकायत की गई है उसके बारे में मैं नहीं बतला सकता हूं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उन्हें हटाया गया है या उन्होंने त्यागपत्र दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : त्यागपत्र दिया था, लेकिन उन्हें हटाया गया है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या दरवाजे तोड़ने की रिपोर्ट आपके विभाग में नहीं आई अपने रिश्तेदारों को देने के बारे में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास बहुत सी शिकायतें आई थीं । उनकी जांच करवाने के बाद जो २, बातें साबित हुई हैं, उनके बारे में कार्यवाही की गई है । लेकिन सवाल में यह कहा गया है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में यह शिकायत की गई है तो वहां से पूछा जाय । मेरे यहां कोई जानकारी नहीं है ।

Page No.24

श्री श्रीभानसिंह : जो शिकायतें आज तक आई हैं एन्क्वायरी के बाद में केस दर्ज किया गया है कहीं और पुलिस को सौंप दिया गया है या क्या किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास में एन्टी-करप्शन में भेजने के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को हमारे विभाग से कोई नहीं भेजी गई।

डॉ० चन्द्रकला : क्या वे शिकायतें गलत थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मिसकन्डक्ट की शिकायतों में हरेक में नहीं होता है कि वे करप्शन की हों। डुप्लीकेट बिल बनाया था वह मिसकन्डक्ट में आता है। और शिकायतें एन्टी करप्शन में चल रही हों उसका मुझे मालूम नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : हर एक कोई चोरी करके त्यागपत्र दे सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : त्यागपत्र नहीं दिया। उनको हटा दिया गया है।

श्री किसनाराम : उनके खिलाफ सैंकड़ों शिकायतें हैं, उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको हटा दिया, फिर जांच का सवाल कैसे पैदा होगा।

श्री श्रीभानसिंह : Is it a sufficient ground that the Chairman has been removed from the office and that he has been exhonerated by the Govern ment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज़ किया कि कोई आफेन्स बनता है तो it will go to the Anti Curuption Deptt. कोई जुर्म नहीं बनता है तो नहीं भेजेंगे। सो ऐसा कोई केस नहीं है। अगर आवश्यक हुआ तो अब भी भेजने को तैयार हैं That has not come to my notice.

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के चौधरी।

(अनुपस्थित)

रतनगढ़ निवासी सीताराम व अगरी बेवा की मोहनलाल सारस्वत के खिलाफ रतनगढ़ थाने में रिपोर्ट

७९. **श्री किसनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्बा रतनगढ़ के निवासी सीताराम पुत्र चेताराम ब्राह्मण व अगरी बेवा चेताराम शर्मा वगैरह की तरफ से पुलिस थाना रतनगढ़ में मोहनलाल सारस्वत के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी ?

(ख) क्या इस किस्म की रिपोर्ट सरकार के पास भी आई थी ?

(ग) अगर हां, तो पुलिस ने व सरकार ने उसके विषय में अब तक क्या कार्यवाही की।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी नहीं, उनमें से किसी ने भी थाने में रिपोर्ट अंकित नहीं कराई, सीताराम पुत्र चेतराम ब्राह्मण ने एस. पी. चुरू को मोहनलाल ब्राह्मण के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके फलस्वरूप थाना चुरू में दफा ४४०।३९७ आई. पी. सी. के अन्तर्गत एक प्रकरण अंकित किया गया है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ख) सरकार के पास इस किस्म की रिपोर्ट नहीं आई।

(ग) प्रकरण का अनुसंधान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महदोय, इसका जवाब मिलना चाहिए, प्रश्न संख्या ८३ का।

प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर (जयपुर) के भवन निर्माण में सरकार द्वारा सहायता

८३. श्री भैरोंसिंह (डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर दने की कृपा करेंगे :

(१) प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर के भवन निर्माण में सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई थी और ग्रान्ट–इन–एड के रूप में कितनी सहायता माहवारी या वार्षिक दी जाती है ?

(२) इस चिकित्सालय की मैनेजिंग कमेटी (संचालक मंडल) के कौन–कौन सदस्य हैं ?

(३) इस चिकित्सालय में चिकित्सक कौन–कौन हैं तथा प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में उनकी क्या योग्यताएं हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर (जयपुर) के भवन निर्माण में सरकार द्वारा अब तक ३५,००० रु० की सहायता दी गई है तथा ग्रान्ट–इन–एड के रूप में गत वर्ष ४५० रुपये माहवार की दर से ५४०० रु० वार्षिक दिये गये थे। इस वर्ष की ग्रान्ट–इन–एड विचाराधीन है।

(२) इस चिकित्सा की मैनेजिंग कमेटी (संचालक मंडल) में ११ आदमी हैं।

(३) इस चिकित्सालय में निम्न दो चिकित्सक हैं :

(१) डा० श्री सुखरामदास, आयुर्वेदाचार्य, ए. एम. एस. एस. तथा १५ वर्ष का प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव है।

(२) डॉ० श्री किशनलाल, हायरक्रेथेरेपी व २० वर्ष का चिकित्सानुभव।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

११.५५ म० पूर्व

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अमृतलाल पायक ने दिनांक २०.२.५६ से दिनांक १५.३.५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

११.५६ म० पूर्व

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतरवाद विवाद

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव था, उसका मैं विरोध करता हूँ और उसका कारण अध्यक्ष महोदय, यह है कि राजस्थान की जनता और विधान सभा के सदस्य यही आशा कर रहे थे कि राज्यपाल महोदय कम से कम अपने अन्तिम भाषण के बाद में इस सरकार को यह राय देते कि जो कि यह मौजूदा सरकार है जिससे कि राजस्थान की प्रत्येक जनता दुखी है वह स्तीफा दे और कम से कम नई सरकार बने। ऐसा भाषण में होता तो मैं उस धन्यवाद का समर्थन करता। उसका कारण, अध्यक्ष महोदय, आज सभी जानते हैं। राजस्थान के अन्दर इतने-इतने आन्दोलन हुए और जो जनता के खिलाफ राज्य सरकार ने बर्ताव किया, उससे आज जनता परिचित है। किसान वर्ग के साथ साथ क्या क्या कानून हुए? किसानों के खिलाफ कितने-कितने कानून इस सदन में सरकार की तरफ से और जो नीचे के राज्य कर्मचारी हैं उनके साथ में क्या-क्या अन्याय हुआ, टैक्सेज़ कितने लगे और नाज़ की इस सरकार के राज्य के अन्दर क्या समस्या हुई है इन सबको देखते हुए बजाय सरकार की तारीफ के कम से कम राज्यपाल महोदय को स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिए था कि अच्छी सरकार बनाकर राजस्थान को हम देंगे कि वह राज्य चलाये।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने शुरुआत में पुलिस के सम्बन्ध में फरमाया कि पुलिस ने बड़े-बड़े डाकुओं को मारा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बड़े-बड़े खतरनाक डाकुओं को पुलिस ने मारा, और पुलिस का कर्तव्य है कि वह डाकुओं को मारे। वह केवल पुलिस का ही काम है जिसके लिए सरकार की इतनी तारीफ हो कि आप अपने अभिभाषण में कहें। पुलिस के डाकुओं के मारने के काम से ही सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मैं यह समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि डाकू कम से कम बड़े पूंजीपतियों का नुकसान करता है लेकिन गरीबों को डाकुओं से क्या शिकायत थी? आज पुलिस गरीबों के लिए बड़ी चीज़ करती तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम हुआ है। राजस्थान के अन्दर वही की वही चोरियां हो रही हैं। मर्डर के केसेज़ वही के वही हो रहे हैं, जिसमें कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय पुलिस के सम्बन्ध में और विचार रखते और जो सही स्थिति है उसके अन्दर कुछ नहीं फरमाया है।

दूसरा, राज्यपाल महोदय के भाषण में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनके सम्बन्ध में

Page No.27

(श्री मदनसिंह)

सुनना चाहते थे वह एक बात भी नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण में फोरेस्ट के सम्बन्ध में बातचीत नहीं है, राज्यपाल महोदय के भाषण में करप्शन के सम्बन्ध में बातचीत नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वह भाषण अधूरा रहा था। इसलिए मैं विरोध करता हूँ कि उन्हें धन्यवाद नही देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है कि यहां पर हाई कोर्ट आन्दोलन एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ है। उसके सम्बन्ध में जनता सुनना चाहती थी कि राज्यपाल महोदय के क्या विचार हैं, और राज्यपाल महोदय के पास हाईकोर्ट के सम्बन्ध में डेपुटेशन गया था बड़े-बड़े एडवोकेट्स का, पढ़े लिखे लोगों का उसके सम्बन्ध में आज तक नहीं मालूम पड़ा कि राज्यपाल महोदय के क्या विचार थे, और आन्दोलन के सम्बन्ध में जो जनता के ऊपर अत्याचार हुए वह सबको मालूम हैं। उस सम्बन्ध में हम सुनना चाहते थे कि राज्यपाल महोदय अपने कुछ विचार रखें। केवल यह कह देना कि डाकू कल्याण-सिंह को मार दिया इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम कर लिया। मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि केवल १० आदमी मुझे दे दो आप तो सारे राजस्थान के लिए वह १० आदमी काफी हैं और एक डाकू को नहीं रहने देंगे। इसलिये केवल 'डाकू' शब्द लाकर ही गवर्नमेंट ने बड़ी चीज़ कर ली हो, ऐसा नहीं है। मैं सही कहता हूँ कि यदि राजस्थान गवर्नमेन्ट का कुछ भी दिमाग होता तो बाहर के आई० जी० पी० को यहां लाकर नहीं बैठाते और अगर यहीं के आई. जी. पी. रखते तो एक भी डाकू जीवित नहीं रहता। बाद में उनके दिमाग में यह बात आई तब यहाँ के आदमी को आई० जी० पी० रखा। बाहर से आनेवाले आई० जी० पी० हमारे इलाके से वाकिफ नहीं, यहां के इलाके के आदमियों से वाकिफ नहीं, प्रान्त से वाकिफ नहीं इसलिये जब तक हमारे यहां बाहर के आई० जी० पी० रहे तब तक ठीक प्रबन्ध नहीं कर सके। और आज आई० जी० पी० राजस्थान के ही रहने वाले हैं और वे यहां के इलाके में काम करना जानते हैं, यहां के लोगों को समझते हैं इसलिये उनके आते ही डाकुओं का सफाया हो गया। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह धन्यवाद आई० जी० पी० को मिलना चाहिये सरकार को नहीं क्योंकि यह सरकार तो बाहर के आई० जी० पी० को लाकर रखती...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : इन आई० जी० पी० को भी तो सरकार ने ही नियुक्त किया है ?

श्री मदनसिंह : (जारी) बाद में किया है। जब उन्होंने यह महसूस किया कि बाहर के आई० जी० पी० को रखना गलती थी तब किया। इसलिये मैं चाहता था कि राज्यपाल सही बात बताते।

दूसरी डेवलपमेन्ट के बारे में बातचीत हुई। इसमें दो राय नही हो सकती कि डेवलपमेन्ट देश की भलाई के लिये है, राजस्थान की उन्नति के लिये है। लेकिन कई काम डेवलपमेंट के हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो रुपया डेवलपमेंट में खर्च हुआ वह सही रूप से नहीं हुआ और जिनके पास रुपया पहुँचना था उनके पास नहीं पहुँचा। यदि इस चीज़ की जांच हो तो पता चलेगा कि उन लोगों के पास नहीं पहुँचा जिनके

(श्री मदनसिंह)

पास पहुँचना चाहिये था। जिस चीज़ के लिये रुपये लिये गये उसके लिये खर्च न होकर दूसरे काम में हुए। मैं अभी भीलवाड़ा गया था वहां मुझे मालूम हुआ कि रबी अभियान में जिस अनाज का वितरण हुआ वह अनाज बीज के काम में नहीं लिया जाकर बाजार में बेचा गया और अच्छे-अच्छे लोगों ने बीज के नाम से अन्न लेकर बाजार में में बेचा। मैं यह मानता हूँ कि डवेलपमेंट से तरक्की हो सकती है लेकिन कब? जब कि सरकार पक्षपात न करे। हमारे कमिश्नर साहब बहुत मेहनत करके जिस तरह से माँ अपने इकलौते बच्चे को पालती है उसी तरह से ये भी पालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बहुत ज्यादा पक्षपात करके हस्तक्षेप करती है इस कारण से सारा काम ठप्प हो रहा है और जो समय-समय पर पैसा पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुँचता है। सरकार के कानों तक कमिश्नर साहब ने बात पहुँचाई होगी। कि डवेलपमेन्ट के कार्यों शिथिलता ए० जी० के कारण से आती है। सरकार से रकम की सैंक्शन हो जाती है, तकाबी आदि देने का आखिरी फैसला भी हो जाता है तब भी ए० जी० के ऑफिस में रकम रोक दी जाती है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह कहा कि रबी अभियान में मदद पहुँचाने में कामयाबी हांसिल की, लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह गलत है। अब तक तकाबी की रकम जिनके पास पहुंचनी चाहिये उनके पास नहीं पहुँची है। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई थी जिसके कारण रबी अभियान सफल हुआ। अन्यथा सरकार के काम से सफलता मिली हो, यह बात नहीं है। सरकार का रवैया यह रहा है कि जब वर्षा अच्छी नहीं होती है तब तो यह कह देते हैं कि परमात्मा की मर्ज़ी ऐसी ही थी इसलिये ऐसा हुआ और यदि कभी वर्षा अच्छी होती है तो कहते हैं कि रबी अभियान सफल हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काश्तकारों के पास पैसा नहीं पहुँचा और रकम लैप्स हो रही है। रबी अभियान में जो मेड़ बन्धी हुई है उसमें सफलता मिली है, उसके लिये मैं भी कह सकता हूं। अन्यथा डवेलपमेन्ट के काम में पक्षपात हो रहा है। अभी मैं डेगाना गया था वहां मुझे मालूम हुआ कि यहां से जो मिनिस्टर और नेता लोग जाते हैं वे यह कहते है कि विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उनकी दर्ख्वास्त पहुँचे, तो रोक दो। डेगाना और भीलवाड़ा तहसील में दो तीन वर्षों से लोगों की दर्ख्वास्तें पड़ी हैं, वे लोग विरोधी दल के पंच हैं या काम करते हैं इसलिये उनको तकाबी आदि सहायता नहीं मिलती है। इस तरह का पक्षपात जिस सरकार में हो वहां राज्यपाल के भाषण में यह कहा जाय कि डवेलपमेन्ट का काम बढ़ गया है, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में स्कूलों की भी चर्चा आई, स्कूलों में बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि बच्चे स्कूलों में और भी भर्ती किये जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा पर जितना खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से शिक्षा बढ़ रही है क्या? मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो शिक्षा शहर में है, वह गांवों में नहीं है। जो शिक्षा पूंजीपतियों के लड़कों को और बड़े आदमियों के लड़कों को शहरों में मिलती है वह शिक्षा गरीबों के लड़कों को गांवों में नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि गांवों में जितने मास्टर नियुक्त होते हैं ये इस ढंग के होते हैं

(श्री मदनसिंह)

कि उनको खुद को कुछ ज्ञान नहीं होता, वे खुद शिक्षित नहीं होते। अनपढ़ मास्टर अनपढ़ों को पढ़ाने के लिये जाते हैं। उनको यह भी तमीज़ नहीं होती कि गरारा कैसे पहनते है। गरारे की एक बांह ऊपर जाती हैं तो दूसरी नीचे जाती है, एक जूते में लैस लगी है तो दूसरे की गायब है। इस तरह के मास्टरों का हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप चाहे हज़ारों स्कूलें खोल दें लेकिन जब तक वहां पर ऊंचे दर्जे के मास्टर नहीं पहुँचेंगे तब तक गांवों में शिक्षा नहीं फैलेंगी। जो मेट्रिक्युलेट मास्टर वहां जाते हैं वे वहां रहना पसन्द नहीं करते क्योंकि उनको वहां सुविधा नहीं रहती और गांवों के जो लोग नौकरी करने जाते हैं उनको सर्विस इसलिये नहीं मिलती है कि उनकी बातचीत का ढंग, कपड़े पहनने का ढ़ंग गांवों में रहने वाले लोगों जैसा होता है। इसलिये मैं कहूंगा कि शिक्षा के लिये यह सिद्धान्त होना चाहिये कि अच्छे-अच्छे मास्टर या प्रोफेसर गांवों में जाने चाहिये और वहां जाने चाहिये जहां के लोग अनपढ़ हों। विदेशों में यह देखा गया है कि जंगली लोगों को शिक्षा देने के लिये जो मास्टर और प्रोफेसर जाते हैं वे बड़े अच्छे और योग्य व्यक्ति होते हैं, लायक होते हैं और दुनिया देखे हुए होते है, ऐसे लोग जंगल में जाकर जंगली लोगों को शिक्षा देते हैं।

(१२·८ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यही कारण है कि यहां पर भी मिशिनरीज़ की शिक्षा को क्यों पसन्द करते हैं गांवों में जो लोग जाते हैं उनको ज्यादा तमीज़ होनी चाहिये। लेकिन आज कल तो मास्टर केवल नाम के ही होते हैं। ऐसी हालत में यह कहना कत्तई ठीक नहीं है कि गरीबों को शिक्षित बनाने के लिये हमने इतना रुपया खर्च किया और अनिवार्य शिक्षा रखी। आज कल जो शिक्षा दी जा रही है उससे तो जो अनपढ़ लोग खेतों में काम करें वही अच्छा है। जो पैसा खर्च होता है वह फिजूल ही होता है। जो बिल्डिंग बनाते हैं वह भी पूरी नहीं होती है। मेरे इलाके में बानूड गांव है, वहां की पब्लिक ने १२-१३ हज़ार रुपया लगाकर स्कूल के लिये बिल्डिंग बनाई, गवर्नमेन्ट ने यह वादा किया था कि हम आधी रकम देंगे। जहां गवर्नमेन्ट को १२ हज़ार रुपये खर्च करने थे यहां आठ वर्षों में १५०० रुपये ही खर्च किये हैं। इसलिये विश्वास नहीं होता कि गवर्नमेन्ट काम पूरा करेगी। इसलिये एम० एल० एज़ को शपथ लेनी चाहिये कि अपने लड़कों को वे अपने अपने इलाके में ही पढ़ावें और मिनिस्टरों को तय करना चाहिये कि हमारे लड़के सेन्ट जेवियर में ही पढ़ने जावें और जिनके वोटों पर हम आये हैं उनके लड़के ऐसे मास्टरों से पढ़ें जो तीन दिन तक मुंह नहीं धोते हैं और तीन तीन दिन तक आंखों में जिनके गीज़ रहती है। वे क्या गांवों में अनपढ़ों को शिक्षा देंगे। जो गवर्नमेंट के रुपयों का दुरुपयोग इस तरह से करते हैं वे सबसे बड़े डाकू हैं आज दुनिया को यह बताया जाता है कि राजस्थान सरकार ५ करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च करती है। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि ये रुपये कहां खर्च होते हैं जो अच्छे-अच्छे लड़के बाहर जाते हैं वे शहरों के लड़के जाते हैं और गांवों के लड़के वहीं रह जाते है क्योंकि बड़े-बड़े

Page No.30

(श्री मदनसिंह)

नेताओं के भाषण होते हैं अच्छे-अच्छे लड़के गांव-गांव में रहने चाहिये। आपके और हमारे लड़के अमेरिका और विलायत जायें, इंजीनियर बनें और जो किसानों के लड़के हैं उनको यह कहदें कि तुम्हारी पतलून अच्छी नहीं है। मैं स्वयं एक लड़के को ले गया था उसको कहा गया कि तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का तरीका ठीक नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें उनका कसूर क्या है जब कि आप मास्टर ही ऐसे भेजते हैं। जो अच्छे और अनुभवी मास्टर हैं उनको गांवों में भेजना चाहिये और नयां को शहरों में रखना चाहिये ताकि गांव वालों की शिक्षा ज्यादा ठीक हो सकें। और जो अनुभवी व्यक्ति हैं वे ही गांवों में जायं। चिकित्सा के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने नहीं बताया। यही हाल गांवों में डाक्टर्स का है। आज भी उसी चूर्ण की गोली पर गांवों के लोग जिन्दा हैं। वैद्य जी की चूर्ण की गोली मिल गई, इसी पर संतोष करते हैं। अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स शहरों के लिये पूंजीपतियों के लिये हैं और जिन लोगों के आधार पर यह सरकार बनी है, उस सरकार को चाहिये कि गांवों में अच्छे डॉक्टर्स भेजे। कुछ नहीं तो कम से कम वर्ष दो वर्ष में एक बार तो अच्छे डॉक्टर्स को गांवों में भेंजे ताकि गांवों में घूम कर वहां के लोगों को समझ सकें।

मैंने यह भी देखा है कि गांवों के बेचारे लोग कहीं से गिर जाते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है तो वे शहरों में पहुंच नहीं सकते और चिकित्सा के अभाव में उम्र भर अपंग बने रहते हैं। यदि ये हॉस्पिटल्स गांवों में एस्टेब्लिश हो जायं, तो शहरों वालों के पास तो साधन हैं कि वे अपने बच्चों को वहां ले जाकर इलाज करायें।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज यदि कोई यह समझे कि शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है, चिकित्सा का अच्छा प्रबन्ध है, मेडिकल एड अच्छी मिल रही है तो यह सत्य नहीं है। मुझे आशा थी कि राज्यपाल महोदय जगह-जगह गांवों में घूमें हैं और वहां के लोगों की दिक्कतें उनको मालूम हैं और उन बातों का अपने भाषण में जिक्र करेंगे पर उन्होंने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र नहीं किया।

पंचायतों के लिये कहा गया कि बहुत पॉवर मिलने वाली है। इससे मुझे कोई नाराजगी नहीं पर आज मैं ऐसी चीज़ सदन के सामने रखना चाहता हूं कि शायद हिन्दुस्तान की क्या, दुनियां की किसी पंचायत में इस तरह की घटना नहीं हुई होगी, व किसी पंचायत के सरपंच ने ऐसा फैसला आज तक नहीं दिया होगा। डेगाना पंचायत के अन्दर तामडोल के सरपंच ने फैसला दिया है, उस फैसले को सुनकर आप आश्चर्य करेंगे कि एक आदमी पर जुर्माना किया है ५५० रुपये का इस कुसूर पर कि उसने जादू किया।

श्री उपाध्यक्ष : वह फैसला कहां है ?

श्री मदनसिंह : यह रहा।

श्री उपाध्यक्ष : कॉपी है।

श्री मदनसिंह : ट्रयू कापी है मय मोहर के।

(श्री मदनसिंह)

ऐसा फैसला सरपंच ने किया कि तुमने एक आदमी पर जादू टोना किया है इसलिये ५५० रुपया का जुर्माना किया जाता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं है। 'यह है' तुमने बस्ता रेगर पर जादू और मूठ किया है इसलिये तुम पर ५५० रुपया जुर्माना किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की टेबिल पर रखियेगा।

श्री मदनसिंह : जरूर रखूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अपील तो नहीं है।

श्री मदनसिंह : जो होगा रख दिया जायगा, उसकी जाँच हो जायगी। ऐसी पंचायतें जहां जादू टोने पर ५५० रुपया जुर्माना होता है। यदिऐसा पंचायती राज्य बनेगा तो जो कुछ दुर्दशा बस राजस्थान की होनी है, वह निश्चित रूप से होगी। पर सरकार की पॉलिसी है और राज्यपाल महोदय फरमा चुके हैं, जो कुछ होगा। यह मैंने एक नमूना पेश किया है, किसी राष्ट्र में इस प्रकार का जुर्माना नहीं हुआ होगा। डेगाना वह एरिया है जहां अच्छे-अच्छे नेता हैं, जिन्होंने राजस्थान की बागडोर सम्हाली है, उसी डेगाना के एरिया में एक पंचायत का सरपंच ऐसा फैसला करे कि जादू टोने के नाम पर ५५० रुपये का जुर्माना किया जाता है, यह एक नमूना मैंने पेश किया है।

फोरेस्ट डिपार्टमेंट पर राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा है, यह भी भाषण में एक कमी थी। फोरेस्ट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कम से कम फोरेस्ट के बारे में भी कुछ बातें फरमानी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जागीरों सम्बन्धी विचार भी रखे और उन विचारों में हमारे माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक अवार्ड दी है, उसके बारे में बात कही, राज्यपाल महोदय ने बताया कि जागीरों की समस्या हल हो गई है पर मैं सदन को और राज्यपाल महोदय को बताना चाहता हूं कि जागीरों की समस्या हल नहीं हुई है, कारण यह है कि जो सीधा तरीका होना चाहिये विश्वास दिलाने का और कार्य करने का वह हमारी सरकार का नहीं रहा है। सौराष्ट्र में जागीरें खत्म हुई और सीधे ढ़ंग से खत्म हुई पर हमारे यहां सरकार वादा करती है और कानून ऐसा बनाती है कि उस वादे की पूर्ति में उससे बाधा आती है। अभी जब मैंने सुना है कि जागीरदारों को २२ गुना मुआवज़ा मिलेगा, साथ ही साथ हमारी सरकार ने क्या किया है कि सैटलमेंट रेट्स ८ गुना घटा दी है, जिससे १४ गुना मुआवज़ा मिला है।

मैं तो यही कहता हूं कि अगर जागीरों के खत्म होने से सबसे ज्यादा आनन्द किसी को आया है, सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला है तो वह बनियों को मिला है। उन्होंने डिग्रियां बना बना कर सब किश्तों का जागीरदारों का पैसा ले लिया है। ऐसी सूरत में यह कहना कि जागीरदारों की समस्या का हल हो चुका है, यह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब जागीरदार अपने केस को ले गये थे तो स्टे नहीं मिला था और स्टे नहीं मिलने के कारण एक विचार रखा था कि अगर जागीरदार नहीं जीते तो.....

Page No.32

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ?

श्री मदनसिंह : यह फैसला हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष : फैसले की नकल है ?

ठा. श्री मदनसिंह : फैसले की नकल भी है और किसी का विरोध भी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : फैसला यदि हुआ है तो दूसरे सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये कि कैसा फैसला है और वे आपत्ति उठा सकें । यदि फैसला आपके पास हो तो उसका रेफेरेंस दें ।

श्री मदनसिंह : इस समय तो नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : तो इसका रेफेरेंस नहीं दिया जायगा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मुझे आपत्ति है, जैसे आपने रूलिंग दी वैसे उसको मानने को तैयार हूं पर जो कोई चीज़ मेम्बर के पज़ेशन में नहीं हो, तो क्या उसका कोई जिक्र ही सदन में नहीं कर सकते । It is upto the Hon. Members to look into that and criticise, but I have my right to say things in the House whether the document is in my possession or not.

श्री उपाध्यक्ष : I quite agree. But has he given some reference about the citation itself, the number of the case, when it was decided, and the nature of the case etc.

श्री श्रीभानसिंह : I am not saying in this particular case, Sir, but the Hon. Member has right.........

श्री उपाध्यक्ष : I have taken that into consideration. If there is a specific reference about the citation, I will not take any objection.

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इसका फैसला भी हो चुका है । कानून भी बन चुका है, जागीर कानून में वह चीज़ है । सरकार किस तरह से ले रही है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी आपत्ति पर आपने ध्यान दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, किस साल हुआ, उसका क्या नम्बर है ?

श्री मदनसिंह : पूरे केस में स्टे मिली उसका फैसला है । जागीरदारों को स्टे इस पर मिला है कि जागीरदारों को सक्सेस मिल जाती है तो ठिकाने की रकम उसके पास रखे और अगर जागीरदार लूज़ कर जाता है तो ज़ागीर की रकम वापिस ले ली जायगी ।

उन छोटे जागीरदारों के साथ जुल्म हो रहे हैं । उनका सुप्रीम कोर्ट से कोई संबन्ध नहीं था । उन पर आज जुल्म हो रहे हैं । गवर्नमेंट चलान कर उन पर जुल्म करवा रही है और उस कानून के विपरीत कर रही है । इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि इतना होने के बावजूद भी उन पर जुल्म किये जा रहे छोटे जागीरदारों का सुप्रीम कोर्ट में जाने का उस वक्त सवाल ही नहीं था क्योंकि उनकी जागीरें उस समय तक समाप्त नहीं हुई थीं । इसलिये, मैं यह निवेदन करूंगा कि जागीरदारों के संबन्ध में

(श्री मदनसिंह)

आनेवाले कानून में इसका ध्यान नहीं रखा गया तो मैं समझता हूं कि आपका उनको मुआवज़ा देना न देना बराबर हो जावेगा। जहां छोटे जागीरदारों पर पंडितजी ने ध्यान दिया वे यों के यों रह जावेंगे और बड़ों को मुआवज़ा मिल जावेगा।

इसके अलावा सब से बड़ा जुल्म जैसलमेर के जागीरदारों पर हुआ है। उस रोज़ सदन में राजस्व मंत्री जी ने जोश में आकर यह कहा था कि एक महीने में सारी जागीरें खत्म कर दी जावेंगी। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने जैसलमेर में एक सैटलमेंट अधिकारी को भेज कर सैटलमेंट कराया और उस अधिकारी ने जिनके पास ५००० बीघा थी उनको ५० बीघा, १०० बीघा थी उनको दो बीघा और ३०० बीघा थी उसको ४ बीघा इस प्रकार का गलत सर्वे सैटलमेंट करवा कर, जागीरें खत्म कराईं। मैंने जोधपुर में इन्क्वायरी की, वहां के सैटलमेंट अधिकारी ने कहा कि वाकई में गवर्नमेंट ने जिनके पास १००० बीघा थी उसके पास १० बीघा और जिसके पास ५०० बीघा थी उसके पास ५ या ४ बीघा जमीन लिखी है। वह सैटलमेंट का सैटलमेंट ही पूरा गलत हुआ है। अगर इस सैटलमेंट पर उनका कम्पेन्सेशन तय होता है तो मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह उनके साथ अन्याय और जुल्म नहीं तो क्या हो सकता है। इसी लिये मुझे कुछ जागीरदारों के बारे में कहना था।

जब उपाध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में हिन्दुस्तान और सारे दूसरे लोगों को बड़ा लाभ दिखाई देता है। इस पर इतना विचार हुआ। माननीय उपाध्यक्ष, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और शर्त के साथ कह सकता हूं कि कोई मिनिस्टर, राजस्व मंत्री या अन्य मंत्री ईमानदारी से बात करें तो उनको पता लगेगा कि यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। या तो व्यक्तिगत अधिकार ही रहेंगे या कोऑपरेटिव फार्मिंग ही। इससे व्यक्तिगत अधिकार किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। यदि कोई कहता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग से व्यक्तिगत अधिकार रह जावेंगे तो यह गलत है। मैं यह कहूंगा कि ऐसा कहना नागरिकों को धोखा देना है। कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि इन्डिविजुअल का कोई हक नहीं है। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि किसान लोग इसको पसन्द करेंगे तो मैं आपसे यही निवेदन करुंगा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी से स्तीफा देकर चले आयें और फिर दुबारा चुनाव लड़ें। यदि किसान आपको वोट देते हैं तो मैं इस बात को स्वीकार करुंगा कि आज का किसान इस बात को चाहता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग हो। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री तो यहां पर नहीं है, अगर उनके साथ इसी आधार पर अगर आज भी कोई स्तीफा दे और फिर चुन कर आ जावें तो मैं कहूंगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को किसान चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जोधपुर में २४ घन्टों में काश्तकारों को सरकार ने खातेदारी राइट्स दिये, उन लोगों को आज धोखे में रखा जा रहा है और उनको आज यह कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी उनकी व्यक्तिगत मिलकियत रहेगी।

Page No.34

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू क्या श्री परमपिता परमेश्वर भी अगर यह कहें कि हम रात को सूर्य की रोशनी दिखा सकते हैं तो नहीं दिखा सकते। कोऑपरेटिव का मतलब ही यही है कि उस पर सब का अधिकार हो और उसमें एक का अधिकार नहीं हो। मैं यह समझता हूं कि या तो कोऑपरेटिव फार्मिंग चलेगी या सरकार चलेगी, यह डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। राजस्थान का किसान जग गया है। अब यह चल नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार अभिशाप दिये जाने से अभिशापों का महत्व खत्म हो जावेगा।

श्री मदनसिंह : राजस्थान का किसान अब समझ गया है। राजस्थान के किसानों में भी राजनीतिज्ञ हैं। इसलिये अब वे दिन गये जब कांग्रेस १२ बजे किसानों को यह सुनाया करती थी कि उनके सोने और चांदी के महल बन जावेंगे, हल टूट जाएगें तो लोहे के इंजिन दे दिये जावेंगे, अब आज वह किसान नहीं रहा है। डट कर मुकाबला रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अब किसान बन गये हैं। आप पहले यह कहते थे कि मुर्गों को ठोक कर पाकिस्तान भगा देंगे। मगर यहां तक ले आये हैं।

श्री मदनसिंह : मैं यह कहूंगा कि राजाओं के राज्य में और जागीरदारों की जागीरें लेने में धोखे बाजी हो सकती है। उनको धोखा भी दिया तो कोई एतराज नहीं। मगर जिन काश्तकारों की हड्डियों पर देश की नींव है...

श्री नाथूराम मिर्धा : वे ही जागीरदार आज किसान बन गये हैं वे मुकाबला करेंगे और उसका नतीजा यही होगा जो आज तक हुआ है।

श्री मदनसिंह : आज जागीरदार किसान हैं। आपने जागीरदारों और किसानों को लड़ाया है और इसके लिये क्या क्या प्रचार किये हैं मैं आपको क्या बताऊं...

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन के बाहर जो विचार होते है उस पर न चलें।

श्री मदनसिंह : मैं सदन में और सदन के बाहर एक ही चीज़ कहता हूं। मैं न तो पब्लिक को धोखा देना चाहता हूं और न सदन को धोखा देना चाहता हूं। इसलिये मेरे विचार बाहर और यहां पर एक ही होंगे और यही मैं मान कर चलता हूं और इसी लिये मैं चुन कर आया हूं।

इसलिए जिन लोगों ने खेतों के कब्जे के लिये यहां तक कहा कि तुम अपनी बुड्ढी माता को बांध कर कूंए में डाल दो यह तो मरने वाली ही है और जागीरदार का नाम ले लो। यह खेत तुम्हारे पास रह जावेगा। इस प्रकार करके अपनी बुड्ढी माता को कूंए में डाल कर और उसका त्याग करके जमीन पर कब्जा पाया। उनके लिये यह करना नामुमकिन होगा और मैं समझता हूं कि अगर सरकार को यही चीज़ करनी थी तो आज से ८ वर्ष पहले क्यों नहीं किया। इसके लिये आपने जागीरदारों और किसानों को लड़ाया, मजदूरों को और मालिकों के लड़ाया राजा और प्रजा को लड़ाया और उनको समाप्त किया।

Page No.35

(श्री मदनसिंह)

मगर आज किसान अकेला रह गया है इस वक्त किसान पर हमला है और यह साफ़ ज़ाहिर है कि आपने राजाओं को समाप्त किया है, जागीरदारों और जमींदारी को समाप्त किया है, आज किसानों को समाप्त किया है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके लिये कोऑपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग बनाया है। जिनको खातेदारी राइट्स आपने दिये वे उनके खातेदारी राइट्स खत्म होते हैं। बड़े से बड़ा नेता क्या..

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ऑफिशियल गैलेरी में कोई अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : We are not concerned with what they are doing in the Officers' Gallery until they do not disturb the proceedings of the House. We are concerned with the proceedings in the House.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But I wish to submit, Sir, that it is an insult to the Chair for any officer to read newspaper in the gallery and I will request the Chair that some decorum must be observed when the House is in Session.

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observation.

श्री श्रीभानसिंह : But I will again submit, Sir, that to read newspaper in the Officers' Gallery is an insult to the Chair and it is......

श्री उपाध्यक्ष : Anyway, the officers have taken a note of the sense of the House.

श्री मदनसिंह : इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन काश्तकारों के वोट लेकर आप यहां आये हैं उनको इस सम्बन्ध में समझाने की जरूरत थी। उनको कुछ लोग समझावेंगे मगर आज जो ...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात पसन्द नहीं आई, मगर ५ करोड़ रुपये दिलाये वे तो बहुत अच्छे लगे।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मुआवज़े की बात इसलिये पसन्द आई कि रुपये आये।

(हंसी)

इसीलिये झगड़ रहे हैं कि रुपया ज़्यादा आवे। इसलिये मैं समझता हूं कि काश्तकारों के लिये यह कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में समझाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष ईश्वर करे, सरकार किसानों को छेड़े। हम तो चाहते हैं कि जितना छेड़े उतना ही अच्छा है। ईश्वर जिनकी बुद्धि हर लेता है उसका नतीज़ा अच्छा नहीं होता है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर अभिशाप देने लगे हैं। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि बार बार अभिशाप देने से अभिशाप का महत्व कम हो जाता है।

श्री मदनसिंह : मैं यहां पर इसी लिये आया हूं कि सरकार का विरोध करूं।

(श्री मदनसिंह)

मैं यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह सरकार खत्म हो और अच्छी सरकार बने। इसीलिये मुझे वोट दिया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि को-ऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होना चाहिये। अगर यह हुआ तो प्रजातन्त्र को खत्म किया जा रहा है। आज व्यापार की क्या हालत है। अनाज के पूरे व्यापार को हाथ में लिया जा रहा है। जनता को इतनी दबाया जा रहा है कि वह रोटी के लिये भी सरकार का मुंह ताकती रहे। It is a move towards Communism. जिसका विरोध होगा। आज तो शक्ति नहीं है उपाध्यक्ष महोदय कि सरकार कह सके कम्युनिज़्म की छाया है। इस पर यदि विचार नहीं किया तो एक दिन इस ओर ही प्रस्थान हो जायगा। एक मुसलमान राजा था वह बहुत ही शतरन्ज का शौकीन था। उसको सूचना दी कि फौज आई है। लेकिन वह देखता ही रहा कि ऊंट किस तरफ बैठा था। ईश्वर आपको भी ऐसी ही बुद्धि दे। इसलिए मैं कहता हूं कि अनाज का जो काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है उसका डट कर मुकाबिला होगा। आप तो जनता को समझाना चाहते हैं कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं और जाना चाहिये, कहते हैं कि किसानों के लिए बड़ी चीज़ होगी लेकिन मैं कहता हूं कि आपको यह विचार कर लेना चाहिये कि राजस्थान की जनता जागरूक है और डट कर मुकाबला करेगी।

मुझे दुख है इस बात का कि राज्यपाल महोदय के भाषण में ये चीजें आ जानी चाहिये थीं और हम तो सोचते थे कि हमारे वयो वृद्ध राज्यपाल महोदय हैं वे सारी गति विधि से परिचित करेंगे। किस तरह से नागपुर का प्रचार हुआ, कितनी बड़ी चीज़ हुई, लेकिन उन्होंने कुछ विचार नहीं रखे। राज्यपाल महोदय का भाषण अधूरा था, इसलिए, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में कृपा पूर्वक दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन में काफी ऐसी बातें कहीं गई हैं, जिनसे एक बात साबित हो गई है कि बिल्ली थेले से निकल आयी है। जैसी अंग्रेज़ी में कहावत है कि : The cat is out of bag. बड़ा राजस्थान बना तब से इस सदन के कुछ मित्र जनतन्त्र और उसके बिचली जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो शोषण पर आधारित है, उसको दूर करने की बड़ी हिमायत की। लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति में परिवर्तन की बात कही गई है, उससे हमारे मित्र इस प्रकार चौंक गये हैं कि उन्होंने अपना सच्चा स्वरूप सदन में रखने में संकोच नहीं किया है।

एक बात कही गई संयुक्त सहकारिता द्वारा खेती करने के सम्बन्ध में, जिसका राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संकेत किया कि उससे जनतन्त्र समाप्त हो जायगा। किसानों की व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जायगी। हुकुमत का एक षड़यन्त्र है, यह किसानों के साथ धोखा है, मैं कहना चाहता

(श्री जनार्दनराय नागर)

हूं कि न तो किसानों के साथ धोखा है और न ही जनतन्त्र को समाप्त करने की बात है और न उन लोगों के साथ भी धोखा है जो जागीरदारी की बड़ी हिमायत करते थे। सच बात यह है कि जमाने में जो परिवर्तन हो रहा है उसको मेरे मित्र समझ नहीं पाये हैं और जिससे वे चौंधिया से गये हैं। को-ऑपरेटिव बनने से जनतन्त्र नष्ट कर दिया जावेगा इसके बजाय मेरे मित्र यह कहते कि जनता की शक्ति को-ऑपरेटिव में लगने से मज़बूत होगी तो मैं समझता कि जनतन्त्र की प्राथमिक बात को वे समझ पाये लेकिन मैं समझता हूं कि वे आगे बढ़े ही नहीं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपने तो उदयपुर ही देखा है।

श्री जनार्दनराय नागर : जब जागीरदारी समाप्त करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि समाज में उथल-पुथल हो जायगी, अशान्ति फैल जायगी। उथल-पुथल और अशान्ति फैलाने की कोशिश की भी गई। लेकिन आज अब कोऑपरेटिव नीति को लेकर चलना चाहते हैं तो धमकियां दी जा रही हैं कि एक संघर्ष होगा। संघर्ष की बात हमारे सामने लायी गई। मैं तो कहता हूं कि संघर्ष करते आये हैं एक नया राजस्थान बनाने के लिए, और एक नया हिन्दुस्तान बनाने के लिये। संघर्ष की धमकियों से आगे बढ़ने वाले कदम रुक नहीं सकते। जनतन्त्र की रक्षा के लिए, जनतन्त्र के पोषण के लिए हिन्दुस्तान की जनता को आज नहीं, कल नहीं, एक सदी तक निरन्तर संघर्ष करना पड़ेगा। कई देशों को, समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए और उसकी रक्षा के लिए सदियों तक संघर्ष करना पड़ा है और संघर्ष किया भी है। हमारे जनतन्त्र की रक्षा के लिए, समाजवादी समाज व्यवस्था की रचना के लिए यदि हमें रक्त भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। लेकिन समाजवादी समाज व्यवस्था को उजड़ने नहीं दिया जायगा। उसकी रक्षा की जायगी।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : यह संघर्ष आपस का है।

श्री जनार्दनराय नागर:(जारी)जनतन्त्र की शक्ति एक अटूट शक्ति है, राजस्थान की जनता जानती है, हिन्दुस्तान की जनता जानती है और भूमन्डल पर रहने वाली मानव जाति की प्रगति इसी में निहित है। मेरे मित्रों को पता नहीं है कि जनतन्त्रीय समाज व्यवस्था ने समाज के दुखों को दूर करने में, शोषण को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है।

श्री मदनसिंह : नेहरूजी का भाषण सुन लेवें।

श्री जनार्दनराय नागर : एक अरब जनता उस भूमंडल पर रहती है, सूर्य और चांद को मित्र बनाने की कोशिश की है, जहां शोषण का नाम नहीं है, राजस्थान को उस दूरी पर ले जाना चाहते हैं, हम गर्व से कह सकें कि शोषण करने वाले नहीं है, अब वो ताकत नहीं है शोषण करने की। हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जागीरदारी समाप्त करने के बाद, सामन्ती व्यवस्था को धीरे २ समाप्त किया, और समाजवादी अर्थ व्यवस्था का मंगलाचरण करें। राज्यपाल

Page No.38

(श्री जनार्दनराय नागर)

महोदय ने एक बारीक बात बड़ी सरलता से कही है कि अब राज्य की नीति यह है कि संयुक्त सहकारी खेती पर आधारित हो। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को उल्टा यह कहना चाहिये था कि आपने हमको मार्ग दर्शन दिया, आधार भूत नीति की ओर मार्ग दर्शन दिया, लेकिन इसके विपरीत बात करते हैं कि राज्यपाल महोदय ने सहकारी खेती के लिए एलान क्यों किया इसलिए धन्यवाद नहीं देना चाहिये। लेकिन जो जनतन्त्र के हामी हैं और जनतान्त्रिक पद्धति द्वारा जनता की प्रगति चाहते हैं वे ईमानदारी और निश्चित रूप से कहेंगे कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक युग परिवर्तन की ओर संकेत किया है। राज्यपाल महोदय ने इस सदन को कई बार संबोधित किया है और उन सम्बोधनों और इस सम्बोधन में भारी अन्तर है। राजस्थान के शासन सत्ता को विकेन्द्रित करने की जो नीति है और ग्राम्य क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था करने का जो आधार है, राज्यपाल महोदय ने निश्चित रूप से उस नीति की ओर इंगित किया है। स्वयम् राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दो आधार भूत बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं और राजस्थान राज्य की सर्व प्रकार की नीतियों पर उनका बड़े विस्तार से प्रभाव पड़ने वाला है। उन्होंने स्वयं ने कहा है इन दोनों बातों को सोचें। इन दोनों बातों के सोचे बिना चैन नहीं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि राज्य की सरकार यह चाहती है कि जो व्यक्तिगत मुनाफाखोरी की नीति है व्यक्तिगत पूंजी लगाकर जो व्यक्ति धन अर्जित करना चाहते हैं उसको धीरे-धीरे राज्य सरकार खत्म करके, समाज की रचना की ओर कदम उठाना चाहती है। इसका एक ही तरीका है और वह यह है कि समाज के हर क्षेत्र में, हर इकाई में, हर घटक में सहकारिता लायें। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के कुछ विचारक इस सहकारिता और इस सहकारी आर्थिक व्यवस्था को पसन्द नहीं करते, वे कहते हैं यह नादिरशाही है, यह अव्यवहारिक है और यह समाज को पीछे ले जाने वाली बात है यह उन लोगों की बातें हैं जो धीरे-धीरे अपने चेहरे का रंग बदलते आ रहे हैं और उन चेहरों में छिपी हुई प्रतिक्रियावादी ताकतें आज समाज के सामने आती जा रही है। भारत की आज़ादी के बाद में जब हमारे देश में लोकसभा और राज्यों में विधान सभायें कायम हुई उस समय प्रतिक्रियावादी ताकतें जिनके पास परम्परा से चली आ रही, शोषित मनोवृत्ति थी, उन्होंने भी नया नकाब धारण कर लिया, नया चेहरा लगा लिया और जनतंत्र के हिमायती होकर इस देश की व्यवस्था के अन्दर अपना प्रभाव डालना शुरू किया। लेकिन जब ऐसे दौर आये जिसमें उनकी नकाब धीरे-धीरे हटती गई और उनका सही रूप सामने आने लग गया और उनकी प्रतिक्रिया सामने आने लग गई। आज वह इस सीमा पर पहुँच गई जिससे वे बच नहीं सकते और न वे चुप ही रह सकते। जब समाजवादी समाज की व्यवस्था का नया दौर चल रहा है, वे आज पुरानी बातें करते हैं। लेकिन आज के जनतन्त्र में वे चलने वाली नहीं है उनका कहना है कि इस सहकारी व्यवस्था वह में कारगर नहीं होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके बजाय वे कौनसी व्यवस्था इस जनतंत्र में लाना चाहते हैं।

(श्री जनार्दनराय नागर)

हमें सही रूप में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू करनी है तो हमें मुनाफाखोरी ख़त्म करनी पड़ेगी। हमने जागीरदारी समाप्त की क्योंकि वह व्यक्तिगत शोषण था जागीरी प्रथा की समाप्ति के बाद हमने छोटी-मोटी आर्थिक व्यवस्था इसलिये खत्म की कि उनसे शोषण होता था। हमारा तो यह पक्का इरादा है शोषण मात्र को खत्म किया जाय...

श्री मदनसिंह : हम भी यही चाहते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) इसीलिये तो सहकारिता आयगी और अभी तो सर्विस क्लास की बातों तक ही यह सहकारिता ला रहे हैं लेकिन हमारा बस चलेगा तो हम कलेक्टिव कोऑपरेटिव लाकर ही रहेंगे। हमारा कदम उस ओर बढ़ रहा है और हम अवश्य इसमें सफल होंगे। हम समाजवादी समाज की रचना कर उसके लिये काम शुरू करके उसके मंगलमय अन्त तक जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश में सही मायने में किसान और मजदूर का राज्य हो जनता का राज्य हो और सदियों से चले आ रहे शोषण का अन्त हो...

श्री मदनसिंह : आज तो पूंजीपतियों का राज्य है।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) सदियों से चली आरही शोषित मनोवृत्ति वाले लोगों की कल्पना आज लड़खड़ा रही है आज उनको भय है आज वे विचित्र स्थिति में आपको उनके प्रति सहानुभूति हो सकती है। ये शक्तियां अंग्रेजों के समय से इस ताक में बैठी है कि उनका वश चले तो फिर सामन्ती शासन कायम कर दें लेकिन आज उनका वश चलने वाला नहीं। आज हिन्दुस्तान में जनता का मंगलमय राज्य कायम है जो देश को दिन प्रति दिन प्रगति की ओर ले जाना चाहता है। यह जो बातें कहीं गई वह हमें मालूम थीं और हमें खुशी है उन लोगों ने आज अपना नकाब उतार दिया है और वे जनता के सामने आगये हैं।

राज्यपाल महोदय के वयोवृद्धता की जा रही है, उनके वयोवृद्ध व्यक्तित्व पर उनको बड़ा विश्वास है। राज्यपाल महोदय के अनुभव और उनके वयोवृद्ध व्यक्तित्व ने निसन्देह राज्य को मार्ग दर्शन दिया है और मैं सोचता हूँ जिस जनता की तरफ से आप आये हैं उनको भी इसमें विश्वास होना चाहिये। आपको जनता के नाम पर, किसानों के नाम पर इस प्रकार की शंका उत्पन्न करेंगे यह तो हमें पता था। आप किसानों को इस बारे में कहेंगे कि आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति छीनी जा रही है...

श्री मदनसिंह : ये तो साहित्यिक बातें हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) साहित्य एकेडेमी की बात का जवाब तो मैं फिर दूँगा। आप से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की बातें कह कर आप एक प्रकार से जो राजनैतिक फ़िजां पैदा करना चाहते हैं और किसानों में यह भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति छीनी जा रही है। राजाओं का जब राज्य लिया गया उस समय उनको यह सन्देह हुआ कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ली जा रही है जागीरदारों से जब जागीरी ली

(श्री जनार्दनराय नागर)

गई उस समय भी यह कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ली जा रही है। माफीदारों से माफी ली गई तो भी व्यक्तिगत सम्पत्ति लिया जाना कहा गया...

श्री मदनसिंह : ये बातें तो आप ठीक कहते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में मालिकाना हक का भी ज़िक्र किया है लेकिन आज दो युग के बाद अगर हिन्दुस्तान में इस मालिकाना हक को जीवित रखना चाहते हैं तो यह नहीं रहेगी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति रहने वाली नहीं है हमें यह मानकर चलना चाहिये आखिर हमारे समाजवादी समाज की रचना की यही तो कसौटी है, धीरे-धीरे हम इस शोषण को समाप्त करने जा रहे हैं और मेरी तो यह मान्यता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति नाम की कोई वस्तु रहनी ही नहीं चाहिये। आज जो यह कहते हैं ये बाल बच्चे हमारे हैं इस सम्पत्ति पर उनका अधिकार है यह उनकी व्यक्तिगत है इस प्रकार के व्यक्तिगत मालिकाना अधिकार का आज जो पुराना रिवाज़ हो गया है वह धीरे-धीरे समाप्त होकर रहेगा। आज जनता में सामूहिक शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसका मुकाबला जो व्यक्ति करेगा वह टिकने वाला नहीं है, जो ताकत इसका मुकाबला करेगी वह ताकत टिकने वाली नहीं है।

श्री मदनसिंह : ऐसा ही पाकिस्तान वाले कहा करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : आज जमाना इस बात को स्पष्ट कह रहा है, हमें अन्य देशों के मुकाबले खड़ा रहना है, उसके मुकाबले की शक्ति हमें उत्पन्न करनी है। मैं यह मानता हूं कि गांव के स्तर पर, तहसीलों के स्तर पर, जिलों के स्तर पर जनता राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई में संगठित की जानी चाहिये तभी हमारे देश में शक्ति पैदा होगी, तभी हम अन्य देशों का मुकाबला कर सकेंगे।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कि रूस ने सारे ब्रह्माण्ड में अपना उपग्रह भेज दिया है जो आज सूर्य की परिक्रमा कर रहा है क्या आपके यहां एक भी विज्ञान का आविष्कार हुआ है इन चालीस वर्षों के अन्दर जो रूस ने विज्ञान के युग में प्रगति की है वह साम्यवादी सभ्यता और शासन की प्रगति का सूचक है। कहने की बात है उपाध्यक्ष महोदय लोग यह कहते हैं कि साम्यवादी शासन प्रणाली में बहुत शोषण होता है ये सब कहने की बातें हैं। आज साम्यवादी शासन ने हमारे सामने अपनी प्रगति का नक्शा रक्खा है उसका हमें उत्तर देना चाहिये। सामन्ती संस्कृति सभ्यता और प्रतिक्रियावादी ताकतें उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। मेरी तो यही मान्यता है कि समाजवादी व्यवस्था के द्वारा ही इस देश का मंगलमय भविष्य बन सकता है।

राज्यपाल महोदय ने जो सहकारी समाज की रचना का ज़िक्र किया है वह आज के समय में अत्यन्त अनिवार्य है। समाजवादी समाज की नीति इसका प्रथम चरण है और वही देश को आगे ले जाने का मार्ग है। अगर हम उनके कहने के मुताबिक मार्ग नहीं बदलते तो हम अन्य देशों की प्रगति की होड़

(श्री जनार्दनराय नागर)

में पीछे रह जायेंगे। आज समय यह नहीं है कि हम किसी प्रकार की शंका करें। यह समय बहस करने का नहीं, आज जब कि हम सहकारिता की ओर बढ़ रहे हैं हमें समाजवादी सभ्यता के अन्दर दाखिल होने का समय है..

श्री मदनसिंह : यह प्रजातंत्र के अनुकूल भाषण नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : हम सब को इस बात को स्वीकार करना चाहिये और हमारा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिये कि राज्यपाल महोदय ने जिन बातों का इंगित किया है निश्चय ही हम उसी मार्ग द्वारा आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इस मार्ग में कठिनाइयां आवेंगी, कई उहापोह भी आयेंगे किन्तु हिम्मत और धैर्य के साथ जिस प्रकार हमने पहले भी कई समस्याओं का सामना किया है। इसमें आने वाली बाधाओं का भी हल निकाल लेंगे।

दूसरी बात, जिस ओर राज्यपाल महोदय ने इंगित किया है वह है सत्ता के विकेन्द्रीकरण की। राज्य सरकार न केवल इस प्रकार का संकल्प ही करती है बल्कि यह उसकी एक नीति होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई जब से बड़ा राजस्थान बना है तब से हम बहुत से अनुभव करते जा रहे हैं। सत्ता केवल जयपुर में केन्द्रित होती जा रही थी केवल जयपुर में ही सारी सत्ता को समेट कर रख दिया गया था, उसका विकेन्द्रीकरण होना बहुत जरूरी था। इस बारे में सदन में भी कई माननीय सदस्यों ने और अन्य लोगों ने बात की मांग की कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और यह आग्रह निरन्तर ज़ारी रहा। पर दुर्भाग्य से...

श्री मदनसिंह : It is repetition there.

श्री जनार्दनराय नागर : कुछ ऐसा भी लोगों का दृष्टिकोण है कि पंचायतों को शक्ति देने से अव्यवस्था हो जावेगी। अभी दो तीन छोटे मोटे नमूने भी रक्खे। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम करने बैठेगा, उससे गलतियां तो हांगी।

श्री मदनसिंह : कल बड़े नमूने थे, आज छोटे नमूने रक्खे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : पर मैं मानता हूं कि वह समय अब आ चुका है जब कि हमें सत्ता को विकेन्द्रित कर देना चाहिये। इससे प्रगति के काम, विकास के कार्य अधिक सुविधापूर्वक हो सकेंगे। राजस्थान सरकार ने आज जो यह निर्णय लिया है वह सुन्दर है। मैं कहता हूं यह अहसान नहीं है, मेहरबानी नहीं है। यह परम आवश्यक बात थी। मैं इसका कारण समझता हूं। आज तीन चार सालों से विकास के लिये जो खर्चा करने की क्षमता हमारी बढ़ रही है उस खर्चे को सुचारू रूप से खर्च करने के लिये आज यह आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है कि सत्ता नीचे दी जाय। यदि सरकार को तीसरी योजना को सफल बनाना है तो निश्चय ही सरकार को सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होगा।

परिषदों का और पंचायत मंडलों का खयाल रक्खा गया है यह जनतान्त्रिक पद्धति की रीति नीति के प्रारम्भ का बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। यदि हमें भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है, यदि हमें कुनबापरस्ती का मुकाबला करना है, जिसकी मेरे कई मित्र काफी चर्चा

(श्री जनार्दनराय नागर)

करते हैं और परेशान रहते हैं और जिन्हों ने भ्रष्टाचार की बात कहना अपना एक तरह से शिष्टाचार बना लिया है, तो ये सारे दोष इससे दूर होंगे। इसके मानी यह नहीं कि इस स्तर पर भूलें नहीं होंगी, होंगी, पर इसमें परेशानी की क्या बात है, जनता का राज्य है, जनता के संगठनों को यदि हम सत्ता देते हैं तो गलतियों से जनता अनुभव हांसिल करेगी, भूलों से वह सीखेगी, सोच कर आगे बढ़ेगी। आज एक कलेक्टर और कमिश्नर क्या गलतियाँ नहीं करते ? क्या उनसे भूलें नहीं हुई या नहीं होती ? जनता में सम्पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। वोट देते समय तो आपको उनकी सूझबूझ अच्छी लगी, तब तो उनका निर्णय बड़ा प्रामाणिक लगा, तब तो वह बड़ी जागरूक और सतर्क लगी पर जब उसे सत्ता देने की बात आती है तो यही लोग कहते हैं यह तो गड़बड़ी की बात है। जिस जनता पर वोट के वक्त विश्वास करते हैं उसको सत्ता देने से इन्कार मत करिये। करते हैं तो मानकर चलिये कि आप जनता की रीति नीति के हामी नहीं हैं। आज तो आप हल्के से उसे वे सब अधिकार दे दीजिये, नहीं तो, जमाना आ रहा है, जनता के पास सत्ता जा रही है और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि राजस्थान सरकार ने इस बारे में ठीक निर्णय लिया। यह भी देखना चाहते हैं कि इसकी कितनी मात्रा है। किस मर्यादा और अवस्थाओं के साथ सत्ता सौंपी जा रही है। यह सम्बन्धी विधेयक जो रक्खा जाने वाला है उसको बड़ी उत्सुकता और दिलचस्पी से हम देख रहे हैं। हमारी इसमें दिलचस्पी है। राज्यपाल महोदय ने जो ऐसी जाग्रति का क़दम उठाया है और सत्ता विकेन्द्रीकरण की हमारी पुरानी मांग को पूरा करने का जो विश्वास दिलाया है, उसके लिये हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं।

यह जो बात कही गई उनके भाषण को लेकर कि उनका इससे सम्बन्ध नहीं था, उनका भाषण तो सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार था। इस तरह के रिमार्क अनुचित हैं। उनका भाषण पिछली प्राप्तियों के उल्लेख से प्रारम्भ हुआ आगे उसमें यह बताया गया कि अगले एक वर्ष में हम क्या-क्या प्रगतिशील नीतियाँ अमल में लाना चाहते हैं। इसके लिये कह देना कि सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की विज्ञप्ति जैसी है, यह ठीक नहीं है। यह भाषण युग परिवर्तन की तरफ खास संकेत है। निस्सन्देह उन्होंने कहा है कि एक नये युग की ओर राज्य सरकार को जाना है।

दो चार पाँच पुरानी बातों को लाया गया। मैं उनमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनका सम्बन्ध मुझ से नहीं है। पर हम भ्रष्टाचार की और कुनबापरस्ती की बातें बहुत करते हैं, बाहर भी करते हैं, यहां भी करते हैं। चार बड़ों ने जो वक्तव्य दिया, उसका भी बार-बार ज़िक्र करते हैं। इसको मैं समझता हूं कि यहां लाने से राज्यपाल महोदय के भाषण से क्या सीधा सम्बन्ध पड़ता है। पर वह बात कही गई और उससे एक प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने कहीं उन्हें दुनिया जानती है। उनका फैसला हो चुका है। फैसला यह हुआ है कि आज जो सरकार में बैठे हैं उनमें अपनी पार्टी ने सम्पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। पर घूम फिर कर फिर इस सदन में लाकर यह बात साबित

(श्री जनार्दनराय नागर)

करने की कोशिश करना, और कहना कि पाँच बड़ों ने वक्तव्य दिया और वह काफी है। मैं कहना चाहता हूं कि उन लेक्चर देनें वालों ने भी शासन किया है। उनका भी शासन प्रान्त में था। भ्रष्टाचार क्या उनके समय में नहीं था, आज वह सारे हिन्दुस्तान में है। लेकिन उसको दूर करने का तरीका जैसा मैंने बताया किसी एक आदमी को लाकर उसे हुक्म देकर, सस्पेन्ड करके निकाल देने में नहीं है। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि यह तो एक राष्ट्रीय रोग है जो हमारे समाज में बहुत गहराई से बैठा हुआ है। हमारा सारा खून ही इससे खराब हो गया है। इस वजह से इसे व्यापक तौर से, गये तरीकों से, समाज के सारे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को नये सिरे से बदल कर ही दूर करना पड़ेगा। यह ऐसा काम नहीं कि आपकी फूंक से दूर हो जाने वाला हो, यह काम तो सारे हिन्दुस्तान के समाजों को करना है। मैं दावे से कहना चाहता हूं आज वे शासन पर आकर बैठें। वे थोड़ा भी दूर कर सकते हैं या नहीं, मालूम हो जावेगा।

श्री मदनसिंह : यह क्या हो रहा है ?

श्री जनार्दनराय नागर (जारी) : द्वितीय महायुद्ध के बाद में उसके परिणाम स्वरूप ऐसा तनाव आया है। मैं आपके सामने दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के प्रमाण देना चाहता हूं। एच० जी० वेल्स का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने लेख लिखा। वस्तु भाव बढ़ता चला जाता है। तमाम संघर्ष की शक्तियां बढ़ती जाती हैं। उनकी वजह से आज सारे संसार में अन्धकारमय मनों का दौर गुजर रहा है जिससे नैतिक मूल्यों का स्तर स्थिर नहीं रह सकता। हमने जो परम्परा से नैतिक मूल्य प्राप्त किये, वे नष्ट होते जा रहे हैं। नये बन नहीं रहे हैं। संक्रमण काल में से हम निकल रहे हैं। ऐसे वक्त यह कहें कि हलके फुलके यह भ्रष्टाचार कहने से, बोलने से कम हो जावेगा, यह नहीं है। इसके लिये भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों से मिल जुलकर किसी तरह उनसे कोई दफ्तर का सीक्रेट कागज़ निकाल कर ले आना और यहां उस पर बोल देना, उनसे विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करना क्या यह भ्रष्टा चार का अंग नहीं है। अपनी अन्तरात्मा से सोचकर बतावें कि क्या यह भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह तो भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : भ्रष्टाचार किस कारण से पैदा हुआ, कहां जाकर रुका है, यह तो एक तपेदिक की बीमारी है, महामारी के समान है। यह महामारी है।

श्री मदनसिंह : कल आप बच गये।

श्री जनार्दनराय नागर : आपके सहयोग की भी जरूरत है इसमें। निश्चित रूप से अपराधी कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें सख्ती से दण्ड दिया जाय। पर इसका क्या आप जवाब देंगे, जब कि समाज की सारी व्यवस्था में ही तनाव हो। संक्रमणकाल में से गुजर रहे हैं, पुराने मूल्य टूटते जा रहे हैं नये पैदा नहीं कर पाये हैं। हमें इस मामले में धैर्य और शान्ति से काम लेना पड़ेगा। यह विषय

(श्री जनार्दनराय नागर)

समाज की स्थिति का विषय है। मैं समझता हूँ कि पं० जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमन्त्री हैं और हम उनसे कह सकते हैं कि आप हमारे देश के प्रधान मन्त्री हैं पर देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिये कह दीजिये आप उनको कि आप नाकाबिल हैं और आप नहीं रहने चाहिये, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सके। मेरी समझ में नहीं आता जब कि रात दिन इससे दूर करने के प्रयत्न किये जाते हैं तो भी बार-बार यह बात सदन में कही जाती है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। इससे मैं मानने को मजबूर हूँ कि भ्रष्टाचार की बात करना उनके लिये शिष्टाचार है। दूसरी बात भीलवाड़ा के बारे में आपने कही। यह कहा गया कि भीलवाड़ा जिला सारे राजस्थान के अन्दर करप्शन का अड्डा बना हुआ है, इसके अलावा और भी बातें कहीं गईं। मैं किसी अमुक जिले को लेकर और उसके बारे में इस प्रकार की बात कहना, मैं इस प्रकार समझता हूँ कि जैसे वहां कोई शासन ही नहीं है, वहां कलेक्टर ही नहीं है, वहां एस० पी० ही नहीं हैं इस तरह का चित्र अंकित करना, मैं कहता हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एक जिले में रहने वाले लाखों लोगों के प्रति अन्याय होगा यदि वह सरकारी लोगों की निन्दा करना चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन सारे जिले के बारे में इस प्रकार का एक निर्णय यहां पर करना,

(१·२ म० प०)

एक जिले के प्रति कोई आदरणीय दृष्टिकोण का सूचक नहीं होगा। अगर वह इसी प्रकार की बात किसी अमुक जिले के बारे में कहते हैं तो मैं भी उनके जिलों के बारे में ऐसी बातें कह सकता हूँ और उनके जिले में भी ऐसी घटनायें होती हैं। उनको बता सकता हूँ, पर उपाध्यक्ष महोदय इस व्यर्थ की छींटाकसी करने में मैं कोई तर्क और तथ्य नहीं समझता। फिर तो उनके भी व्यक्तिगत बातों के बारे में कहा जा सकता है कि वह स्वयं भी किसी को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि एक जिले को लेकर कहना कि वहां करप्शन का अड्डा है तो हम कह दें कि जिला यहां के राज्य के बाहर का जिला है, वह जैसे और जिले राजस्थान के हैं, भीलवाड़ा भी राज्य का एक जिला है। क्या वहां पर कोई सरकार की सृष्टि नहीं है। मैं कहता हूँ कि वहां पर पूर्ण शासन है और सब प्रकार की सरकार की गतिविधियां वहां पर पूर्णरूप से पनप रही हैं। इसलिए एक जिले को इस सदन में बदनाम करने की कोशिश करना, बिल्कुल अनुचित बात है और यदि इससे किसी प्रकार का कोई रोष पैदा होता है तो वह उपयुक्त नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : बोलने के ऊपर सीलिंग करें तो अच्छा रहेगा, वरना हर सदस्य द्वारा काफी समय लिया जा सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) सर्विस कोऑपरेटिव के लिए कहा गया कि यह गुट की बात है मैं कहता हूँ कि यह तो नया स्लोगन दिया जा रहा है। एक बात यहां पर कहना चाहता हूँ कि मुझे ताज्जुब है कि आप बताएं कि कौन से गुट की बात है। मान लीजिए यदि हम यह मान भी लें तो यह हमें मानना पड़ेगा कि यह कांग्रेस की नीति का प्रभाव नहीं है। नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में

(श्री जनार्दनराय नागर)

पास हुए दो प्रस्ताव आज देश में वाद-विवाद का विषय बन रहे हैं। देश में काम करने वाले हज़ारों कार्यकर्त्ता नागपुर के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ऊंचे स्तरों पर विचारों की सफाई होना भी आरम्भ हो गया है। नागपुर के प्रस्तावों का विश्लेषण जितना हम कर सकते थे, उतना किया है। यह देश में एक इन-क्लाब पैदा करने वाले प्रस्ताव थे, यह सब ने एक जबान से माना है। अभी एक जगह मेरी एक कम्युनिस्ट मित्र से बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कांग्रेस ईमानदारी से काम कर सकेगी ?

(१·५ म० प०)

(श्री मनोहर कोठरी, सभापति, पदासीन)

मैंने कहा निश्चित रूप से। आज एक हलचल हो गई है...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : विनोबा भावे ने क्या कहा, याद है ?

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) जो इस प्रगति को रोकना चाहते हैं, मैं मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आज हलचल हो रही है और हम आपको हिलाना चाहते हैं क्योंकि आप सदियों से सोये हुए थे। हम चाहते हैं कि राजस्थान को दुनियां की दौड़ के साथ ले आएं। सच बात तो यह है कि हम सब खोई हुई वस्तु फिर पाना चाहते हैं। नागपुर के बारे में लोग कहते थे कि समाज-वादी समाज की बात कांग्रेस करती है लेकिन वह करना नहीं चाहती हैं। पर एक छोटा सा रेज़ोल्यूशन आया कि हम सर्विस कोऑपरे-टिव करना चाहते हैं, उस पर भी शंका होती है। मैं कहता हूँ कि अभी तो बहुत पानी चढ़ने वाला है। हम सर्विस कोऑपरेटिव को वहां तक लायेंगे कि जहां तक व्यक्तिगत सम्पत्ति देश में नहीं रहेगी। मुझे खुशी है कि आप उठे हैं, आपको नये अवतार का रूप देने का हमारा निश्चय है, लेकिन हम आपको करोड़ों और अरबों रुपयों का मुआ-वजा क्यों दें, यह सब इसलिए देते हैं कि आपने दो आत्मा के निर्माण में बड़ा काम किया है, हम मानते हैं इस चीज़ को। हिन्दुस्तान की ताकत को बनाये रखने में आपका बड़ा हिस्सा है। यही काम हैं, आपका यही पुन्य है जिसे कांग्रेस अपना फर्ज समझती है कि आपको भी इज्जत के साथ राजस्थान का एक सम्मानित नागरिक बनाकर रखा जाये। हमें और आपको दोनों को मिलकर राजस्थान को बनाना है। यदि समाजवादी समाज का प्रारम्भ जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा करना है तो आपके खून के लगने से समाज-वादी समाज होने वाला है। वह हमारे और आपके सम्मिलित प्रयत्नों से होगा। आपने अब तक समाजवादी व्यवस्था को रखने के लिए काफी खून दिया है, चित्तौड़ का क्षेत्र, उसका नमूना है। हमारी शिरोमणि महिलाओं ने जाने कितना खून दिया है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका और हमारा खून मिलकर एक साथ ही काम करें। यदि आप ऐसा नहीं सोचते तो हमें आपके विचारों पर शंका होती है। मैं यहां स्पष्ट कहना चाहता हूं क्योंकि हिन्दुस्तान के आस-पास चारों तरफ एशिया में डिक्टेटरशिप खड़ी होती चली जा रही है और उसका असर हमारे देश पर भी है और मैं भी कह सकता हूं कि इस देश के अन्दर जो मुआवज़ों से पची पचाई ताकतें हैं, उनके मनसूबे अभी गए नहीं हैं।

(श्री जनार्दनराय नागर)

इसलिए हमें मालूम है और हम सब इस खतरे से सावधान हैं। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में कुछ लोग डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं और आस पास ऐसा जाल भी बिछा रहे हैं, पर यह बातें होना इतनी सरल नहीं हैं। लेकिन एक बात है हिन्दुस्तान के अन्दर ताकतें मिलकर इस देशमें एक तरह की डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रही हैं, हम इससे सावधान हैं। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि अब सम्पत्ति के साथ सहकारिता का अस्तित्व कायम कर दिया जाये। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि चमकने की कोई बात नहीं है, चौंकने की बात नहीं है। यह तो युग के थपेड़े हैं जो लगते रहेंगे। यह लगते हैं तो हम तिलमिला कर रह जाते हैं। हम और आप इस देश के भविष्य की खाद हैं। हम में बदबू है, सड़ान है लेकिन निश्चित रूप से हम और आप सम्मिलित रूप से देश के लिए खाद हैं। इस पर देश की शक्ति निर्भर है, इस पर हमारे और आपके बच्चों का भविष्य निर्भर है। हिम्मत और साहस के साथ सहकारी समाजवादी समाज का शासन हम कायम कर दें, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए छोटी मोटी बातों पर न जाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र के मंगलाचरण का आरम्भ है।

अन्त में मैं कहना चाहता था कि हमने गये साल में कोई प्रगति नहीं की ऐसा कहा गया। लेकिन जो प्रगति की बात हमारे सामने आई उस पर ही विचार करें तो यह कहना पड़ेगा कि कोई न करें, क्योंकि कहना अच्छा नहीं, लगता तो दूसरी बात है या थोड़ी सी बात विचार कर के देखें तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान राज्य सरकार ने दो तीन सालों में काफी उन्नति की है। जैसा कि हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण से भी स्पष्ट है। इसमें दो वैगन फैक्टरियों की बात कही गई है एक भरतपुर और दूसरी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में ही एक डीज़ल लोकोमोटिव प्लान्ट स्थापित करने की सिफारिश की गई है उदयपुर और कोटा में टैक्सटाइल और नाइलोन फैक्टरी की बात आई, एक फर्टीलाइज़र फैक्टरी की बात आई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही गई है, वह है कि उदयपुर में बहुत जल्द जस्त गलाने का एक कारखाना (जिंक स्मेल्टर) खोला जायेगा। तांबे की खान की भी उम्मीद दिलाई गई है। करीब २०० से अधिक लघु उद्योग खुल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट का नक्शा बराबर विस्तार के साथ में लागू किया जारहा है, और खनिज़ों का, मैं समझता हूं, बराबर सर्वे शुरू हो गया है। इसको आप प्रगति न मानें तो यह आपकी इच्छा है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अब तक आज से दो साल पहले औद्योगिकता का कोई नाम हमारे सामने नहीं आया है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में हर तरफ हम एक-एक बड़े उद्योग की बात करते जा रहे हैं। यह क्या कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंक स्मेल्टर और ताम्बे के दो बड़े स्मेल्टर राजस्थान के अन्दर कायम होंगे। एक टैक्स्टाइल मिल उदयपुर में। एक नाइलोन की फैक्ट्री कोटा में खोल रहे हैं। सवाई माधोपुर के लिए हमारे राज्यपाल महोदय ने ठीक ही कहा है कि इन्जीनियरिंग कला के लिए, इन्जीनियरिंग के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख केन्द्र राजस्थान में होने वाला है। मैं समझता हूं कि चित्र आपके सामने कोई मालूम नहीं होता

(श्री जनार्दनराय नागर)

है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई चित्र नहीं है। जो उद्योग नीति इस चित्र के द्वारा हमारे समाने आ रही है जहां तक खनिज व्यवसाय का सवाल है, मैं समझता हूं इस देश का शिरोमणि प्रदेश राजस्थान है। इसलिए हमें राज्यपाल महोदय को इस इस मामले में निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमारे सामने राज्य सरकार के उन प्रयत्नों का जिक्र किया और उस चित्र को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में उसकी जमीन में से खनिज निकालना, राजस्थान की औद्योगिक क्षमता और औद्योगिक व्यवस्था के परिणामों को बढ़ाना राजस्थान की प्रगति के लिए बहुत अनिवार्य है। कृषि के विकास से ही राजस्थान आगे जायगा ऐसा में नहीं मानता हूं। कृषि के ऊपर भी साथ-साथ ध्यान देना चाहिए और उसको आगे ले जाना पड़ेगा, लेकिन सरकारी, समाज और समाजतन्त्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें औद्योगिक विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको ऐसा समझता हूं कि आने वाली तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर होगा। यह बात ठीक है कि अन्न के उत्पादन की दृष्टि से मैं यह मानता हूं कि तीसरी योजना के अन्दर विचार करना पड़ेगा। तीसरी योजना के सम्बन्ध में किस प्रकार की राज्य सरकार योजना बनाना चाहती है इसकी प्रक्रिया राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दी है। उस प्रक्रिया के बारे में मैं समझता हूं कि अभी कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, हर पंचायत से सलाह लेकर बनाई जाय। इसमें तहसील पंचायत तक की मर्यादा दी गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार मेरे इस सुझाव को मानने की कृपा करेगी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों से पूछकर काम किया जाय। वर्किंग ग्रुप्स के द्वारा विचार करें, लेकिन प्लान फेज़ को पूरा करने में हमें यह सोचना चाहिए कि पंचायतों से इस मामले में सलाह लें, क्योंकि, सभापति महोदय, हम आज की पंचायतों को न्यायालय बनाने जा रहे हैं। दो ढ़ाई हज़ार नई पंचायतें बनाकर, राजस्थान सरकार, विकास विभाग का सारा काम पंचायतों के जरिये हो तो मैं समझता हूं, एक बहुत ही समझदारी का तरीका होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के आधार पर जाकर बात करें, इसलिए मैं समझता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। मैं यह कहना चाहता था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस विस्तार और मिकदार से राजस्थान सरकार करने वाली है उसके बारे में कुछ सूचना हमारे सामने आयेगी, तो एक औद्योगिक आधार पर मैं समझता हूं हमारे विकास का चित्र आगे बढ़ सकता है। यह बात ठीक है कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से हमारी चिन्ता है, क्योंकि जो अनाज की कमी है और महंगाई बढ़ी हुई है राजस्थान में वह चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि जहां तक पैदावार का सवाल है, राजस्थान कमी का क्षेत्र नहीं है। राजस्थान से अनाज बम्बई और मध्यप्रदेश में जा रहा है चाहे रेल के द्वारा या ट्रक के द्वारा। राजस्थान में अन्न उत्पादन की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है। अन्न संग्रह और वितरण की समस्या उतनी नहीं है।

Page No.48

(श्री जनार्तनराय नागर)

किसान और बनियां दोनों में अनाज के संग्रह की प्रथा चल गई है, क्योंकि किसान और बीच का आदमी चाहता है कि कीमतें ऊंची हों, इसलिए अनाज को वह बाजार में लाना नहीं चाहता। यह बात साफ है कि मंडियों में अनाज की कमी है। अब ऐसा समय आ चुका है कि राज्य सरकार को साहस के साथ में कदम लेना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय ने स्टेट ट्रेडिंग का जो ज़िक्र किया है कि राज्य सरकार का साफ निश्चय है। यही एक रास्ता है। अन्न की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं उन कीमतों का रोकने का और कोई जरिया नहीं है। सिवाय इसके कि राज्य अन्न का व्यापार अपने हाथ में ले ले। लेकिन इसके लिए यह कहा गया कि थोक व्यापार रहेगा तो भ्रष्टाचार फैलेगा। लेवी जैसी हालत हो जायगी। लेवी और स्टेट ट्रेडिंग में भेद करने की आवश्यकता है। क्योंकि लेवी हो चुकी है इसलिए समझते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग भी लेवी है। नाम बदल लिया गया है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में सैकड़ों नाम नहीं होते हैं। यह लेवी नहीं है। मैं कहता हूं कि यह स्टेट ट्रेडिंग है। जिस प्रकार से स्टेट ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइजेशन किया जाना चाहिए, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि अन्न का व्यापार भी स्टेट करे। उसका भी एक प्रकार का स्टेट ट्रेडिंग के ज़रिये से सारा संचालन हम करना चाहते हैं। वह इसलिए करना चाहते हैं कि किसानों में अधिक उत्पादन की क्षमता को बनाये रखा जाय। यह कहा गया है कि इससे किसान की उत्पादन क्षमता पर असर होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान आज बड़ा दुखी है। दुःखी इस बात से है कि जब बोने का समय होता है तो बीज मंहगे रूप में दिया जाता है, लेकिन जब फसल आती है तो सस्ते भाव से लिया जाता है। बीच के लोग सारे अनाज को अदृश्य कर देते हैं और मंडियों में अनाज नहीं मिलता है। ३४)३५) रु० का जयपुर में भाव है और २८) २६) का उदयपुर में है। यह अनाज की मंहगाई है। उसकी वजह से समाज के निम्न श्रेणी के जो लोग रहते हैं वे बहुत दुखी हैं। बहुत परेशान हैं इसलिए राज्य सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कार्यवाही शुरू की है। दूसरी ओर हम भारत सरकार की खाद्य नीति की वजह से एक मर्यादा में बन्धे हुए थे, इसलिए जितना जल्दी यह कदम लेना चाहिए था, वह नहीं ले पाये हैं। नहीं ले पाने से जो नुकसान होने वाला था, वह हो गया। ज्यादा आगे नही होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अनाज की मंहगाई बहुत बढ़ी है। राजस्थान सरकार को उसको कम करना चाहिए। उसमें जल्दी का रास्ता क्या है। रास्ता केवल यही है कि अनाज के व्यापार को राज्य अपने हाथ में लें, और किसानों से ठीक मूल्य पर खरीद कर सही दामों पर राज्य की दुकानों पर बेचें। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर आज जो कहते हैं कि केवल भ्रष्टाचार फैलाने का जरिया है। इसका कोई इलाज नहीं है। सिवाय इसके कि मंहगाई और कीमतों का मुकाबला करना। आज संविधान के जरिये आपके पास में कोई नियम और अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार किसी को व्यापार नहीं करने दे। जब एक ही तरह के लोगों को व्यापार नहीं करने दिया जाता तो यह अखिल भारतीय दृष्टि से अखिल भारतीय नीति है, राज्य सरकार

(श्री जनार्दनराय नागर)

व्यापार की नीति राज्य में लागू करती है आज उस नीति में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य सरकार व्यापार करना शुरू करेगी। सैद्धान्तिक रूप से ऐतराज हो सकता है कुछ लोगों को जो व्यक्तिवादी हैं वे कह सकते हैं कि राज्य सरकार व्यापार क्यों करे लेकिन यह तो जमाना बदल रहा है, पुराना जा रहा है, पुराने मुर्दे जल चुके हैं और उनकी भस्मी हवा में उड़ चुकी है। समाज ने जिन लोगों को प्रिय समझ कर, भगवान की तरह अवतरित समझ कर पूजा है और जिन्होंने सैकड़ों लाखों लोगों को कुचला है उनकी राख हो चुकी है और सारी भस्मी उड़ चुकी है। अब जो युग आया है वह दूसरा ही है इसमें स्टेट ट्रेडिंग का युग है, ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइज़ेशन होगा, कम्युन बनेंगे। यदि हमारा वश चला तो हम इन्हें जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं लेकिन करें क्या हमारे रास्ते में गड्ढे हैं, खंदक हैं...

श्री मदनसिंह : भ्रष्टाचार है।

श्री जनार्दनराय नागर : सबको प्रेम और सत्य से साथ लेकर चलने की कांग्रेस की नीति है। इसी वजह से बहुत सी बातें हमको सहनी पड़ती हैं। लेकिन यदि दूसरा तरीका अपनाया गया तो कांग्रेस शायद इसे पूरा न करे। लेकिन जो दूसरी ताकतें पैदा हो रही हैं, जमाना तेजी से बदल रहा है। लेकिन दुःख यह है कि मेरे मित्र अनुभवी हैं, समाज में चलते फिरते हैं, होशियार हैं कई उथल पुथल उन्होंने की हैं वे यह क्यों नहीं समझते कि जमाना बदल गया है। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने इन नीतियों का खाका खींचा है जिससे लोग जमाने का बदलना महसूस करें और जो कदम आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ता हुआ देखें। शिकायत तो राजतन्त्र और व्यक्तिवाद की थी। मैं कहा करता हूं कि कांग्रेस ब्युरोक्रेसी के घोड़े पर बैठी है। मैं समझता हूं राजतन्त्र में से ब्युरोक्रेसी को दूर करना जरूरी है। हम जब शक्ति का विकेन्द्रीकरण जिला समितियों और पंचायत समितियों से करना चाहते हैं तब भी यह बात मेरे मित्र के समझ में नहीं आती कहते हैं भ्रष्टाचार और गड़बड़ी में जा रहे हैं। यह उनकी समझ का ही फेर है।

श्री अध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

१.२३ म० प०

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Chairman, Sir, year after year we hear that the law and order situation in the State improves or remains satisfactory. Due to the lack of figures, it is difficult to know, Sir, how much the State affairs has improved or remained satisfactory. I have noted, Sir, during the past seven of my time in this House that from every side voices are raised against the attrocities, inefficiency and corruption of the Police Department. Thefts and dacoties take place, Sir, and all such crimesas are heard of. Six thefts took place in one night in one muhalla in Bharatpur City. A dacoity last week took place, Sir, on the main Bharatpur-Deeg road at village Babuna which is only one mile from Kumher. On the Udaipur National Highway, two buses and one jeep were looted in the

Page No.50

(राजा श्री मानसिंह)

broad day light. These are the few examples which I mention and with these examples, I would like to know, Sir, how the situation remains satisfactory or improved ? There has been mention in the Governor's address that certain officers and men have been awarded for the gallantary actions against decoities etc. However I am surprised to know that the Government has made no mention of the gallantary actions of Junior Deputy Superintendant of Police, namely Mr. Ohi, who, so very gallantary, ordered lathi-charges on the citizens of Bharatpur during last December, The Government has made no efforts whatever to Justifg or condemn the action of the officers by holding any enquiry into the matter. The accused persons have been beaten and mal treated in the Bharatpur District Jail because they have affiliations with Political parties, that oppose the congress. On medical examination by the Jail Doctor one man-namely Shri surajbhan received 19 injuries on his body. These socialists were injured by sharp and blunt weapons on the delicate parts of their bodies. It is a shame, Sir, that after 11 years of congress regime, this sort of affairs should remain. I think, even those, who are sitting in this house and who fought for the freedom of the country never received this sort of treatment even from the British. The Food situation, Sir, in our State is critical, and it still remains critical. Rajasthan is normally a surplus productive area but our food policy is defective because it is wrongly assessed, because grain is smuggled out of the State because of natural calamities and sometime scrop-failures. Rajasthan is a big province and every year some part or the other of the province suffers from natural calamities and the Government should have made it their business to see that in cases of any calamity that may occur in our State sufficient stock of food-grains should remain in our State. I have come to know, Sir, that surplus wheat stocks have been found on Bombay road and imported wheat which was unloaded at Bombay was supplied to us. It is obvious, Sir, to any layman to see that the Government has failed fo insist on the neighbouring Governments that imported wheat stocks should have been used in the deficit areas of Bombay and wheat should not go out of our State and should remain for our own use. This mis-management of affairs, Sir, has led to the utilisation of the transport facilities in importing grains instead of using it for more productive commodity. The Government, Sir, has been unable to take stepe effectively to check the smuggling of food grains even from the deficit areas of Rajasthan. I mention as an example that 68 thousand of bags were imported to Bharatpur from Madhya Pradesh and whole of which was smuggled out to U. P. There is no machinery or whatever to stop this smuggling. The law is not effective.

Page No.51

(राजा श्री मानसिंह)

We are told, Sir, in the Governor's Address that last year Rajasthan sufferred due to rain failure. This may be a fact in the western Rajasthan but in Eastern Rajasthan it was only due to heavy rain-fall. But it was not mentioned in the address. The floods in Bharatpur District are caused by two factors. One by heavy rains over which we have no control and secondly mis-management in the course of irrigation in Bharatpur District. The Executive Engineer Irrigation who is incharge of the management of the irrigation system in the Bharatpur District has several qualifications. I understand, he has a Matriculation Certificate. He has also Overseers Training Certificate and about28 years of service and lastly he has the qualification of political affiliaton. He is not at all a trained Engineer. Works have been executed on the proposal of this officer only on political grounds so much so that the welfare of the people is in danger and the irrigation system has been over-taxed. So many irrigation works are taken to ensure the success in election of the former Rajasthan Ministry. I think, not even one pie of public funp has been spent during the last five years on the Girraj irrigation canal, which is very important from the point of flood control.

It is really extraordinary, Sir, that this highly qualified engineer ordered at the critical time of floods in Bharatpur that the headway of Gir-Raj Canal should be closed and the excessive water should be allowed to flow across the Bharatpur-Mathura road and across the Bharatpur-Agra railway line, causing great hardship and damage to property, both of the people and the Government. I showed this to one of the Cabinet Ministers, Shri Badri PrasadJi when he visited Bharatpur at that time.

Regarding flood relief, Sir, I would like to mention a few things. Some relief was given by the Government during the floods in 1956, but this was when the floods were much more severe. I would like to give you an idea of the relief given by the Government to the people. In the eight villages of Bayana Tehsil that were affected by the floods during the flood period, the Government gave one tin of kerosine oil, 20 seers of Atta and seven bwndles of (bidies). We are told now that the Government has spent 10 lakhs of rupees in giving flood relief after the elections. We would like to know, Sir, how much has been given to Bharatpur and how and where ? The greatest relief of course that can be given to Bharatpur would be to transfer this Executive Engineer of the Irrigation Department.

I do not like to speak against Government officers, but the welfare of six lakhs of the people of district is at stake.

I have been pressing, Sir, that no

(राजा श्री मानसिंह)

irrigation charges should be lived in the flood affected areas. I have been pressing that no land revenue should be leired in the flood affected area and also I have been pressing for the postponement of the realisation of taccavi loans, but my suggestion unfortunately has fallen on deaf ears.

I would like to mention, Sir, the inefficient working of the office of the Executive Engineer of Irrigation Department. That office should be located at Bharatpur and not at Alwar. This would not only lead to saving in public funds but is bound to lead to satisfaction. In Bharatpur District we have the largest amount of irrigation being carried out, probably 2½ lakhs acres of land is irrigated in Bharatpur District of which 35,000 acres are irrigated at present in Dholpur. When the Parvati Project is complete, this irrigation figures of Dholpur will increase. While in Alwar, Sir, only 20,000 acres of land are irrigated. But at present, because of politics, the office of the Exeutive Engineer, Irrigation is at Alwar. On the question of land revenue, Sir, I may say that on the one hand the Governor mentions that in most parts of the State, holdings are small and un-economic and, on the other hand, through the 6th Amendment of the Rajasthan Tenancy Act, which is better known as the Ceilings Bill, we propose to make other holdings small and un-economic. I have opposed the ceilings on land over and over again with facts and figures, but the ceilings are bound to come because according to the National Development Council resolution, by the end of the 2nd Five Year Plan, co-operative membership is to be doubled and by the end of the Third Five Year Plan, every farmer in the village is to be a member. This can only be done by creating through ceilings more un-economic holdings so that the farmer will be compelled to go and get Government aid through co-operatives. It is necessary here, Sir, to view the position of our co-operative societies as they exist today. I understand that at present there are 11000 co-operative societies in Rajasthan many of which are bogus. The total membership at present is 4.25 lakhs of which 3.50 lakhs are agriculturist due to the lack of staff, gross mis-management takes place in these societies. There is no proper supervision, no proper inspections and no proper audit. I have come to know that Government will try to improve this situation next year.

Then again, Sir, it is interesting to look at the Rural Credit Survey Report 1956 made by the Reserve Bank of India in which it says that co-operatives have failed in India but must be made to succeed. These are the words contained in that report. Other interesting facts that are contained in the report are that upto the beginning of the second Five Year Plan only 3% of the credit require-

(राजा श्री मानसिंह)

ments of the farmers were meet through co-operatives. Another 3% of the credit requirements of farmers were meet by Government loans. At this period of the second Five Year Plan, the ratio has risen upto 7½%. That means that through Government aid only 11% of credit requirements are being meet today and the farmer has to go for the rest elsewhere. This is the state of affairs after 50 years of the working of the co-operatives movement which was started, I think, in 1904.

We are told in the Governor's address that loans advanced to Co-operatives have increased from Rs.4.4 crores to Rs. 7.73 crores. We should remember, Sir, that all these loans are short term loans which are repayable within one year. Now it is proposed to give medium and long term loans repayable in five or 20 years respectively through land mortgage banks. Once the farmer takes loan from land mortgage banks on his un-economic holding, it is next to impossible that he will be able to redeem his land after paying back the loans and at the same time meet his normal requirements. This will mean that through co-operatives the Government will control all agricultural land sooner or later. On the other hand, Sir, the Government will loose its income from agricultural income tax and as such, I feel that they will have to increase land revenue and levy other taxes on agriculturists to meet their requirements. The Congress has relinquished the policy of socialistic pattern of society and is moving towords communistic pattern of society. Co-operatives working in other spheres have also not proved successful as so many of them are under liquidation. Co-operative farming, Sir, may be successful in China where there is different form of Government but in the democratic form of Government in India, I feel it doubtful whether co-operatives will be successful here. However, one thing is certaih; that food production will not be increased by co-operative farming, as there will be lack of interest of the individuals. Due to the great illiteracy amongst our farmers, Sir, they will be exploited by those controlling and keeping the accounts of the societies. I have here, Sir, the English translation of the Governor's address from which I would like to quote a paragraph:—

"In most part of the State the holdings are small and un-economic. Revitalisation and establishment of service co-operatives followed by co-operative farming societies is, therefore, inevitable for optimum production. It has, therefore, been decided to cover the State with service Co-operatives within the shortest possible time."

It is obvious from these words, Sir, and as my friend from across the floor has just told that the Congress wish to regiment the agriculturists

(श्री राजा मानसिंह)

through Co-operatives as a step towards collective farming on the Russian lines. If Co-operatives are to be tried at all, Sir, the Government should have made an effort to put small-scale industries under Co-operative societies. We have been told, Sir, that more than 200 units of small scale industries have already come up. 200 capitalists or individuals have been accommodated, this is what it means. If small-scale industries had been given over to the Co-operative societies. which the capitalists do not want, then perhaps over 3,000 families would have been grateful.

There has been mention, Sir, in the address regarding Decentralisation of Power. According to the recommendations in the Balwant Rai Mehta Committee Report, the Government wish to constitute zila Parishads at district level and Panchayat Samitties at the block or tehsil level, whose functions will be in the words of the Governmor:-

"The functions of the popular bodies should include general administration and development of the area other than functions of law and order and administration of justice." This means that these bodies will have no power at all. Further to emphasise my point, Sir, I again quote from the address:—"The Zila Parishad will mainly be a co-ordinating and advisory body." The policy of the Government, Sir, is not to Decentralise Power but to centralise it, as these bodies will function under the chairmanship of the Collectors and the S. D. O. s

Favouritism and communalism continues to be rampant in the administration, Sir. Appointments and promotions are made, not on any sound basis of seniority and qualifications. Due to favouritism and communalism the right claimants are often by-passed. A clear example of this, Sir, is in the Industries Department where non-technical R. A. S. and I. A. S. officers have been appointed on technical posts. Selection to the R. A. S. is made on the same basis. In the reorganisation of the Panchayat Department, a Board selected some persons from Tehsildars and Naib Tehsildars for the posts of District Panchayat Officers. The appointments orders have been held up because from amongst the persons who have been selected, 4 persons belong to Bharatpur of which ae there is no representation in the Cabinet, and besides two or three favourites of Ministers were left out as they were not considered competent enough to be selected. Ways are now devised how to accommodate these favourites and how to drop the competent officers from Bharatpur. The Hon'ble Governor....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : Let me inform my friend that there was no Selection Committee and their names were only sent by the

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

Chairman, Revenue Board, and what he is saying is incorrect.

राजा श्री मानसिंह : (जारी) Sir, the information given by the Minister does not agree with the information that I have got, which says that a Board consisting of the Chairman, Board of Revenue, Director of Panchayats and the Secretary for Local Self Government selected the persons.

The Hon. Governor has been very tactful in not mentioning the work of the Anti Corruption Department because no work has been done there. Great hopes were raised two years ago when the Rajasthan Government appointed a special I. G. P. to take up this work. But we have seen that inspite of many complaints no action has been taken by the Department. I feel Sir, that the Government is not really keen enough to root out corruption from the administration which has shown no decline during the past number of years. As such, I would like to make a suggestion that if corruption has to continue, atleast the public funds should not be wasted on the Anti Corruption Department and on the salary of the Special I. G. P. who does not do any work.

Finally, Sir, I oppose this motion of thanks on the Governor's address as I do not agree with the policy that the Government wish to follow in the future.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस धन्यवाद के प्रस्ताव के लिये विशेष बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में अगर हम देखे . . .

श्री श्रीमानसिंह : There was no mention of Farmers' Forum in that.

श्री मोतीलाल चौधरी : I don't mind that.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a point of information, Sir, राज्यपाल महोदय के इस भाषण पर बहुत बोलने वाले हैं। कल तक ही इस पर बहस होगी। इसलिये यदि टाइम लिमिट मुकर्रर कर दिया जावे तो उचित रहेगा।

श्री सभापति : अभी समय नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : (जारी) दो हिस्से हैं। एक, पिछले साल के अन्दर सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं और सफलता मिली है उसके लिए धन्यवाद दिया गया है और दूसरा हिस्सा वह है कि हमारी स्टेट में आगे व्यवस्था कैसी होगी, उसमें उसका आभास है। अभिभाषण में, सही रूप से हम देखें तो यह है कि इसके अन्दर समाज को नया रूप देने के लिए कहा गया है, जिसके लिए हम बहुत समय से इन्तजार कर रहे थे, आज़ादी के पहले से जिसके लिए इन्तज़ार कर रहे थे कि हमारे देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा क्या होगा ? देश के आज़ाद हो जाने के बाद राजनैतिक स्वतन्त्रता तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए बिना जनतन्त्रीय स्वरूप नहीं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

रहता। उसके बाद ही हमारे यहां सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। चूंकि आज के इस अभिभाषण में उसका उल्लेख है इसलिए राज्यपाल महोदय उसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

जिस विषय को लेकर समाज की नयी रचना होगी, खास करके दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और उनके साथ बैठे हुए माननीय सदस्य जो इस समय उपस्थिति नहीं हैं, उन्होंने इस ओर इंगित किया था और खास कर ज्वाइन्ट फार्मिंग के बारे में मेरे ख्याल से ज्वाइन्ट फार्मिंग क्या है? उनको खुद को ही पता नहीं है और इसलिए उनको संदेह हो रहा है। अतः सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्वाइन्ट फार्मिंग क्या है?

श्री मदनसिंह : आप चीन पधारते।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं अमेरिका और यूरोप गया हूं।

ठा० श्री मदनसिंह : आपसे ज्यादा मैं भी गया हूं।

श्री श्रीभानसिंह : I may inform both the Hon'ble members that it is not a qualification.

श्री मोतीलाल चौधरी : विदेश जाना कोई बात नहीं है।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : That may not be a qualification for you but that may be for them.

श्री मोतीलाल चौधरी : It may not be but we have been. जिस विषय को लेकर चर्चा चल रही थी उसमें खासकर यह बताया गया कि क्लैक्टिव फार्मिंग होने से कम्युनिज़्म आवेगा। उसमें यह साफ है कि को-ऑपरेटिव फार्मिंग में प्रत्येके किसान का हिस्सा है।

श्री मदनसिंह : But you oppose Communism ?

श्री मोतीलाल चौधरी : Hear me First. Yes, oppose it.

(हंसी)

इसके अन्दर स्पष्ट है कि कृषकों के क्या अधिकार रहेंगे। किसानों की बात को लेकर जितनी चर्चा उन्होंने की, राजस्थान में सब को मालूम है कि वे क्या हैं? उन्होंने किसानों की हमदर्दी की बातें कहीं, खुद क्या हमदर्दी करेंगे जो उनके साथ ज्यादतियां करते रहे हैं, वे जानते हैं...

श्री मदनसिंह : हमने तो किसानों को बसाया।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपने किसानों को रुलाया है, किसानों को ही नहीं भूस्वामियों को भी रुलाया है, लड़ाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री मोतीलाल चौधरी : उनकी जो स्थिति थी वह यह थी कि जब जागीरें जा रही थीं तो उनके घर पर मीटिंगें होती थीं कि कैसे जागीरों को बचाया जाय, लेकिन वे बची नहीं। पुलिस के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे १० आदमी दे दिये

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जांय तो सब डाकुओं को ठीक कर दूँगा और कर सकता हूं। हजारों भोमियों को लेकर आये थे वे दिन भी न रहे, जागीरों के वक्त में कितने डाके पड़े थे, वे भी नहीं सम्भाले गये, मैं नहीं कह सकता कि वे कन्ट्रोल करते हैं, डाकुओं से उनकी सांठ होगी और उससे कन्ट्रोल करते होंगे, इतिहास कहता है, कुचामन में ट्रेनिंग दी गई थी, डाबड़ा कान्ड में भी थे...

श्री मदनसिंह : उस समय में ईजिप्ट में था।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं भी जानता हूं, जनता भी जानती है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, इस तरह पर्सनल आक्षेप नहीं होने चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : उस क्षेत्र में किस तरह से लोगों को तकलीफ थी और किस तरह से जागीरें गईं यह उनका जी जानता है। वे नहीं तो उनके दूसरे भाई, विदेशों में पूंजी ले जाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और स्विटज़रलैंड में किस प्रकार से पूंजी हिन्दुस्तान से ले जाई जाय। जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं, वह सुन्दर नहीं है।

श्री मदनसिंह : मेरे पास तो पैसा नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपको यह कहूंगा कि ज्वाइन्ट फार्मिंग, को-ऑपरेटिव फार्मिंग में किसानों का राइट है उसमें तरमीम नहीं होने की है। को-ऑपरेटिव फार्मिंग प्राय: सब देशों में थोड़ी-थोड़ी है। जिस देश का आप ज़िक्र करते हैं, उसकी नीति का समर्थन करते हैं वहां को-ऑपरेटिव फार्मिंग है। इज़राइल को ही देखिये, को-ऑपरेटिव फार्मिंग के द्वारा ही उसने काफी उन्नति कर ली है।

इसके बाद मैं आपको कलेक्टिव फार्मिंग की बात करता हूं वह भी को-ऑपरेटिव फार्मिंग की तरह है। कलेक्टिव फार्मिंग में किसान को हक नहीं रहता है। लेकिन को-ऑपरेटिव फार्मिंग में किसान को हक रहता है। ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी में किसका अधिकार है, किस दृष्टिकोण से चलती है? यह कलेक्टिव फार्मिंग और को-ऑपरेटिव फार्मिंग के बीच का हिस्सा है। कलेक्टिव फार्मिंग पूंजी वालों के पास रहता है। ज्वाइन्ट फार्मिंग में किसानों का हिस्सा रहेगा, काम करने वालों का हिस्सा रहेगा। किसान की जितनी जमीन, जितने अधिकार उसके हैं, उसका हिस्सा उसको मिलेगा। शोषण की स्थिति उसमें नहीं रहेगी जब शोषण की स्थिति नहीं रहेगी तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में को-ऑपरेटिव फार्मिंग लाभदायक नहीं होगा। नागपुर अधिवेशन में और जहां-जहां इसका स्पष्टीकरण किया गया है, वहां कहा गया है कि यह ओपश्नल है और कम्पलसरी नहीं है। हो सकता है कि इसको रोकने के लिए रोड़े भी आवेंगे लेकिन जिन्होंने इस नीति को निश्चित कर लिया है वे अब रुकने वाले नहीं है और वह लागू होगी।

अमेरिका को ही ले लीजिये जिसके लिए आप बहुत उत्सुक हैं सुनने को। वहां पर को-ऑपरेटिव पर ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स

(श्री मोतीलाल चौधरी)

निर्भर होती है काश्तकारों को जितनी बिजली मिलती है उसमें ६५ पर्सेन्ट को-ऑपरेटिव्ज़ को हैं, टेलीफोन ८५ को-ऑपरेटिव कोऑपरेटिव्ज़ को हैं, फ्रूट तो बिना को-ऑपरेटिव के नहीं मिलते केलिफोरनिया स्टेट में तो फ्रूट का एशोसियेशन है। इसके आलावा मार्केट के अन्दर फ्रूट नहीं मिल सकता, बिना सहकारी-समिति के।

इसी तरह से मैं आपको अमेरिका का उदाहरण दूँ अमेरिका के अन्दर एक स्टेट है जिसके साथ राजस्थान का टेक्निकल ट्रेनिंग से सम्बन्ध है। उस स्टेट के अन्दर जिस स्टेट के साथ हमारे राजस्थान की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये ट्रीटी है They are handled through Co-operative farming Saving effected through the Co-operative farming in them. They have spent more money and improved standard of living. जिस देश, अमेरिका में इन्डिवीज्युअल फार्मिंग, है उसमें जितना भी सामान बिकता है उस सारे में ६० प्रतिशत कोऑपरेटिव फार्मिंग द्वारा बिकता है। वहां केवल बारह पर्सेंट किसान हैं। वहां जो भी प्रोडक्शन बढ़ा है वह सहकारिता के आधार पर बढ़ा है। वहां पर भी किसानों के दो संगठन है जैसी स्थिति हमारे यहां है, वैसी स्थिति वहां पर भी है। जैसे यहां बड़े जागीरदार और किसान सीलिंग से डरते हैं वहां भी ऐसे किसान और पूंजीपतियों का संगठन है। एक संगठन है जो बड़े-बड़े फार्मर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा संगठन है छोटे-छोटे किसानों का जिनका कोऑपरेटिव फार्मिंग दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। उसके अन्दर सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि अन्य व्यापार भी इस सहकारिता के आधार पर बीस पच्चीस प्रतिशत बढ़ रहा है।

दूसरा देश है, हॉलैन्ड जिसने सहकारिता के आधार पर ही उस देश के ढांचे को बदल दिया है। आज जिस चीज को अमेरिका कर नहीं पाया है उसको हॉलैन्ड ने कर दिखाया है। वहां जो नेशनल इन्कम है उसका हिस्सा प्रत्येक को बराबर मिलता है। वहां पर ८५ से लेकर ६० प्रतिशत तक एग्रीकल्चर या मील प्रोडक्ट हो वह सब कोऑपरेटिव बेसिस पर होता है। वहां की शुगर फैक्टरीज़, ६५ प्रतिशत कोऑपरेटिव के अन्दर में है। उस देश का अपना सारा ढांचा कोऑपरेटिव बेसिस पर निर्माण किया गया है।

आज पूंजीपति द्वारा गरीब के शोषण को समाप्त करने के लिये सहकारिता की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनीज़ जिन-जिन देशों में है वहां के लोग भी कोऑपरेटिव प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी और सहकारिता में इतना फर्क है जितना एक पूंजीपति और गरीब में। आज पूंजीपति ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी में पैसा लगाते हैं उससे वे जितना मुनाफा चाहे कमा सकते हैं लेकिन कोऑपरेटिव व्यवस्था में मुनाफा दस प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकते। ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी में शोषण चाहे जितना कर सकते हैं सहकारिता में यह बात नहीं है। अगर हमारे देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू होता है तो देश के किसानों की दो दिक्कतें मिट जायेंगी। सब से पहली दिक्कत समय पर बीज मिल जाना चाहिये वह आसानी से प्राप्त हो सकेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि आज जागीरदार

(श्री मोतीलाल चौधरी)

लोग अब भी जबरदस्ती किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर देते हैं वह उसमें नहीं हो सकेगा। आज जो बेदखल करने की धमकियां देते हैं, वह नहीं दे सकेंगे। ऐसी स्थिति में दो दिक्कतों से किसान मुक्त हो जायेंगे। इसके अलावा, सभापति महोदय, एक चीज़ की ओर मैं सदन का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह कि जहां आप सर्विस में कोऑपरेटिव प्रणाली को महत्व दे रहे हैं वहां इस व्यवस्था के बाद में ज्वाइन्ट फार्मिंग की ओर स्टेप लिया जाय। जमीन का सीलिंग फिक्स हो जाने के बाद में जो जमीन बची रहेगी उसका क्या होगा, उसको किस तरह से बांटा जायगा ? इस बारे में सरकार ने एक समिति बनायी है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि वह जमीन कलेक्टिव फार्मिंग के लिये दे दी जाय, यह सुविधाजनक होगा। कलेक्टिव फार्मिंग में इनडिवीज्युअल का सवाल नहीं रहता। जो आदमी उसका मेम्बर रहेगा उन सब का राइट उस पर रहेगा। आज हम देखते हैं रेगिस्तान में कोऑपरेटिव बेसिस पर ही फार्मिंग हो रहा है हॉलांकि इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। रेगिस्तान के अन्दर एक कुंआ होता है, वह बहुत गहरा होता है उसके अन्दर से पानी निकालने के लिये ६ और आठ-आठ बैलों की आवश्यकता होती है, वहां एक काश्तकार खेती नहीं कर सकता। इसलिये ग्यारह बारह परिवार मिल कर खेती करते हैं। हमारे नागोर में भी यही हाल है वहां एक परिवार खेती नहीं कर सकता दो-चार मिल कर खेती करते हैं। वहां भी दो-चार परिवार मिले बिना खेती नहीं कर सकते...

श्री मदनसिंह : तो उनको आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी : हम डिस्टर्ब कहां कर रहे हैं, हम तो उनको जमा रहे हैं ११ आदमी मिल करके खेती कर सकें इस प्रकार राज्यपाल महोदय ने सहकारी ढंग पर कृषि करने की ओर कदम बढ़ाया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं राज्यपाल महोदय ने ज्वाइन्ट फार्मिंग का ज़िक्र अपने अभिभाषण में करके काश्तकार को शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह सबसे ऊंची बधाई की बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराट) : माननीय सभापति महोदय,

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी : इसके बाद सभापति महोदय, एक बात आती है स्टेट ट्रेडिंग की। यह जरूरी है उचित मूल्य पर समय पर काश्तकार को और कन्ज्युमर को सामान की उपलब्धि कराने के हिसाब से। बहुत सीधी सी बात है। जो पैदा करता है, उसको समय पर उचित मूल्य अपने माल का मिल जावे और जो खरीददार है उसको समय पर और उचित मूल्य पर वस्तु मिल जावे। देश में ६० प्रतिशत किसान मज़दूर हैं। दस प्रतिशत से भी कम वे लोग हैं जो पैसा रखते हैं और माल होर्ड कर सकते हैं और जो ६० प्रतिशत का शोषण करते हैं, जिसमें कन्ज्युमर हैं और किसान दोनों हैं जिनके पास पैसा नहीं होने से रोज-रोज माल बेचना और खरीदना होता है। तो आज जो स्टेट ट्रेडिंग का विरोध करने वाले, इस थोड़े से पर्सेंटेज़ के तबके

(श्री मोतीलाल चौधरी)

के लोग हैं। यह एक सीधी सी बात है। वे थोड़े से लोग होर्ड करके मुनाफा ही नहीं कमाते, आढ़त और धर्मादा लेते हैं और धर्मादा लेकर ट्रस्ट बनाकर उनको अपने नाम करके सारा लाभ उठाते हैं। उनका यह शोषण बन्द हो जावेगा। इसलिये उनका विरोध करना तो स्वाभाविक है।

इसके बाद है महत्वपूर्ण बात सत्ता का विकेन्द्रीकरण। आज भी विकास खण्डों के स्तर पर हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और करना चाहिये भी। आज जागीरदार सदस्य यह कहते हैं कि सारी सत्ता जयपुर में ला कर रख दी जानी चाहिये, इसे नौकरशाही के लोग भी चाहते हैं। जागीरदार लोगों ने और इस नौकरशाही के लोगों ने गांवों में जो जाट, गूजर, भांमी, थोरी आदि तबके के लोगों को डाट रक्खा था, दबा रक्खा था, आज वे इस युग में सरपंच और पंच बनकर अपना सिर ऊंचा उठाते जा रहे हैं, उनसे आज वे घबरा रहे हैं। पर डेमोक्रेसी का तकाज़ा है कि सब को समान अधिकार हो। वह आज हो रहा है। इस दृष्टि से किसी भी गांव में और शहर में बड़े से बड़े पूंजीपति, लखपति, करोड़पति या बड़े से बड़े आदमी, जागीरदार या नौकरशाही के पुर्जे की भी आज वही ताकत है, जो एक मामूली से किसान और मजदूर को हांसिल है। आज दोनों की वोट की शक्ति बराबर है। समान न्याय हो गया है। इससे वे घबराते हैं। उनको डर है कि तहसील पंचायतों और ग्राम पंचायतों और जिला स्तर पर अगर शक्ति चली गई तो उनको शक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति उन साधारण किसान और मजदूर लोगों के हाथ में चली जावेगी। इससे वे डरते हैं। यह स्पष्ट है कि आज आजादी की शक्ति सब जगह केन्द्रीकरण में सर्विस क्लास के लोगों को अधिक मिली है। आज भी सत्ता उनके हाथ में है, पहले भी थी, पर अब परिवर्तन आ रहा है, इससे वे घबराने लगे हैं। इस सर्विस क्लास की शक्ति कम होगी और आम जनता को वह शक्ति अब मिलेगी। उदाहरण देते हैं, वे कभी डेगाना की या भीलवाड़ा की। डेगाना, भीलवाड़ा, लाडनूं आदि सभी जगह आपने चुनाव में देखा तो है। पंचायतों ने एक दो ने कोई गलत फैसला कर दिया तो कौनसी बड़ी बात कर दी, हाई कोर्ट और कोर्ट भी तो गलत फैसले कर देते हैं। सिलेक्शन बोर्डों में गलतियां होती हैं। आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के सिलेक्शनों में भी तो गलतियां होती हैं। क्या इन बड़े कहलाने वालों ने गलतियां नहीं कीं, इन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं जिसके कारण इनके राज्य और जागीरें तक चली गई हैं। इस स्थिति में उनको आज शक्ति का उनके पास जाना बुरा लगता है क्योंकि वे उनके सामने जाकर अब टिकने में हल्कापन महसूस करते हैं।

श्री मदनसिंह : इसीलिये चुन कर वे यहां भेजते हैं हमको।

श्री मोतीलाल चौधरी (जारी) : इसीलिये हम आये थे और जागीरें ले लीं।

(हंसी)

इसके बाद माननीय सभापति महोदय, लॉ और ऑर्डर की बात कही गई। प्रथम चुनाव जब हुआ था और हम यहां आये थे तो स्थिति काफी खराब थी, यह हम सब

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जानते हैं, पर आज वह कन्ट्रोल में है। पुलिस ने आज यही नहीं किया कि इन डकैतियों को कन्ट्रोल किया हो, उसने दूसरे आन्दोलनों को भी कन्ट्रोल किया है। भूस्वामियों के आन्दोलन को कन्ट्रोल किया है, उनके नेता को भी कन्ट्रोल किया है। भूस्वामियों ने गड़बड़ी की थी बड़े—बड़े नारे लगाये थे, हम राज लेकर छोड़ेंगे, वह करके छोड़ेंगे और उस समय ये नेता दाढ़ी लगाते थे। आज दाढ़ी साफ करके आते हैं। उनको भी पुलिस ने ठीक किया था। तो इसलिये वह जो कहना था कि पुलिस ने कन्ट्रोल नहीं किया, गलत है। पुलिस इस लॉ और ऑर्डर के लिये आज बधाई के पात्र हैं।

साथ—साथ हमारे दूसरे डवेलपमेन्ट के काम हुए है, खास करके इन्डस्ट्रियल वर्क काफी हुआ हैं। वह वास्तव में देश में जैसा मैंने कहा था राजस्थान में ७०-८० प्रतिशत मज़दूर किसान हैं। पर जब तक जमीन पर से इन्डस्ट्री पर नहीं आवेंगे तब तक आर्थिक दृष्टि से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस दृष्टि से जो प्रगति हुई है उससे हमें खुशी है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन—जिन चीजों की लिस्ट बताई थी उनको देखते हुए कह सकते हैं कि वास्तविक उन्नति हुई है। और भी विभिन्न तरीके की इन्डस्ट्रियल उन्नति हुई है। कुछ चीजों की चर्चा इसमें नहीं है फिर भी हम देखते हैं कि राजस्थान में बनी हुई साईकिलें आज हमें मिल रही हैं, किसानों को बहुत चाहिये, राजस्थान में ही नहीं, देश भर में मकराने की एक इतनी बड़ी इन्डस्ट्री है कि पहले दो चार खानें थीं। अब २०,२५ खानें चल रही है। पहले हिन्दुस्तान में मार्बल स्टोन इम्पोर्ट होता था, मगर मकराना इन्डस्ट्री ने उसको पूरी तरह से सप्लाई किया है और इस काम में वह पूरी तरह समर्थ हुआ है। ऐसी स्थिति में हम कहें कि इन्डस्ट्री हमारी डवेलप नहीं हुई है और कुछ काम नहीं हुआ है, इस तरह कहने की तो उनकी आदत है और कहते ही जायेंगे। उसके बाद में एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा खास करके भाषण के अन्त में जो एक सेन्टेन्स है उसके ऊपर। उसमें यह है कि :

'इसमें सरकार की कामयाबी केवल आपके हार्दिक सहयोग, राज्य कर्मचारियों के सद्भावना और ईमानदारी से किये गये सद्प्रयत्नों और विभिन्न स्तरों पर गैर सरकारी संस्थाओं के सक्रिय योग पर ही निर्भर है।'

यह तीनों बातें वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल महोदय के इस भाषण का जो अंतिम सेन्टेन्स है यही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। देश के अन्दर कोई भी नीति हम लायें, किसी भी कदम को उठायें जब तक कि इन तीनों शक्तियों से एक साथ काम नहीं लिया जाये, तब तक कोई काम पूरा नहीं हो सकता। देश के लोग, सरकार के कर्मचारीगण और जो प्राईवेट इन्स्टि-ट्यूशन्स हैं जब तक यह तीनों मिलकर कोई काम नहीं करें, तब तक वह काम पूरा नहीं हो सकता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भी इस बात की ओर आकर्षित करूंगा। बराबर यह कहा गया है कि जो प्राइवेट संस्थायें हैं और जो वह काम करती हैं उनका अब तक पूरा सहयोग लेने के लिए आह्वान किया गया है और उनका सहयोग

(श्री मोतीलाल चौधरी)

आयन्दा भी बाद्‌वान किया जायेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है जिससे जो संस्था जो काम करती है वह पूरी तरह से उसको कर सके। लेकिन दो तीन बातों के बारे में कहा गया, खास करके सरकारी अधिकारियों के बारे में। सरकारी कर्मचारियों के सहयोग के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इंगित किया है। सद्‌भावना राज्य सरकार के हाथ में है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह तो सरकार के ही सबऑर्डिनेट हैं और वह उसी के कर्मचारी हैं। यह ठीक है कि उनकी सद्‌भावना के बग़ैर काम नहीं चल सकता। वास्तव में इनमें कुछ कमजोरियां हैं जो कमजोरियां सर्विस के अन्दर हैं और इन कमजोरियों से हमारे विकास कार्यों में रुकावटें आती हैं। मैं चाहता हूं कि इन कमजोरियों को भी मिटाना चाहिए। मैं ऐसे दो तीन उदाहरण दे सकता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंचायत एक्ट को लीजिए, पंचायत एक्ट के अन्दर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायतों को गोचर भूमि का अधिकार दिया गया है, पंचायतों को आबादी की भूमि का अधिकार दिया गया है और कई जगह ऐसा हुआ है कि बहुत सी तहसीलों में काफी जमीनें अभी तक सौंपी गई हैं। इससे यह झगड़ा होता है कि पंचायत कहती है कि यह जमीन हमारी है और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट कहता है कि हमारी जमीन है, और इस तरह के झगड़ों को चलते-चलते तीन-तीन साल हो गए, मगर उनका कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें कन्ट्रोल करना चाहिए।

इसी तरह से बहुत कुछ बातें और भी हैं। मैं सबसे पहले पलाना का उदाहरण दूंगा। बिजली के अलावा कोयला भी शक्ति है। मेरा ख्याल है कि हममें से किसी से भी पलाना खान की स्थिति छिपी हुई नहीं है। उसके अन्दर कितना कोयला है उसके बारे में अलग-अलग रिपोर्टें आई हैं। इसमें ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि पलाना में कोयले की ४ डिपाज़िट्स हैं। इसके बारे में जो सन् १६४७-४८ और ४६ की रिपोर्ट है उसमें है कि इसमें कितना कोयला है। इसके बारे में ओपिन कॉस्ट माइनिंग करना है लेकिन इस पलाना में ओपिन कॉस्ट माइनिंग करने के बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई संकेत नहीं है। ओपिन कास्ट माइनिंग करने में क्या हानि है। जब तक हम ओपिन कास्ट माइनिंग नहीं करते हैं तब तक हम १५ पर्सेन्ट कोयला ही निकाल सकते हैं और ओपिन कॉस्ट माइनिंग करने के बाद में हम सेन्ट पर्सेन्ट कोयला निकाल सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के विशेषज्ञ भी यही राय दे चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं, इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए।

मैं सिर्फ एक विशेष बात की ओर मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और वह है कमिश्नरी के संबंध में। कल भी जिस समय प्रस्तावक महोदय बोल रहे थे उन्होंने भी इसकी ओर इंगित किया था कि कमिश्नरी तोड़ी जाय, ऐसी एस्टीमेट्स कमेटी की राय है। तो उस फैसले के बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर कुछ निर्णय लेने के लिए तय हो चुका था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ। उसके बाद में जैसा प्रस्तावक महोदय ने कहा कि

(श्री मोतीलाल चौधरी)

इस दृष्टिकोण से इस पद को नहीं हटाया जा रहा है कि वह विकास के कार्यों को देखेगा। तो विकास के कार्यों को देखने के दृष्टिकोण से अलग कोई अधिकारी रखा जाता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न ही मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं भी कहूंगा कि जिला स्तर के ऊपर कोई अधिकारी रहना चाहिए लेकिन इसमें यह तथ्य नहीं रहता कि कमिश्नर रहने चाहिएं। कमिश्नर की जो ग्रेड है, जो स्केल है और जिस काम के लिए उनको रखा गया है उसका तो यह काम न करे और उसके लिए यह कह दिया जाये कि वह विकास कार्यों को देखें और इसी के लिए उसको रखा जाये। मैं इसके बारे में थोड़े से आंकड़े देकर कहूंगा। हमारे यहां राजस्थान में पांच कमिश्नरी हैं। बीकानेर में है। वहां बीकानेर डिविज़न की जनसंख्या १४॥ लाख है, उदयपुर की जनसंख्या देखते हैं तो वह ७६ लाख के करीब है और जयपुर में ८० लाख की जनसंख्या है। तो तीन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कमिश्नर, और दूसरी और ८ जिलों के ऊपर एक कमिश्नर और जयपुर में ६ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां एक कमिश्नर। कोटा में तीन डिस्ट्रिक्टस हैं वहां के लिए एक कमिश्नर कोटा और बीकानेर के अन्दर १४ लाख के ऊपर एक एक कमिश्नर हैं और इधर जयपुर में ८० लाख की जनसंख्या पर एक कमिश्नर। अब जिलों का संगठन देखिये सिरोही के अन्दर १ लाख १२ हज़ार के ऊपर एक कलेक्टर, जयपुर में १५ लाख के ऊपर एक कलेक्टर, नागौर में ८ लाख के ऊपर एक कलेक्टर, भरतपुर में ११ लाख के ऊपर एक कलेक्टर। तो हमने यह इकाइयां शासन करने के लिए बनाई हैं। अगर हम इन इकाइयों को जनसंख्या के आधार पर, एरिया के आधार पर और काम के दृष्टिकोण के आधार से री-ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ जायेगा और उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर और पंचायत इन्स्पेक्टर भी एक ही काम के लिए पहुँचते हैं। तो मेरे ख़्याल से एस्टीमेट्स कमेटी ने यह कहा था कि पुलिस को और कमिश्नर के ढांचे को फिर से री-ऑर्गेनाइज़ किया जाये। इससे सरकार को मेरे ख़्याल से करीब दो या ढाई करोड़ की बचत होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि खर्च को कम करने का सरकार का पहला कर्त्तव्य होना चाहिए। समाज का आर्थिक ढांचा, समाज की नीति को सुधारने के लिए हमें जरूर ही खर्चे में कमी करनी चाहिए। शासन का खर्च कम करने के लिए हमें री-ऑर्गेनाइज़ेशन करना चाहिए और जहां तक हो सके विकास के कामों को देखने के लिए कोई अधिकारी अगर रखने हों तो वह रखे जायें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर डवेलपमेन्ट कमिश्नर है, उनकी पे स्केल देखिये, बीकानेर के कमिश्नर के बराबर भी नहीं है। जब कि राजस्थान के अन्दर एक डवेलपमेन्ट कमिश्नर काम सम्भाल सकता है तो कमिश्नर हम रखते हैं तीन डिस्ट्रिक्ट्स का काम चलाने के लिए, यह समझ में नहीं आता। कोटा का एरिया ४ हज़ार स्क्वायर माइल है, नागौर के अन्दर ८ तहसील मैं, कोटा में २१ तहसील हैं। तो मेरा निवेदन है कि देश की गरीब जनता को शोषण से मुक्त कराने के लिए हम चल रहे हैं तो सरकार का जो शासन है उसके खर्च में कमी करनी होगी और जब हम शासन के खर्चे में कमी करेंगे तभी हम

Page No.64

(श्री मोतीलाल चौधरी)

विकास कार्यों में काफी मदद कर सकते हैं। अतः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसको सभी एकमत से स्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री जयसिंह राणावत।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं निवेदन करूंगा कि रामराज्य परिषद् की तरफ वालों को चान्स अभी तक नहीं मिला है।

श्री सभापति : इनके बाद में चान्स दिया जावेगा। आप बोल लें। श्री जयसिंह।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : On a Point of order, Mr. Chairman, there is one request to you that time limit should be prescribed so that other members may have a chance to speak. There should be fair distribution of time.

श्री जयसिंह राणावत (आसींद) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जो घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे मेरा खास इरादा आज बोलने का नहीं था, लेकिन इस बारे में बोलना मेरे लिए यों आवश्यक हो गया क्योंकि कल एक माननीय सदस्य ने अपनी एक ऐसी ऊंची उड़ान उड़ी जैसे एक साथ पक्षी आकाश में स्वतन्त्र वायु मंडल और वातावरण में जा कर, वापिस ऐसे अनुचित स्थान पर आकर बैठता है कि जहां उसको स्वतन्त्र वायुमंडल से आकर जिनके पास में बैठना अच्छा नहीं लगता है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अक्सर कुछ साथियों का या इन संगठनों का ऐसा रवैया हो गया है कि सरकार कितना ही अच्छे से अच्छा काम करे वह नुक्तेनिगाह की दृष्टि से देखते हैं और कोई न कोई नुक्तेचीनी ऐसी बताते हैं जो तथ्य के बिल्कुल परे होती है। मेरे पास कल के भाषण के जवाब में तथ्य और आंकड़े हैं जिन्हें मैं उनको और हाउस को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। यह बात अवश्य है कि सरकार जिस लक्ष्य को लेकर चलती है उस मंजिले मक़सूद पर अभी तक पहुँच नहीं पाई है और कई खामियाँ और कई रुकावटें आ रही हैं। इसको मैं मानता हूं और हम सब मानते हैं कि आज सरकार १० साल या ११ साल का छोटा सा बच्चा है। जिसका विकास होना अभी आवश्यक है, और एक कहावत के अनुसार वह अगर कुछ रुक-रुक कर खराबियों को सुधारने के लिये सहम कर चलता है तो कोई अत्याचार की बात नहीं है।

२. ३३ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

वैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के एक दो पाइन्ट पर मुझे निवेदन करना है। मैं उन्हें बाद में निवेदन करूंगा। लेकिन श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आसींद क्षेत्र की सामूहिक कृषि सहकारी की आलोचना और विवेचना की है वह मुझे असह्य है। वस्तुस्थिति सभापति महोदय, यह है कि यहा पर जो १० हज़ार का लोन दिया गया है वह एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है। वह रजिस्टर्ड सामूहिक कृषि सहकारी समिति है, और जितना लोन गवर्नमेंट ने

(श्री जयसिंह राणावत)

दिया है, उतना ही पैसा उन सदस्यों ने एकत्रित करके उसको जिस काम में लगाना चाहिए था, उसमें लगाया है। उन्होंने कहीं भी अपने भाषण में यह ज़िक्र नहीं किया है कि पैसे का दुरुपयोग किया या पैसे का गबन कर गये। जो वस्तु स्थिति है वह यह है कि करीब ३०० बीघा जमीन के लिए सहकारी समिति के २०, २५ सदस्यों ने प्रार्थनापत्र भेजे। तहसीलदार ने अपने नीचे के अधिकारियों को मौके की जांच के लिए भेजा। उसके दरम्यान में अब यह शिकायत आई कि कुछ गांव वालों को एतराज है तो दुबारा, तिबारा और मुकर्रर जांच के लिए अफसरों को भेजा और गांव के लोगों को मौका दिया कि अपने उज़रात पेश करें। इस बारे में जो फैसला नायब तहसीलदार साहब ने दिया उसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि मेरे पास है। आपकी आज्ञा से मैं हाउस की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं। वह फैसला इस प्रकार।

"प्रार्थना पत्र सामूहिक कृषि सहकारी समिति आसीन्द बाबत मिलने जमीन नोतोड़। मि० नं० ५६ सन् ५७ अवलोकन में आई तो प्रकट है कि सामूहिक कृषि सहकारी समिति आसीन्द की ओर से प्रार्थनापत्र पेश हुआ कि इस समिति के २० सदस्य हैं। इस समिति की रजिस्ट्री हो चुकी है। लिस्ट सदस्यों की व प्रतिलिपि रजिस्ट्रेशन की पेश है सो ४०० बीघा भूमि काश्त के लिए दी जाय। मोजा आमिसर, रायरा गणेशपुरा, रामपुरा की सरहद में निशा देही की जावेगी। इस पर भूमि-अलॉटमेंट की कमेटी ने दिनांक २०-५-५७ में सामूहिक कृषि सहकारी समिति, इस तहसील में पहले से ही कायम होने से ३०० बीघा भूमि देने की स्वीकृति दी। बिनाबर निशा देही व कार्यवाही मौका पटवारी हलका आमेसर के पास भेजा गया तो...

श्री शिवचरणदास (मांडल) : On a point of order, Sir. यह जो फैसला है, वह कलेक्टर का नहीं है...

श्री सभापति : Yes, he has taken my permission and he will place it on the Table of the House,

श्री शिवचरणदास : तहसीलदार ने यह नैतिक फैसला दिया या नहीं लेकिन...

श्री सभापति : That is no point of order please.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो प्रश्न खड़ा किया गया वह यह है कि जो श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का ज़िक्र किया है तो मैं बताऊंगा कि तहसीलदार और एस० डी० ओ० से जो फैसला है वह जबरदस्ती कराया गया है। लेकिन कलेक्टर का फैसला दूसरा है। कलेक्टर ने जमीन देने से इनकार किया। वह पढ़कर सुनावें। तहसीलदार के फैसले को सुनाने से क्या फायदा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वह आप सुना दें।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह कल सुना दिया।

श्री जयसिंह राणावत : सभापति महोदय, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि मैं मुख्तसिर में इसको निवेदन कर देना

(श्री जयसिंह राणावत)

चाहता हूं उसमें जो मवेशियों के लिए चरागाह व भूमिहीन किसानों की बाबत ज़िक्र किया तो कुल जमीन काबिले काश्त का वहां पर ५०० बीघा हैं जिसमें चारागाह का रकबा २५०० बीघा कायम किया और २५०० बीघा काबिले काश्त के रकबा बचता था। सहकारी समिति को ऐसी जमीन दी गई है जो पहाड़ियों के बीच में काबिले काश्त थी। जांच पड़ताल से कुल लगभग १०० बीघा जमीन जो मिली है वह ऐसी जगह है जिसके चारों ओर पहाड़ियां हैं। सहकारी समिति ने ट्रैक्टर से अच्छी तरह से बुआई करके उसको तैयार की है। बीच-बीच में छोटी-छोटी पहाड़ियां और टेकरियां हैं जो कि हटाई नहीं जा सकतीं हैं। इस फैसले से साफ़ है कि भूमिहीन किसानों को भूमि देने और गांव के किसानों के मवेशियों के लिए जमीन छोड़ देने के बाद भूमि दिये जाने की आवश्यकता समझी गई है। तहसीलदार साहब ने फैसला किया है। उसकी यह प्रमाणिक प्रतिलिपि जो मेरे पास है. वह मैं हाऊस की टेबिल पर रखता हूं। इसके बारे में...

श्री शिवचरणदास : कलेक्टर साहब ने क्या किया ?

श्री सभापति : Please do not interrupt.

श्री शिवचरणदास : चेयरमैन महोदय, इस बारे में अन्तिम निर्णय कलेक्टर साहब का होता है।

श्री जयसिंह राणावत : जो माननीय सदस्य इस बारे में बोल रहे थे, वे वहां उस ज़िले के मांडल से आये हुए माननीय सदस्य के आवेश में आकर चले गए। वहां दांता के नेता साहब भी चले गये, और वहां ऐसे पर्चे बांटे जो जनता को गुमराह करने वाले थे कि एक बहुत बड़ा जनसंघ का सम्मेलन हो रहा है...

श्री सभापति : Do you want to place it on the Table of the House ?

श्री जयसिंह राणावत : मैं इसको रख रहा हूं।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जनसंघ का यह पर्चा उस गांव के किसान, बावजूद कहा सुनी के भी, कोई किसान छिपाने को तैयार नहीं हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें भीलवाड़ा के अपने किसी साथी को टटोलना पड़ा। काफी दौड़ धूप करने, डंडा पीटने और गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाने के बाद भी कोई ८०-१०० किसान वहां पर आये होंगे और स्थानीय किसानों को चकमा देकर २००), ४००) रु० लाये थे, उसकी फ़र्ज़ मनसबी कल उन्होंने दे दी। मैं कहना चाहता हूँ कि सहकारिता के बारे में उनके सद्भावना के कैसे विचार हैं। यह तो कल के उनके भाषण से ही पता चलता है कि उनके ऐसे विचार हैं। सहकारिता तो क्या किसी को भी ये पनपने नहीं देंगे। मैं भी यह चाहता हूं कि इस फायल को जहां कहीं भी यह हो, तहसील में या कलेक्टरी में, वहां से मंगाकर देखिये कि सहकारी समिति कहां गलती पर है। सहकारी समिति ने जो मेहनत की है, फसल बोई है, कमाई की है, उसे राजनैतिक दृष्टिकोण से ग़लत करार देने

(श्री जयसिंह राणावत)

की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। इस फैसले में तहसीलदार ने यह फैसला दिया है कि सरकार के किस हुक्म से सहकारी समिति को जमीन दी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में शीघ्रता से फैसला दें ताकि सहकारी समिति को निश्यात्मक नीति मालूम पड़ सके और परिश्रम को सफल मानें।

चेयरमैन महोदय, अब में राज्यपाल महोदय के भाषण की ओर संकेत करना चाहता हूँ।...

श्री शिवचरणदास : इस सहकारी समिति में किसान कितने हैं?

श्री जयसिंह राणावत : उनके भाषण के पृष्ठ संख्या ६ के पैराग्राफ २१ में उन्होंने यह फ़रमाया है कि उदयपुर में कपड़े की नयी मिल और कोटा में नायलोन फैक्ट्री के निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू हो जायेंगे। जहां तक कपड़ा मिल का प्रश्न है मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन नाइलोन फैक्ट्री के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इस वक्त जबकि हमारे राष्ट्र के बड़े-बड़े नेता एक ओर स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को सद्भ्रान्त नागरिकों यह सुझाव देते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनना उचित नहीं है, तब हमारे यहां नाइलोन फैक्ट्री खोलना भी उचित नहीं है। हमें सादगी से रहना और ऊंचे विचार रखने चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले ही देश में बेकारी का प्रश्न है और काफ़ी लोग बेकार बैठे हैं। ऐसी हालत में ऐसी फैक्ट्री को स्थान नहीं देना चाहिये।

दूसरा ध्यान उनके भाषण के पृष्ठ संख्या १३ के पैरा ५.२ की ओर खींचना चाहता हूं जिसमें सहकारिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस बारे में वर्ग सहकारिता की ओर राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है फिर भी कुछ प्रवृत्तियें हैं जिनके कारण निराश होना पड़ता है। मैं भीलवाड़ा ज़िले के बारे में निवेदन करूं कि वहां पर जितनी सहकारिता खुली हैं उसके मुकाबले में स्टाफ नहीं पहुँचा है। स्टाफ की कमी के कारण जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है। इसलिये राज्य सरकार से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सहकारिता आन्दोलन को सफल करने के लिये पर्याप्त स्टाफ भेजे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कल से यह प्रश्न चल रहा है कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिया जाय या नहीं। यह एक तरह की परिपाटी है और इस परिपाटी के हिसाब से यह होता है कि उनको औपचारिक तौर पर जिसके जो भाव हों, गवर्नमेंट के प्रति विचार हों उनको व्यक्त करने का मौका मिलता है और दूसरी पार्टी, जो अपोज़ीशन की है, उसको भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये यह शुरू में यूरोप से चली हुई परिपाटी है। वैसे दो, तीन या चार रोज़ धन्यवाद के लिये रखते हैं तो इसमें यह विचार रहता है कि उनके वास्ते जो भी दोनों पार्टीज़ विचार व्यक्त करना चाहें तो कर सकती हैं।

मेरा निवेदन यह है कि सारे हाउस से ही नहीं, राजस्थान की जनता से ही नहीं प्रत्युत सारे भारत की जनता से भी यह बात

Page No.68

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान में काफी कमियें हैं और दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों के अन्दर राज्यपाल महोदय के भाषण के विचार विमर्श के अन्दर भी, यह कहना पड़ेगा कि इसमें हाथ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का भी रहता है। जैसे प्रश्न आया था 'लॉ एण्ड ऑर्डर' के बारे में विचार रखने का, 'लॉ एण्ड ऑर्डर' में जो जो प्रगति हुई है और जिस तरह से आउट लॉज़ को खत्म करने की कार्यवाही हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है और पहले माननीय सदस्यों ने निवेदन कर दिया है कि यहाँ पर राजस्थान के खुद के लोकल हैड वर्तमान आई० जी० पी० परदेशियों की बजाय होने के कारण भी ऑडिटलॉज़ को खत्म करने से काफी असर पड़ता है। बावजूद इसके यह भी चीज़ पैदा हो रही है कि जयपुर में एक छोटे से प्वॉइन्ट को लेकर, हाई कोर्ट के प्रश्न को लेकर कई सख्तियें उस समय की गई थीं, उसको यहां की जनता ही क्या, भारतवर्ष की जनता भी और दूसरे लोग भी काफी अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग, जिनके, यहां आकर विचार रखने का प्रश्न आता है, हमें इस बात की आवश्यकता होती है कि जो भी दोनों ओर की तरफ से कोई वाज़िब बात हो, पूरा दोष ढूंढने के अलावा जो ठोस काम भी हुए हों, उनके बारे में भी अपनी विचारधारा रखना आवश्यक होता है। इसके लिये यह कहने के वास्ते कि अब भी जैसी बात कई दफा उपस्थित हुई है, उधर की ओर बैठे महानुभाव और इधर माननीय के सदस्य भी जिस प्रकार की भाषा काम में लाने का हिसाब रहा रहा है, १२ वर्ष हो चुके राजाओं को जो अपनी इच्छा से राज्य छोड़ गये और जागीरदारों ने जागीरें छोड़ दीं, अब उनका कोई प्रश्न सामने नहीं है उनकी छिछालेदारी करना और छिद्रानुवेषण करना असामयिक और अनुपयुक्त है।

मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा अभी प्रश्न आया था डवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को और भी आगे बढ़ाने का सवाल है। उसमें काफी कार्य हो रहा है और काफी धन खर्च हो रहा है। इसके लिये यह कहने की अत्यन्त आवश्यकता है कि इसमें जो धन खर्च हो रहा है वह तरीके से हो और उसमें कोई दूसरी विचारधारा के 'कलर का टिन्ज' न हों और आगे बढ़े तो कोई ताज़ुब नहीं कि उससे इतना ठोस काम हो सकता है कि जिसके बराबर कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अजान नहीं हूं, मैंने भी जो सफेद बाल किये हैं वे जनता की सेवा में किये हैं और एड्मिनिस्ट्रेशन को चलाने में थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस धन के बारे में यदि यह विचार रखा जाय कि ढंग से काम लिया जाय तो इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये काफी कहा जा चुका है विशेष कहना पिष्टपेषण होगा, फंसे हुए को फंसाना होगा। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इस बात के लिये उल्लेख करना और विचार करना अनावश्यक है।

अब प्रश्न जो को-ऑपरेटिव फार्मिंग के लिये आया, जैसा कि मैंने हाउस में निवेदन किया वह वहां की विचारधारा है, सेन्टर की विचारधारा है और उस समय की जब नागपुर में हमारे महामहिम पं० जवाहरलालजी के शब्दों से उस समय विचार उच्चरित हो

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कर यह आधार शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा यह अत्यावश्यक, चीज़ है। यदि वहां की विचारधारा को यहाँ की गवर्नमेंट लेती है तो इस बार ज़्यादा कारण देने के लिये कहने की आवश्यकता नहीं है।

चूंकि यह प्रश्न इधर से उठा है और यह भी कहने की आवश्यकता है कि बार-बार मुंह बन्द किये जाने की कोशिश की जाती है कि अपोज़िशन की ओर से ऐसे मामले क्यों कहे जाते हैं। यह तो अपोज़िशन का काम है। यदि ऐसा नहीं होता तो राजाओं के राज्य में, इन्डियन राजाओं के राज्य में नहीं, जालिम राजाओं के राज्य में, सीजर, केसर, नेपोलियन, हलाकू और चोज़ खां के राज्य में और इसमें विशेष फर्क थोड़े ही पड़ सकता है। कई महानुभावों ने कई दफा विचार रखा है कि यह गणराज्य का हिसाब है, मैं तो कहता हूं कि यह पुराना है पर उनका कहना है कि यह एक नई चीज़ आई है। इस प्रकार के विचार रखते हैं तो यह निवेदन करना है कि मैं राम राज्य पार्टी को बिलोंग करता हूं पर हमारे महामहिम बापू से लेकर भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि सारे विश्व की जनता महाराज भगवान् रामचन्द्र को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। उनके चरित्र के वास्ते उनके विचारों में बहुत ऊंचे भाव हैं, जो परमेश्वर के आलावा किसी के लिये इतने ऊंचे भाव शायद विश्व में नहीं रहे होंगे। आप तो कहते हैं दूसरी पार्टी से, पर यहीं से नहीं जो वर्ल्ड की दूसरे पने है वहां से भी कहा जाता है कि हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने के मुकाबले में, छोटे से रजक के कहने पर गर्भवती सीता को वनवास को भेज दिया, चूंकि मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं, तो कहना पड़ेगा कि वह चीज़ कम गौरव-स्पद नहीं है।

विचारों को रोकने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि दुनियां में कोई ताकत नहीं जो विचार-धारा को रोक सके। यह कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। मैं निवेदन करूं कि हम ही लोगों का प्रश्न नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग का सवाल ऐसा है कि जिसमें यहां के अति-रिक्त राजस्थान के ही नहीं भारतवर्ष के और बाहर के भी चोटी के लीडर्स ने इसे असाम-यिक और अत्यन्त अविचारपूर्ण बताया है। देखा जाय तो राजगोपालाचारी, के० एम० मुन्शी, प्रोफेसर रंगा और दूसरे उच्च कोटि के महानुभाव व जो यहां बैठे हैं, बाहर बैठे हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इस समय आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी विचार रहा है कि यह असामयिक है। अतः मेरा निवेदन है कि इसको विचार करके रखना चाहिये। भारत का वातावरण बहुत क्षुब्ध है और यह कहना पड़ेगा कि भारत, रूस या चीन नहीं हो सकता, भारत में और रूस, चीन में बहुत फर्क है। सोशियलिज़्म के पेटर्न को लेते हुए, जैसे विश्व कम्युनिस्ट पेटर्न में जाते हुए थोड़ा विचार करता है, मेरा तो क्या, आज से ७५ वर्ष पहले मेरे पिता ने सारी चीज़ों को ठुकरा दिया था, सारी चीज़ों को ठोकर मार कर ऐसे छोड़ दी, जैसे कोई चीज छोड़ी जाया करती है। मैं तो यही निवेदन करूंगा। मैं तो, चेयरमैन महोदय के द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय को को-ऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में यही निवेदन करूंगा कि उनसे संचालित मन्त्री मण्डल में दो दफा विचार करके सेन्टर से दलील करके, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

करना ज़रूरी होगा और यह ठीक भी चीज़ है। मैं तो इसको अनुपयुक्त चीज़ समझता हूं। राजस्थान हिस्टोरिकली, स्ट्रेटेजिकली, सोशियेली, इकोनॉमिकली और हर प्रकार की चीजों से बड़ा विचित्र स्थान है, जहां का १००० वर्ग मील का हिस्सा पाकिस्तान और दूसरे हिस्सों से मिला हुआ है, उस स्थान में इस प्रकार की बात खड़ी करना मैं अनुचित समझता हूं।

आज उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों क्षुब्ध हैं और कई नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं। कोई बूढे आदमी को ऐसा कहने से रोका नहीं जा सकता, यह अनुचित और असामयिक है, यह कहने से रोका नहीं जा सकता। कहा जायगा, विचार किया जायगा, हमें खतरा है कि ऐसे खतरे में डेमोक्रेसी ही नहीं, सोशियलिज़्म ही नहीं, जिसके लिये महामहिम जवाहरलालजी दोहाई देते हैं, यह एक ऐसा सवाल है कि अगर एक दफा इसको आगे बढ़ा दिया जायगा तो फिर इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जायगा, इसको समेटने के लिये विचार करना पड़ेगा। और इसके लिये हिस्ट्री ही नहीं पोस्टेरिटी रोयेगी और कहेगी कि एक अविचारपूर्ण काम इस लिये हाथ में ले लिया गया कि उससे रूस, चीन और कॉम्युनिस्ट पेटर्न के सेटेलाइट हैं, वे खुश होंगे। और उनको प्रलुब्ध करने के लिये इस प्रकार की विचारधारा काम में ली जा रही है। यह गलत धारणा होगी।

३ म० प०

राजस्थान को छोड़िये, लेकिन भारतवर्ष है वह कभी भी किसी कॉम्युनिस्ट पेटर्न से प्रेरित हो नहीं सकता और अगर हो जाता है तो ज़्यादा दिन आगे बढ़ नहीं सकता है। पाकिस्तान और दूसरे स्थानों पर इस प्रकार की चीजें हैं अगर बढ़ी हैं और उनका जो प्रश्न रहा है वह आज सो कॉल्ड America and Co. and Soviet & Brothers. से प्रेरणा पाकर काम कर रहे हैं। मगर इस संबन्ध में, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बारे में धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकूंगा कि उनका बेलेन्स ऑफ पॉवर और इक्वीलिब्रियम को रखने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। बेलेन्स ऑफ पॉवर को कायम रखने के लिये बड़ी-बड़ी आवश्यकता इस बात की रहती है कि किसी तरह से अपना प्रभुत्व बना रहे। पाकिस्तान को इस्ट एण्ड वेस्ट में बांटना अमेरिका एण्ड क० का प्लॉनिंग था। यह उनकी बनाई हुई चीज़ है। इसके लिये बेलेन्स ऑफ पॉवर और इक्वीलिब्रियम की जरूरत है। जहां तक हो हम दूसरी पार्टी इस तरह की रखें जो वक्त जरूरत मदद दे सके। मैं हिस्ट्री का स्टुडेन्ट भी हूं। इसके अलावा मैंने थोड़ी अवस्था भी ली है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि मौका आवेगा जिसके लिये यह प्रश्न आता है और दोनों की पॉलिसी का प्रश्न आता है। अगर आज युद्ध छिड़ जावे, भगवान करे ऐसा न हो और युद्ध न छिड़े और जो कोल्ड वार चल रही है उसी प्रकार चल कर ही खत्म हो जावे, मगर फिर भी यदि युद्ध हो जावे, तो मैं यह कहूंगा कि एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर ही जो इन्डिया की पॉलिसी की बात आ रही है उसके खिलाफ इंडिया को रूस और चीन की तरफ और अमेरिका एण्ड ब्रादर्स के खिलाफ अलटीमेटम देना पड़ेगा। अगर में जिन्दा रह गया तो बता दूंगा कि इसमें

Page No.71

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वह चीज़ कह रहा हूं कि जिसके लिये आप लोग कहते हैं कि पार्टी बाजी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। ऐसा न हो कि इसके लिये बाद में पछताना पड़े और विचार करना पड़े।

श्री सभापति : आप प्रश्न पर चलें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दूसरी पार्टी बैठी है, राजगोपालाचार्य और मुंशी और रंगा साहब और दूसरे बड़े-बड़े प्रवीण लोग बैठे हैं। उनकी विचार धारा को हम रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि जगह-जगह यह प्रश्न पैदा हो रहा है। मुझे डर है कि शायद यह राजस्थान में, राजस्थान में तो क्या है, यह तो एक तरह से बलीदान का बकरा है। यह तो बहुत छोटी ताकत है। इसको चाहे जिस तरह से काम में लें मगर जिस समय दूसरे देशों का प्रश्न आवेगा उस पर हमें विचार करना है और यह विचारने की चीज़ है। इसलिये इस पर इतना जल्दी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आज भारतवर्ष का जन समाज और राजस्थान का जन समाज, इधर बैठने वाले और उधर, सामने बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, उसके अलावा माननीय मंत्री महोदय, अगर उनके हार्ट इन हार्ट सोचा जावे, तो वे शायद सभी उसके लिये अनुकूल नहीं होंगे। काश्तकारों से ताल्लुक रखनेवाले माननीय सदस्यों ने कहा कि हम लोगों ने राजाओं को, रईसों को और जागीरदारों को बड़े कड़े शब्द कहे गये हैं। अब तो १२ वर्ष हो गये हैं कोई भी रईस और राजा नहीं है। हम लोग सब भारत की भलाई के और जन समुदाय और उसके अलावा कृषक समुदाय की भलाई के लिये विचार करते हैं और निवेदन करते हैं। जैसा कि मैंने अपने लिये निवेदन किया, मुझे अपने लिये निवेदन नहीं करना चाहिये था, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो एक निष्पक्ष भारतवासी के नाते और छोटे से छोटे युनिट के तौर पर और विचार धारा के तौर पर कहूंगा कि यह विचार इतने जल्दी से लाये जा रहे हैं इन पर कुछ सोचने की बात है। अब रही बात यह कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिया जावे या नहीं। इसके लिये कहने की क्या आवश्यकता है। धन्यवाद तो उसी तरह से दिया जावे कि इधर से और उधर के बैठे हुए माननीय सदस्यों ने कहा है कि भ्रष्टाचार, पर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाये गये। मैंने तो अपने उम्र में सबसे पहले भ्रष्टाचार का शब्द ही राज्यपाल महोदय के पधारने के चार माह बाद में ही हुए भाषण में सुना था। उससे पहले मैंने भ्रष्टाचार का शब्द नहीं सुना। शायद सबसे पहले इस गवर्नमेंट की डिक्शनेरी में पहली ही बार काम में लिया गया होगा। मैं आज ७० वर्ष की आयु को पहुँच चुका हूं। मगर मैंने तो कभी सुना ही नहीं और न कभी भ्रष्टाचार पर विचार ही किया। मैंने इस समय यह कहा है यह कोई भविष्यवाणी हो। मैंने कई दफा धन्यवाद दिया था उस समय मैंने यही निवेदन किया था कि मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं और उसके अलावा हमारे मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से यह प्रश्न चल रहा है। उसके साथ-साथ मैंने यह भी निवेदन किया था कि मुझे यह डर हो रहा है कि आज भी मुख्य मंत्री महोदय उन्हीं लाइनों पर चल रहे हैं। यह आज से २॥ या तीन

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

वर्ष पहले की बात है। मुझे डर हो रहा है कि शायद राजस्थान ही सोशियलिज़्म के पेटर्न में परिवर्तन न हो जावे और जैसा इस समय दक्षिण में प्रश्न चल रहा है यहां पर भी पैदा न हो जाए। जो माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं वे भी इसके लिये मन में विचार कर रहे हैं वे भी मेरी राय से इत्तफ़ाक करते होंगे और यही सोच रहे होंगे। इसलिये मेरी ओर से यही निवेदन है। मैं तो उनकी इस फ़ेजियालोज़ी को नहीं समझ सका कि इसका असर दूसरों पर कैसे नहीं पड़ेगा। उनका इस फ़ेजियोलोजी से क्या मतलब है। अभी भी माननीय राजस्व मंत्री इस फ़ेजियोलोज़ी को क्लीअर करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत उचित होगा और मैं उसको बहुत उपयोगी समझूंगा कि यह प्रश्न किस तरह से आ रहा है। एक तरफ़ से यह विचित्र फ़ेजियोलोज़ी है जिससे यह डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और दूसरी तरफ़ से मेरे अन्दाज में तो यह है कि जब यह प्रश्न आ गया और राज्यपाल महोदय ने सवाल उठाया तो कहीं शुगर कोटेड कुनेन पिल्स जैसी चीज़ तो नहीं होगी ! क्योंकि जिस चीज़ को खत्म करने का सवाल आता है तो क्रोकोडायल टीयर्स और फांसी पर जाने वाले कलप्रिट को जलेबिया खिलाई जाती हैं, यह चीज़ भी उसी प्रकार की चीज़ नहीं होगी कि जैसा वह सवाल आया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि खेती के मामले में यह नहीं होना चाहिये, ५० वर्ष मुझे एक जागीर के ठाकुर हुए हो गये, अर्ध शताब्दी बीत गई। काश्तकार, बलाई और रेगर दोनों पार्टीज़ बराबर हैं, खेत के अन्दर वे काम करते थे, आज ११, १२ वर्ष में, उन सब को निकाल दिया गया। वे गरीब हरिजन हैं। जरा गहराई से देखें और सोचें तो आपको मालूम होगा कि वे आज दाने-दाने के मोहताज़ हो रहे हैं और उन पर अत्यन्त अन्याय किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि किसकी ओर से। जागीरदार जो कृषक हैं उनकी ओर से हो सकता है, मैं यह भी नहीं कहता कि ब्युरोक्रेसी की ओर से यह सवाल पैदा होता है, मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि जाट और दूसरा कृषक समुदाय है उनकी ओर से हो रहा है। लेकिन नागौर, मेड़ता और दूसरी जगहों में एक बलाई के पास दो हल की जमीन भी नहीं मिलेगी और वे आज निष्कासित होकर अन्न-अन्न के लिए मोहताज़ हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को इससे ज्यादा चीज़ दी जाय और विशेष अधिकार दिये जायं तो मैं तो साफ़ यह निवेदन करूंगा कि जितनी चीज़ की आवश्यकता है वही की जाय। राज्यपाल महोदय को और मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे कम्युनिस्ट पेटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। जो सदन में महानुभाव हैं और जो मुझे जानते हैं, मैं १५ वर्ष से कहता आया हूं कि एक दिन विश्व के ऐटलस पर लाल स्याही की बोतल ढुलक पड़ेगी हम जागीरदार इससे नहीं डरते हैं। लेकिन डरते हैं, दूसरी तरफ़ बैठने वाले माननीय सदस्य, उनके दिल कांप रहे हैं। सारी बातें हमारे ऊपर थोपते हैं, जागीरदार कौन हैं, हम जागीरदार या नये पैदा हुए जागीरदार।

३. १२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक मानीय सदस्य : अब तो नहीं रहे।

Page No.73

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वैसे के वैसे हैं। जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट पेटर्न की विचार धार पर रहे हैं और परमात्मा करे वही विचाराधारा हो कर रहे।

श्री जनार्दनराय नागर : होकर रहेगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरे विचार तो आज भी वही हैं और रहेंगे कि मेरे में, मेरे सर्वेन्ट में, मेरे मोटर ड्राइवर में फर्क रहा तो भगवान के अस्तित्व में फर्क समझता हूं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

ये सिद्धान्त ७५ वर्ष से रहे हैं। आज से ७५ वर्ष पहले मेरे पिता ने हाई स्कूल स्थापित किया। आज से १२ वर्ष पहले मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला।

श्री जनार्दनराय नागर : ब्रिटिश सरकार को चलाने में कितनी मदद दी ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : बहुत।

(हंसी)

हीरालाल शास्त्री, रामनारायण चौधरी, हज़ारों आदमी पैदा कर दिये।

(हंसी)

जो आपकी ऐकेडेमी से शायद ही पैदा हुए हों।

श्री उपाध्यक्ष : हम विषयान्तर हो रहे हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं नहीं विषयान्तर हो रहा हूं। उनको कह रहा हूं कि एक दफा सोचो और फरमाओ कि आप किस ओर बढ़ रहे हो, आपकी विचार धारा किस ओर जा रही है। मैं बुड्ढा आदमी हूं शायद वह समय मैं देखूं या नहीं। मुझे यह भरोसा है कि कम्युनिज़्म भारतवर्ष में फैल कर रहेगा और दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। आपने जिस एकेडेमी के लिए कहा था, मैं आपसे कहूंगा कि मैंने चार वर्ष पहले, शायद आप लोगों को याद होगा, आप नहीं फरमायेंगे, आपने नोट किया होगा किताब में, वे तो मूक बातें हैं, असेम्बली हाल तो जरूर कहेगा कि मैंने यह कहा था, कि हमारे मुख्य मंत्री जिस मार्ग पर जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और जिस टूटे फूटे रेल लाइन पर और टूटे ब्रिज पर होकर रेल की तरह आप माननीय सदस्यों व राजस्थान की निरीह जनता को घसीट कर ले जा रहे हैं तो कहीं बड़े भारी खड्डे में गिरने का मौका न आ जाय। यही स्थिति रही तो अवश्य ही कम्युनिज़्म होगा और मेरा अन्दाज़ है कि कम्युनिज़्म भारतवर्ष में फैल कर रहेगा और आप हम देखेंगे। नेहरूजी की और मेरी उम्र करीब करीब एक है।

श्री जनार्दनराय नागर : विचारधारा अलग-अलग है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरी विचारधारा तो उनसे भी एडवान्स है।

श्री जनार्दनराय नागर : भाग्य, भाव अलग-अलग हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपकी विचार-धारा में फर्क है। वह समय आयगा तो विचार करेंगे कि वस्तुतः हम किधर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छुराम। (श्री होतीलाल से) I mean you, Sir.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के भाषण के ऊपर जहां तक पॉलिसी का सम्बन्ध है बहुत वक्ताओं के भाषण हो चुके हैं। मैं पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा न जाकर अभाव और अभियोगों की ही बात अधिक करूंगा। वैसे एक पॉइन्ट के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक सरकार का निर्णय फूड ग्रेन्स ट्रेड को अपने हाथ में लेने का है मैं उससे इत्तिफ़ाक नहीं करता। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जितना सरकार के पास है उसी का सही इन्तजाम कर ले तब आगे कदम बढ़ाये तो अच्छा होगा। बीज़ जब ठीक तरह नहीं बांट सके, जो सीड इस टाइम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बांटा वह भी समय पर नहीं बांट सके तो खाद्य पदार्थों को सब लोगों के लिए कैसे इन्तज़ाम कर सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। बीज का जहां तक सवाल है मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनको मिलना चाहिये था उनको नहीं मिला और जिनको मिला उन्होंने बाजार में बेचा। जब यह एक थोड़ी सी मिकदार में ग्रेन की चीज़ सरकार के हाथ में आयी, उसी में इतना मिसमैनेजमेंट है तो जब ग्रेन के सारे व्यापार को हाथ में सरकार लेगी, तो इतना इन्तज़ाम करना मुश्किल हो जायगा और जैसा कि अभी सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार और इनएफिशियेन्सी के बारे में कहा कि यदि एक चीज़ अपने यहां मंत्रीमंडल और ले लेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही।

जहां तक प्रश्न है रबी कम्पेन का जैसा कहा गया है कि रबी कम्पेन से हमारी फसल बढ़ी है और बड़ी अच्छी फसल हुई है। इसके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा हुई, जो अच्छी वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई। यदि इस श्रेय को सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है तो मैं यही कहूंगा कि यह जनता को भुलावे में डालने की ही चीज़ है।

जहां तक इस रबी कम्पेन का प्रश्न है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में निवेदन करूं कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें कलेक्टर साहब ने कहा था कि सरकार का ऐसा आदेश आया है। इसका प्रचार करना चाहिये। सरकार फैसीलिटिज़ जनता को देना चाहती है जिसका अधिक से अधिक जनता फायदा उठाये। इसके बाद में सरकार ने क्या क्या मदद की है यह मेरी नोलेज में अभी तक नहीं आया है।

यह बात ज़रूर है कि अगर सरकार इस ओर प्रयत्नशील होती तो मैं समझता हूं कामा में जो पच्चीस हजार एकड़ भूमि बगैर काश्त के पड़ी रही, भरतपुर में बारह हज़ार एकड़ जमीन और इतनी ही जमीन रूपवास में बगैर काश्त किये हुए पड़ी नहीं रहती। इसके लिये सरकार का जवाब हो सकता है कि फ्लड में वह जमीन होने के कारण हम उसका इन्तज़ाम नहीं कर पाये। मेरा निवेदन है कि उस फ्लड पर कन्ट्रोल किया जा सकता था और वह जमीन खाली हो सकती है। अगर सही तरीके पर जिस सिस्टम पर, भतरपुर का पहले इर्रिगेशन सिस्टम था, अगर उसी सिस्टम पर चलते तो यह फ्लड की नौबत नहीं आती और न इतनी जमीन ही पानी में रहती। इस बात के लिये मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। वहां का जो इर्रिगेशन सिस्टम है, वह है नदियों को रोककर बांध

(श्री होतीलाल)

बनाना और बांधों का निर्माण इस प्रकार करना जो सारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकता हो। उसमें यह चीज़ थी जब बरसात हो रही है तो जयपुर की तरफ जो मिलते हुए बान्ध हैं उनको पहले भरने दिया जायगा जो आगे बांध है उनको खाली रखा जाता था। वह इसलिये कि अगर इमर्जेन्सी के समय बरसात ज़्यादा हुई तो पानी पीछे से आयगा उसको एब्जोर्ब किया जा सके। लेकिन इस दफा हुआ क्या कि बिल्कुल इसके विपरीत इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया। जो भरतपुर में चिकसाना बांध था और जो मोतीझील बांध था वे ड्रेनेज के बांध हैं जिनको लास्ट में भरा जाना चाहिये था उनको सब से पहले भर दिया। इससे क्या हुआ कि पिछले जो बांध थे वे अपने आप भर गये वैसी हालत में सरकार के सामने यह ज़रिया नहीं रहा कि फ्लर्ड को किस प्रकार कन्ट्रोल किया जाय। इस बात की ओर लोकल ऑथोरिटीज़ का ध्यान दिलाया गया कि मोतीझील जो बांध है उसको खाली कर दिया जाय, लेकिन वहां पर जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर और एग्ज़िक्युटिव इन्जीनियर्स थे, उन्होंने हायर ऑथोरिटीज़ को यह कहा कि हमेशा मोतीझील बांध तो दस फुट तक भरा रहता है अभी तो साढ़े सात फुट ही पानी भरा है अभी खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दस फुट तक उसमें पानी पहुँचा ही नहीं, ६ फुट पर ही भरतपुर को जाने वाली जितनी भी सड़कें थीं, सब पानी के नीचे आगयी। मेरी समझ में नहीं आया कि पहले जब दस फुट तक भर जाता था फिर भी सड़क पर पानी नहीं आता था तो अब ६ फुट पानी से सड़क कैसे ढक गई। इस ओर जब ध्यान दिलाया गया तो किसी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस वज़ह से सारा काम हुआ। मैं जहां तक समझता हूँ इसमें कुछ मिसअन्डरस्टेडिंग है जो पोलिटिकल लीडर्स की रही है। उसमें मिसअन्डरस्टेडिंग इस प्रकार की हुई कि मोतीझील बांध पर एक ऐसे सदस्य का मकान है जो अपोज़िशन में बैठते हैं और रूलिंग पार्टी का विरोध करते हैं उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं की कि सरकारी कागज़ात या पटवारी के कागज़ात को देख लेते तो जितनी परेशानी लोगों को हुई वह नहीं होती। उस मोतीझील बांध पर एक ऐसे सदस्य का मकान है और पास में उनकी ज़मीन भी है उनका यह विचार था कि यह इतना भरे कि कभी खाली न हो।

एक माननीय सदस्य : वे मेम्बर कौन थे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य जिनका ज़िक्र कर रहे हैं, क्या वे इस सदन के सदस्य हैं ?

श्री होतीलाल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबन्ध में प्रकाश न डाले।

श्री होतीलाल : इसके आगे नहीं कहूँगा। मेरा मतलब तो निकल ही गया।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो इस पर प्रसन्नता नहीं है।

श्री होतीलाल : लेकिन लोगों को तो जानकारी हो गई। दूसरी वज़ह, मैं कहूँगा जिससे लोगों को परेशानी हुई वह परेशानी क्रीएट

Page No.76

(श्री होतीलाल)

की गई । गवर्नर महोदय ने बड़े फख्र के साथ अपने एड्रेस में कहा है ।

'One wagon factory had already started production in Bharatpur.'

माननीय सदस्य यह सोचते होंगे कि वहां पर वैगन फैक्टरी के कायम हो जाने से वह सरसब्ज़ हो गया होगा कितनी तरक्की हो गई होगी । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं यह फ्लड आदि की जो सारी मुसीबत आयी वह वैगन फैक्टरी के कारण । The Wagon factory is a curse to the people of that area. It is not at all beneficial.

इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को इस बात के लिये इनफ्लुएन्स किया गया कि वैगन फैक्ट्री को पानी से बचाया जाय । उस वैगन फैक्टरी को बचाने के लिये ड्रेनेज़ बन्द किया गया और उसके कारण हज़ारों आदमियों पर मुसीबत आयी और खेती की सारी बरबादी हुई ।

एक वैगन फैक्टरी के कारण भरतपुर में इतनी तबाही हुई । सवाई माधोपुर में भी एक फैक्टरी खोलने का भी उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया है । हो सकता है वहां की जनता इससे खुश होंगी लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वहां की स्थिति में और आपके यहां की स्थिति में अन्तर होगा ।

श्री होतीलाल : मैं यह कह रहा था कि जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है हमारे यहां भी किसी लोकल आदमी को नहीं लिया गया सारे लोग बाहर से लाये गये हैं । माल का जितना भी कन्ज़म्पशन है, वह सब बाहर से किया गया है सिर्फ बिल्डिंग के लये ईंटे ज़रूर वहां से खरीदी हैं । जो सारी स्थिति हमारे यहां हुई, वह मैंने आपके सामने रख दी है ।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करूंगा ।

"Welfare of Scheduled Castes and Tribes continued to received special attention.

इसके बारे में थोड़ा सा निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्ज़ के लिये काफी रुपया खर्च किया जा रहा है । जैसी मेरी जानकारी है उसी प्रकार का वेलफेअर सारे राजस्थान में होता है तो मैं समझता हूं यह उन बेचारों के साथ बड़ा अन्याय है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 'बेचारे' शब्द का प्रयोग क्यों किया, उसके सदस्य इस सदन में भी हैं ।

श्री होतीलाल : मैं बाहर वालों के लिये अर्ज कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने पर फूला भाई मेम्बर एतराज करेंगे ।

श्री होतीलाल : (जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर सोशियल वेलफेअर भरतपुर के बारे में । वहां सन् १६५७-५८ के अन्त में कुछ फर्नीचर और इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदा गया, उसके लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये गये और तीन

(श्री होतीलाल)

कम्पनीज़ ने टेन्डर दिये उसमें एक तो भरतपुर ट्रेडिंग कम्पनी थी, दूसरी P.M. Khandelwal, and the third one was Lakhomal Gandhi.

इन तीनों के टेन्डर्स आये। फाइनेन्शियल रूल्स के तहत जितनी खाना पूर्ति आवश्यक होती है वह उन फर्मों ने कर दी। लेकिन मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि तीनों फर्मों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं और न उस समय ही एग्ज़िस्ट करती थीं और यह माल खरीदा गया भरतपुर ट्रेडिंग कम्पनी से जो न तो उस समय ही एग्ज़िस्ट करती थीं और न आज भी। जिन कीमतों में खरीदा गया कुछ के भाव तो मैं समझता हूं कम से कम ड्योढ़ भाव की होंगी और कुछ दुगुने भाव से भी ज्यादा की होंगी। ये बातें इस डिपार्टमेन्ट में होती हैं। इतना ही नहीं, उसी फाइनेन्शियल इयर के एन्ड में ७८ हज़ार रुपये की एक राशि बाबरिया कौम को बसाने के लिये उनके मकानों के लिये मन्जूर हुई। वे ७८ हज़ार रुपया खर्च तो नहीं कर पाते इतने अल्प समय में, फिर भी उन सब रुपयों को उठाकर बैंक में जमा करा दिया गया। मैं समझता हूं कि बैंक में जमा कराना भी फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ है। लेकिन यदि नियत में खराबी न हो तो मैं समझता हूं इसमें कोई एतराज की बात नहीं। ए० जी० और फाइनेन्स डिपार्टमेंट को एतराज हो सकता है, मेरा ताल्लुक तो सिर्फ नियत तक ही है।

वह ७८ हज़ार रुपया ड्रा करना शुरू किया और ३।४ हिस्सा उसका बैंक में से ड्रा कर चुके हैं। उनसे पूछा गया कि आपने क्या खरीदा? पत्थर खरीद रहे हैं साहब मकान बनाने के लिये। स्पोट पर जाकर देखा, उनसे पूछा भी कि वह पत्थर है कहां? तो कहते हैं कि वह तो फ्लड में बह गया। यह भी एक नई चीज़ सुनी पत्थर आया और बह गया। कम से कम वह पत्थर स्पोट पर नहीं है, फ्लड में वह गया या क्या हुआ यह वे ही जानें। खरीद फरोख्त कागजों में काफी है।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : फ्लड जोर से आया होगा?

श्री होतीलाल : यह तरीका सोचा होगा। यह हालत स्पेशल अटेन्शन की है जो गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : समय आपका हो गया है।

श्री होतीलाल : (जारी) अजी साहब, मुझे सबसे कम मिला है। जरा कागज़ देखने दो। भाषण सुनने के बाद उपाध्यक्ष महोदय,

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार उक्त अभिव्यक्ति कार्य-विवरण में से पृथक की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद : I take objection to it, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : यह ऑब्जेक्शनेबल है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भविष्य

(श्री उपाध्यक्ष)

में गवर्नर महोदय के सम्मान के सम्बन्ध में इस सदन के प्रांगण में कुछ न कहें और जो कुछ कहा गया है उसे एक्सपन्ज करने का मैं आदेश देता हूं।

श्री होतीलाल : मैंने यह कहा है उपाध्यक्ष महोदय, कि उम्र का तकाज़ा है। पर मैं यह निवेदन करूंगा कि शायद गवर्नर महोदय की जानकारी में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं और आपके ज़रिये मैं यह चाहता हूं कि मेरी आवाज़ आप उन तक पहुंचावें।

श्री उपाध्यक्ष : No, no You will not cast any aspersions on the personality of the Governor.

श्री होतीलाल : (जारी) लॉ और ऑर्डर के बारे में उन्होंने कहा। मुझसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसकी क्या स्थिति है ? एक एक रात में एक एक मोहल्ले में छः छः चोरियां हो जावें, पुलिस स्टेशन के पास में हो जावें, पर फिर भी उनका पता नहीं लगे। यह उस इलाके की बात है, जिसमें मैं पैदा हुआ। मैंने कभी डकैती और चोरियों की इस तरह की बातें नहीं सुनीं। वहां डकैती भी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें उस इलाके में दिन व दिन बढ़ती जा रही है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि लॉ और ऑर्डर सुधरा किस तरह से है। अपनी तरफ़ के अनुभव से तो मैं यही कह सकता हूँ कि यह बिगड़ा ही है। उन्होंने कल्याण डाकू को जोधपुर में मार दिया होगा। पर अपने यहां तो हालत बिगड़ी ही है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के बारे में मैं अर्ज करूंगा। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली इनके बीच में डिग्री कॉलेज़ एक भरतपुर में है। वहां की ऑथोरिटी ने रिप्रेजेन्टेशन दिया। मैंने भी एक दो बार सदन में कहा। इतने इलाके के बीच में एक कॉलेज़ है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ शुरू कर दी जावें तो लड़कों की परेशानी बचेगी। कुछ ऐसा ख़्याल हो सकता है कि धौलपुर वालों को आगरा नज़दीक पड़ता है, इसलिए धौलपुर वाले आगरा जा सकते हैं, पर आगरा का क्यों ज़िक्र करते हैं। वहां फीस में दुगुना फर्क है। अब भी भरतपुर आना पसन्द करते हैं बजाय आगरा जाने के। इसका जवाब लिखा पढ़ी करने पर यह आया कि चूंकि सरकार की पॉलिसी इस तरह की है कि यूनीवर्सिटी में ही पोस्ट ग्रेजुएट क्लास रक्खी जावे और इसलिये बाकी के कॉलेजों में शुरू नहीं की जा सकती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी समझ में यह जवाब आया नहीं। एजूकेशन मिनिस्टर साहब इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। हो सकता है मैं गलत होऊं समझने में। अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ यूनीवर्सिटी को देनी हैं तो यह खाली शायद जयपुर के लिये ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे राजस्थान की पोस्ट ग्रेजुएट क्लासें बन्द कर दी जावें और अगर कभी बन्द हुई भी तो सबसे पहले जयपुर में ही होंगी न कि भरतपुर, जोधपुर या बीकानेर में। लोअर एजूकेशन के बारे में जो भी कुछ इस में है उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता पर हायर एजूकेशन के लिये सरकार को कहूँगा कि उसे जनता को इसमें अधिक फैसीलिटी देनी चाहिये।

डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन ऑफ पॉवर के बारे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूं तहसील समिति जिसको

(श्री होतीलाल)

आप पॉवर देना चाहते हैं, उस रूप में है जिसमें आज ब्लॉक डवेलपमेन्ट कमेटी है। वैसे ही काफी इन्स्टिट्यूशन्स आज भी मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी के लेवल पर जिला समिति होंगी, लेकिन इसके अलावा आज भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कई जगह मौजूद हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि तहसील पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म करने के बाद किस तरह से पॉवर का डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन होगा। यह मेरी समझ में नहीं आया। जो पॉवर आप देना चाहते हैं वह तो आज भी मौजूद है। मैं तो यह कहता हूं कि जो कुछ पॉवर आज है उनमें भी करटेल करने जा रहे हैं। नाम तो आप रख देते हैं, पर पॉवर किसी को देने की नीयत नहीं है। आइडिया बड़ा सुन्दर है, पर करते नहीं हैं। कथनी और करनी में फर्क नज़र आता है, सरकार के।

दूसरी चीज़ में निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने करप्शन के लिये यहां ऐलान किया था। गये सालों में हम एक बहुत अनुभवीं आदमी इसके लिये बाहर से ला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि गये दो सालों के अन्दर उन्होंने क्या एचीवमेन्ट किया है। इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि अगर हम अन्धकार में हों तो उजाले में आ जावें कि दरअसल में कुछ किया है, नहीं तो इस तरह के सुपरफ्लस डिपार्टमेन्ट को रखने से क्या फायदा ?

इन सब शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इन सारी चीजों पर विचार करे और वे प्रस्ताव तो पास करेंगे, वे चेन्ज करने को तैयार नहीं होंगे। देखते चले आ रहे हैं। पर जो मन में है उस पर थोड़ा दिमाग से सोचें और अमल करने का प्रयत्न करें तो एफिशियेन्सी आवे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहस काफी हो चुकी है और बहुधा पुनरावृत्ति हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए भाषण संक्षेप में दिये जावे तो उपयुक्त होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इतिहास याद रखने की अपेक्षा इतिहास निर्माण करने की ज़रूरत है। अगर हम सब बैठकर आपस में बातें करें, मेरी समझ में उन बातों का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। हमें तो इतिहास का निर्माण करना है और इतिहास के निर्माण करने वाले व्यक्ति इतिहास की पिछली बातों को इसलिए याद करते हैं कि हमारे आपस में वैमनस्य पैदा हो। मगर यहां पर सवाल तो सीधा सादा है कि हमें इतिहास का निर्माण करना है। सारा देश एक नया मोड़ ले रहा है, नई पाठशालायें बन रही हैं, नये पंचायतघर बन रहे हैं और नई तस्वीरें सामने खड़ी कर रहे हैं....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं निवेदन करूंगा कि "हिस्ट्री रिपीट्स इट्सैल्फ" भी कोई चीज़ है।

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) ठीक है, आपने कहा मैं उसका भी उत्तर दे दूँ। एक दफा वैज्ञानिकों ने जब राम की मूर्ति को बनाना चाहा तो राजनीतिज्ञों ने बीच में कुछ इन्टरफीयरेन्स किया और वह रावण की मूर्ति बन गई। मैं नहीं चाहता कि जो हम इतिहास

(श्री मूलचन्द डागा)

का निर्माण कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई इन्टरफीयरेंन्स हो। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा होती है, जब जन जाग्रत हो जाता है, समाज आगे बढ़ने लग जाता है और उस प्रगति में अगर कोई रुकावट डालता है तो वह पीस दिया जाता है। हिस्ट्री रिपीट करती है। लेकिन जब मानव का स्तर इतना ऊंचा हो गया है और मानव मानव के नज़दीक आ चुका है और इतना नज़दीक कि वह दूरी अब हम नहीं नाप सकते तो हमें उन पुरानी कहावतों को भूल जाना चाहिए, पुरानी दंतकथाओं को छोड़ देना चाहिए। जमाना बहुत तेजी और रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाले लोग पुरानी कहावतें और इतिहास के पुराने मुहावरे नहीं देते, बल्कि मानव अपनी सूझ स्वयं ही बना लेता है और जो अणु युग में चलते हैं तो उसमें मानव को तेज रफ्तार के साथ चलना होगा। वयोवृद्ध और घिसटी हुई दलील देना आज के युग में शोभा नहीं आता।....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वह दलील...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) मैं यह बात किसी पर कहना नहीं चाहता। मेरा एक मकसद था। मैं कोई यहाँ उपदेश देने खड़ा नहीं हुआ हूं। बात यहाँ पर यह है कि जो राज्यपाल महोदय ने यहां पर अभिभाषण दिया है उसके बारे में हम क्या कहें। हम राजस्थान की भूमि में उद्योगों को अधिक से अधिक पनपाना चाहते हैं। एक संकेत है माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। उस भाषण को आपने पढ़ा और हमने भी पढ़ा। उनके अभिभाषण की भाषा भी हमने पढ़ी। शुरू में वह शब्द हैं और आखिर में वह शब्द हैं। चाहे सन् ५७ का भाषण ले लीजिए, ५८ का भाषण ले लीजिए और चाहे इस वर्ष का भाषण ले लीजिए, इन सभी भाषण में एक ही वाणी है। लेकिन उसने अपने आपको राजस्थान की जो जनता है, उसका इस ओर संकेत किया है कि हम उसमें चिमनियां और फैक्टरियां खोलना चाहते हैं। हम राजस्थान के रेगिस्तान में और इस भूमि पर उद्योगीकरण की दृष्टि से उद्योगों के बड़े-बड़े कारखाने खोलना चाहते हैं और इसीलिए १६ फरवरी की रात, जब रात शांत हो गई होगी, तब आकाश ने धरती से पूछा होगा कि बोलो राजस्थान की धरती ने आज तुम्हारे वक्षस्थल पर क्या कहा ? तो धरती ने कहा होगा कि आज राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात कही गई और वह यह है कि राजस्थान के कोने-कोने और जगह-जगह पर उद्योगों के कारखाने खुलेंगे। धरती ने एक बात आकाश को कही होगी और आकाश ने बात को सुनकर क्या कहा होगा ? उसका उत्तर आप सोच सकते हैं। हम एक देश की बेकारी को मिटाने का तरीका लाना चाहते हैं। देश को समृद्धिशाली और शक्तिशाली बनाने का हमने निश्चय कि है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं या और कोई व्यकित किसी पार्टी का भौंपू बन जाते है तो अपनी अन्तरआत्मा की ध्वनि को दबा देता है तो वह फूटे ढोल की तरह बोलता हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी के होकर, किसी पार्टी की वफादारी करने के लिए वह

(श्री मूलचन्द डागा)

पार्टी हमें खरीद ले । यहां खरीद फरोख्त का धन्धा नहीं है, यहां तो सवाल है राष्ट्र के निर्माण का और देश को आगे बढ़ाने का और अपने देश को दूसरे देशों की गिनती में खड़े करने का । सवाल साफ है लेकिन कोई कहे कि ११ साल के बाद राजस्थान की भूमि पर क्या हुआ ? एक प्रश्न आता है, मैं कहता हूं कि हमारी वाणी कहती है, क्या यह सही है ? मैंने कई गांवों की सभाएं देखी हैं और अखबार में पढ़ा है । जब हमारे मन्त्री महोदय भाषण देने जाते हैं, किसी चीज़ का उद्घाटन करने जाते हैं और जब अपने भाषणों की झड़ी के द्वारा लोगों पर भाषणों की वर्षा करते हैं तो उनके भाषण दे चुकने के बाद, उनके जाने के बाद तुरन्त ही लोग कहते हैं कि यह देश के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । क्या उन लोगों की वाणी का तुम्हारे व्यक्तित्व पर असर नहीं पड़ता ? इसका कारण मन्त्रियों के व्यक्तित्व की कमी है । मैंने एक जोधपुर के समारोह में देखा है कि लोग क्या कहते हैं । क्या है मानव की इज़्ज़त, कि पीछे से लोग कहें कि यह हमारे खज़ाने के साथ खिलवाड़ है । हम किसी पार्टी की वकालत करें, किसी देश की बात कहें, हमने मन्त्रियों की चापलूसी के वातावरण में अपने व्यक्तित्व को तो दिया और इसके कारण सेक्रेटेरियट उन पर हावी हो जाता है । मुझे देखकर दुख है कि आज एक विधान सभा का सदस्य पटवारी से भी बदतर है । आज पटवारी की रिपोर्ट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत एक लाख के प्रतितिधि के । यह है डेमोक्रेसी, उसकी खिलवाड़ आपका एक पटवारी कर सकता है, एक एस० एच० ओ० कर सकता है, एक सेक्रेटरी कर सकता है, सेठ और गुमाश्ते का सम्बन्ध है । आप ही ११ साल के बाद एक निर्णय दें और इसी का फैसला दें और राजस्थान के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की तकदीर देखें । कौन कह सकता है कि आज समाज से डाकू चले गए । अब तो वह डाकू पैदा हो गए हैं जो सारे सामाजिक वातावरण को कलुषित कर रहे हैं । एक कल्याणसिंह, गैंदासिंह और हरीसिंह चले गये, इनके अलावा और भी बीस पच्चीस चले गए मगर सारे समाज को कलुषित और अपवित्र और घृणित बनाने वाले डाकुओं की टोलियां पैदा हो रही हैं और उन डाकुओं की टोलियों को बस में नहीं किया गया, चाहे मशीनरी युग हो जाये, चाहे राजस्थान में बिजली चमकने लगे, चाहे भाखरा कैनाल या राजस्थान कैनाल चली आये मगर जब तक गंगा की पवित्र धारा नहीं बहेगी तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा । आप ही बताइये कौन सी ऐसी बस है जिसमें पुलिस का सिपाही फ्री नहीं घूमता हो और उसका टी० ए० नहीं बनता हो । यह सचमुच बड़े शर्म की बात है । पुलिस का सिपाही अपने डंडे के ज़ोर पर और उसके अधिकार से एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है और टी० ए० सरकार से प्राप्त कर सकता है । छोटी सी बातें करने वाले आदमी छोटी बात करते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले ऊंची बातें कर सकते हैं । राजस्थान का एक एस० एच० ओ०, एस० पी०, डी० आई० जी० अगर कहीं पर जाता है तो उसके लिए पहले से ही सीट रिज़र्व की जायेगी और यह कहा जायेगा कि यहां पर साहब का का टोप रखा हुआ है, डंडा रखा हुआ है और लोगों को पीछे बैठा दिया जाता है । आपने २५० पाने वाला एक पी० आई०

(श्री मूलचन्द डागा)

बना दिया, जिससे आप यह उम्मीद करते हैं कि वह डेकोयटी के केस चलाये, उस वकील के सामने जो कि १५०० पाने वाला है और फिर कोर्ट और सरकार उससे यह उम्मीद करे कि पी० आई० ईमानदार बने। उपाध्यक्ष महोदय, उस पी० आई० और पी० एस० आई० को जो कागज़ दिये जाते हैं वह सड़े और गले होते हैं और उससे आप उम्मीद करें कि वह १५००) रुपये पाने वाले वकील के सामने टिका रहे। लेकिन दुःख की बात है कि फूड एड-ल्टरेशन एक्ट निकला उसके मातहत सारे के सारे केसेज़ के लिए अलग वकील मुकर्रर किये गये। वकील कौन हैं? हमारे जैसे एम० एल० एज़०। क्या हुआ उसका परिणाम? ५० केसेज़ में आधे से ऊपर अदम पैरवी में खारिज़ हुए, क्योंकि हमारे एम० एल० एज़० साहब को फुरसत नहीं मिलती है पैरवी के लिए। उन्हें एक एक मुकदमे के १५) रु० दिये गये। क्यों नहीं १५) रु० फी केस के पी० एस० आई० और पी० आई० को दिलाये जायं फूड एडल्टरेशन एक्ट के केसेज़ लड़ने के लिए। मेरा, पुलिस की जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी ओर, सामने की तरफ मेरा संकेत है। मैं उनसे न्याय मांगता हूं। आई० जी० पी० ने क्या कभी यह लड़ाई की है कि पी० एस० आई० या पी० आई० जो है उनकी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए वे मुकाबला करते हैं इस बात का कि फूड एडल्टरेशन के केसेज़ पी० एस० आई० कोर्ट में लड़ सकता है। पुलिस की ११ साल की हालत के बाद में 'May I help you.' मगर किस तरह? अगर सेवालय बना है, अगर डॉक्टर अस्पताल को मन्दिर समझता है और रोगी की सेवा करना उसका सर्वस्व बन जाता है, तो अलग बात है, नहीं तो हमारी एक पद्धति बन गई है निकालने की वह निकाल दी है। और पुलिस के महकमे की वही हालत है। उनकी जबान अभी भी ब्रिटिश ज़माने की जबान है। उनकी जबान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही जबान बोलते हैं जो कि आज से १० साल पहले बोला करते थे। उसमें मिलावट नहीं आई है। पहले जिस तरह से लोगों से बोलते थे वही है।

एक छोटी सी बात को लेकर मैं पुलिस की ओर संकेत करना चाहता हूं। सारे के सारे ट्रेफिक के अन्दर पुलिस का हर आदमी निडर होकर घूम सकता है। मैं बतलाऊं कि आप क्या चाहते हैं हम से?

लीजिये, अब आप दूसरे विभाग, न्यायालय को। छोटी-छोटी बातें हैं। सेशन कोर्ट और सिविल एन्ड सेशन्स जज को एक पॉवर, एक अधिकार क्रिमिनल केसेज़ लड़ने के हैं। तो एक पी० आई० को २५०) रु० देते हैं और एक को ३५०) देते हैं एकसे काम को, एक ही कोर्ट में एक से समय में करने के लिए। क्या है आपके पास? आप क्या बतलाना चाहते हैं? आप क्या देना चाहते हैं। सिर्फ आप एक २५०) रु० माहवार का वकील करते हैं और दूसरा एन्गेज करता है १०००) रु० का। मैं आपको बतला दूं कि केसेज़ बन जाते हैं। जहां किसी पब्लिक सर्वेन्ट एस० एच० ओ० एस० आई० के खिलाफ केसेज़ बन जाते हैं, क्योंकि वह बड़ा अफसर है, तो उनके केसेज़ को डिफेन्ड करने के लिए पुलिस की तरफ

(श्री मूलचन्द डागा)

से खड़े होते हैं। अगर कोई एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट, माननीय गृहमन्त्री इस बात को नोट करेंगे, के लिए कितने केसेज़ कोर्टस् में हैं उनमें किस कारण से हिचकिचाहट होती है गवर्नमेंट की तरफ से पी० एस० आई० और पी० आई० को कन्डक्ट करने पड़ते हैं जब कि दूसरी पब्लिक के नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों बराबर हैं। दोनों की उस स्थिति में अन्तर क्या है। पुलिस के केसेज़ में हम पुलिस की तरफ से डिफेन्ट करने के लिए भेजें। यह है आपके पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ, शोभा, इज़्ज़त और आबरू ! मुबारक हो आपको ! हम तो कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में पुलिस समझ ले कि वह हिन्दुस्तान का सिपाही है और आपकी पी० टी० होती है उसमें शानदार परैड देते हैं और झन्डा फहरा देते हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग पर झन्डा फहरा देना चाहिए और गरीबों के प्रति आपका ध्यान हुआ तभी हम कहेंगे कि पुलिस का सिपाही हमारा सच्चा सेवक है, हिन्दुस्तान का सेवक है। आज तो इतने सेवक पैदा हो गये हैं फिर भी दुखी हैं। इतनी दाइयां पैदा हो गई हैं लेकिन देश के पेट में अभी दर्द है। कोई ऐसी दाई नहीं है कि जो पेट मसलकर उसके दर्द को मिटा दे। कितनी तरह के सेवक हैं। पुलिस सेवक, मन्त्री सेवक, एम० एल० एज़० सेवक बड़े से बड़े आदमी सेवक बन गये। सेवकों की भरमार होते हुए भी दर्दियों की कमी नहीं है। यह है हमारी पोज़ीशन, यह है हमारी स्थिति।

न्यायालय को लीजिये। सेशन्स जज, सिविल एन्ड एडिशनल सेशन्स जज की कोर्ट को ले लीजिये। मैंने कई अदालतें देखी हैं। माननीय गृह मंत्रीजी नोट करें कि क्लर्कस बयान ले रहे हैं और चूंकि आपकी आदत हो गई है गप्पे मारने की, क्योंकि आपका स्वभाव है, आप वहां डींगे मारते रहते है कि मैंने सप्लाई में वह काम किया, यह काम किया। कोई आकर आपसे कहता है कि साहब बयान लें लें एब्डक्शन का केस हैं तो कहते हैं रीडर से कि तुम ले लो बयान उधर जाकर, बैठकर। कितने बयान मजिस्ट्रेटस के हाथ के हैं और कितने बयान क्लार्क के हाथ के हैं ? यह हालत है अदालतों की जहां से कि हमें इन्साफ मिलता है ? जहां की कोर्ट फीस कम नहीं हुई है, जहां पर गरीब की पैरोकारी करने के लिए कोई आदमी नहीं दिया गया है। इस डेमोक्रेसी में, इस जनराज्य में, इस लोकराज्य में इस प्रजा राज्य में वकील करने के लिए गरीब की हिम्मत नहीं होती है। गरीब की भी इज़्ज़त है। देश की इमारत गरीब की हड्डियों पर आधारित है। कल मैंने अखबार में पढ़ा है कि गरीब क्या है ? राजस्थान में क्या, देश भर में क्या है ? एक गरीब घूमता घूमता श्मशान में चला गया। अचानक एक मुर्दा उठने लगा। मुर्दे को उठता देखकर गरीब ने उससे कहा कि भाई थोड़ा आराम मैं भी करना चाहता हूं क्योंकि काम करते करते मेरी कमर टूट गई है, मेरी हड्डियां घिस गई हैं, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है। मुझे थोड़ा सा लेट जाने दो। मुर्दा थोड़ा झिझका और फिर लेट गया खुद और कहा कि तेरी गरीबी से तो मेरी मौत अच्छी है। आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, बड़ा अच्छा नारा है, आकर्षण है इसमें, वह अचम्भा पैदा करने वाला है। वह एक बिजली पैदा करता है लोगों के दिलों

(श्री मूलचन्द डागा)

में। कल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने के बाद हरएक क मज़दूर ने अपनी दाल में डेढ़ पाव घी डाला होगा। यह ज़ाहिर है कि कौन से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की इस मंहगाई के जमाने में तनख्वाह बढ़ी है। हमारी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख सिद्धान्त हैं कि हम विषमता को कम करना चाहते हैं। अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो वह उद्देश्य मत रखिये। आप अपनी करनी और कथनी में फर्क मत कीजिये। आपकी वाणी और आपके काम में अन्तर नहीं होना चाहिए। १६५८ से हमने घोषणा कर दी कि हम डेस्पेरिटी को कम करना चाहते है कोई ऐसा सिविलियन ऑफिसर नहीं है जिसके घर पर अर्दली, सवार या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम नहीं करते हों, उनकी औरतों का काम नहीं करते हों या तहसीलदार के बच्चों को पहुँचाने स्कूल नहीं जाते हों। एस० पी० या दूसरे अफसरों को जिनके घर पर पहरा लगता है क्या उनको भूत खाता है या डर लगता है जिसकी वजह से पहरा लगता है। इसका क्या कारण है? इस पर कितना खर्चा लगता है। एक एक चपरासी अफसरों के घर पर रहता है, प्रोसेस सरवर सब्जी लावें या घर का सामान लावें या टी टाइम पर अटेन्ड करें। शर्म है, लानत है। मेम्बर बनने पर हमको लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय सुनाने के। क्योंकि हमको मेम्बर बनना था, मेम्बर बन गये, हमारी आवाज़ क्या है। कौनसा चतुर्थ श्रेणी का आदमी है जिससे कोई भी अधिकारी काम नहीं लेता है। क्या उस चतुर्थ श्रेणी के आदमी के बच्चे नहीं है या औरत नहीं है कि वह सर्दी के दिनों में भी आपके द्वार पर खड़े रहें और रात को अपने कुटुम्ब से अलग रहे। क्या यही आपका न्याय है? कुछ नहीं, आपके दिमाग में छोटी बातें हैं। उसके बच्चे बीमार हों या औरत

४. १. म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

बीमार हो तो वे घर पर पड़े रहें, पर उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। लाखों रुपयों से ज्यादा उस पर खर्चा होता है। सरकार के प्रोसेस सरवर चार काम करते हैं तो ११ प्रोसेस सरवर बैठे हुए हैं। न तो कलेक्टर बोल सकता है और न एस० डी० ओ० बोल सकता है और न तहसीलदार बोल सकता है, क्योंकि सभी के यहां आदमी काम करते हैं। किसी को रोटी बनाने वाले की ज़रूरत होती है तो वैसा आदमी भेज दिया जाता है और किसी को नाई चाहिये तो नाई भेज दिया जाता है। अगर वह आदमी कुछ बोले तो उसको धमकी देते हैं कि तेरा ट्रान्सफर कर देंगे। उस गरीब के लिये एक धमकी ही काफी है, गरीब के लिये ट्रान्सफर की धमकी ही काफी है, मुर्गी को तकबे का घाव ही काफी है। यह है हमारे यहां की हालत। क्या कोई हैं ऐसे चीफ सेक्रेटरी जो यह बतावें कि मैंने फलां ऑफिसर को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से काम लेने के कारण मुअत्तिल कर दिया है। यहां हम समाजवाद की रूप रेखा बनाना चाहते है। हमारे यहां ऐसा ही समाजवाद हुआ तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का क्या हाल होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि लंका में विभीषण नहीं बने रहते या काबुल में, जो बात लोग कहते हैं, मैं नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

कहना चाहता, वे नहीं रहते। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ यही आपका न्याय है, व्यवहार है और यही आपके समाजवाद का नारा है ?

अब मैं आपसे यह कहूं कि तनख्वाहें आप देखिये, शिक्षा को ले लीजिये। हम भविष्य को सुन्दर देखना चाहते हैं। हमारा भविष्य गौरवमय हो, सुन्दर हो और हमारे भविष्य के कर्णधार उन स्कूलों में पढ़ें जिनके अध्यापकों की हालत दयनीय हो, सोचनीय हो। उन अध्यापकों के हाथ में हमारे होनहार बालकों के जीवन को सौंप दिया जाय। हम अपने देश के साथ जुआ खेलना चाहते हैं मैं आपको जुए की बात बताना चाहता हूं। राजस्थान के बड़े—बड़े नगरों में रात को फीचर चलता है जिसको सारा पुलिस महकमा जानता है लेकिन सबका कुछ न कुछ हिस्सा ठहरा हुआ है, सौदा ठहरा हुआ है, कोई भी कर सकता है। यह तो रोज की बात है। मेरे पाली शहर में भी रोज पांचा, चौका खुलता है और गुब्बा करते हैं गरीब मजदूरों के पैसों से। आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आप पहले इन जुर्म करने वालों को पकड़ें। आपका पुलिस महकमा काम करता है लेकिन गांव—गांव में मीणा लोग चौथ लेते हैं। आपका इन्तज़ाम वहां नहीं चलता। किसकी ताकत है कि बैलों को उनसे बचा सकें आपका पुलिस स्टेशन भी नहीं बचा सकता। जो गरीब किसान हैं उनको ३० रु० या ४०) मन के भाव से भी अनाज लाकर मीणों की झोली में डालना पड़ेगा। जिसको आप स्वराज्य और समाजवाद कह सकते हैं वह हमें सेक्रेटेरियट या एसेम्बली भवन में नहीं चाहिये। हम इसे छोटे-छोटे गांवों में चाहते हैं, जहां आपके संदेश और नेताओं के भाषण नहीं पहुँच सकते या बड़ी-बड़ी पंच-वर्षीय योजना की किताबें नहीं पहुँच सकतीं या जहां पर जन संपर्क कार्यालय की विज्ञप्तियां नहीं पहुँच पातीं। हम समाजवाद को उस कोने में ले जाना चाहते हैं जो कौना बन्द है। यह है आप का दृष्टिकोण।

सभापति महोदय, आपने यू० डी० सी० क्लर्क की इज्ज़त से एक शिक्षक की इज्ज़त को कम समझा है। राजस्थान में हम शिक्षा का फैलाव करना चाहते हैं, जिससे पढ़ कर चका चौंध हो जावें, आदमी गिर पड़े। हमने जगह-जगह स्कूल खोले हैं और हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा इन्सान खड़ा किया है जिसमें खून नहीं हैं, जिसमें तेज नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है। खाली हड्डियों का ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। राजस्थान में सुन्दर इमारत खड़ी करना चाहते हैं। गुरुकुलों में जैसे कहा जाता था कि कुंए पर जाकर धोती धो लाओ या बाड़ी में जाकर सब्जी ले आओ तो विद्यार्थी ये काम करते थे। लेकिन आज यदि कहा जाय तो साइकिल लेकर सैर करने निकल जायेंगे। मैं मावली से आने वाले साहित्यिक पुरुष से कहना चाहता हूँ कि वे गांवों में जाकर इन स्कूलों में घूमें और उनकी हालत देखें, या शिक्षा मंत्रीजी या शिक्षा सचिव या अन्य अधिकारी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने भेजें। इन पाठशालाओं में मदरसों में भेजें, जहां आपके शिक्षक एक बनिये की तरह बैठते हैं, आप किस तरह से देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनका ग्रेड एक यू० डी० सी० के ग्रेड से भी कम है जो

Page No.86

(श्री मूलचन्द डागा)

कागज़ों के साथ खेलता है। इनका ग्रेड राजस्थान में या अन्य सरकार में ऊंचा हो सकता है लेकिन जो बालकों का जीवन निर्माण करता है उसका ग्रेड इनके ग्रेड से भी कम होता है। क्या है यू० डी० सी० का ग्रेड : ८०. ५. १२०. १०. २२०. और एक अध्यापक जो २० साल तक अध्यापकी करके अपना जीवन बिताता है उसका ग्रेड क्या है ? ६०. ४. ८०. ५. १३० । बालकों के साथ जो खेल करते हैं उनके जीवन में रौनक पैदा करना चाहते हैं, उसके जीवन की कीमत आपके समाजवाद के ढांचे में यह है और कागज़ के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनकी कीमत यह है। इसी कारण से इन शिक्षकों के पास जो बालक पढ़ते हैं, उनकी हालत क्या होती है यह भी देखिये। मैंने अखबार में पढ़ा था भरतपुर के बच्चों ने साइकिल की चोरी करली...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : भरतपुर में नहीं, पाली में हुई होगी ?

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) मैंने अखबार में पढ़ा कि भरतपुर में स्टूडेन्ट्स ने साइकिल की चोरी की, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों ने साइकिल के सीट की चोरी की। यह हालत है आपकी शिक्षा की। जो लड़के आज चोरी करना सीखते हैं वे आगे चल कर राजस्थान की गरीब जनता को क्या छोड़ेंगे। पिछली बार जब जोधपुर गये, तब इंजीनिरिंग कॉलेज के लड़कों ने किस तरह का प्रदर्शन किया था। क्या ये बातें हमारी शिक्षा पर गर्व करने वाली हैं ? इस पर भी हमारी शिक्षा को फैलाने वाले कहें कि हम उन्नति कर रहे हैं। हमारे राज्यपाल के प्रति, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के प्रदर्शन करें और लड़कों को चोरी करने की आदत हो और इस पर भी हमारे शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और अन्य शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारी और कर्णधार उन पर गौरव करें, तो मैं कहूंगा कि यह राजस्थान के भाग्य के साथ खिलवाड़ करना है। हमें ज़रूरत नहीं हैं उन छोटे-छोटे टटपूंजिये टीचर्स की जिनके विचार कंगाल हों। आप ऐसे-ऐसे टीचर्स भेजते हैं जो बच्चों के भाग्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपना हौंसला बढ़ाते हैं। इससे तो बेहतर है कि हमारे आदमी पढ़े लिखे न हों। आप प्रजा राज्य और लोकतन्त्र राज्य कायम करना चाहते हैं उसके जो कर्णधार बनने वाले हैं उनकी ओर मैंने संकेत किया। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही, मैंने भरतपुर के छात्रों की बात कही। क्यों नहीं आप इनको देखते हैं, अब आपके जागने का समय है। शिक्षा मंत्री सबों के घरों पर जाकर देखें। मदरसे की क्लासेज़ चल रही हैं। एक टीचर के घर पर बीस-बीस लड़के ट्युशन करते हैं और रुपये कमाते हैं। हर घर में बाल बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान कॉलेज जैसी कॉलेजेज़ सब जगह खुलें। आपने गांवों में मामूली स्कूलें खोली हैं। वहां अध्यापकों को आप ४० रुपये देते हैं। आपने लड़कों की फीस माफ कर दी है। हमें आपकी इस प्रकार की शिक्षा मुफ्त में भी नहीं चाहिये। जो शिक्षा बच्चों की विचार धारा को बदल सके, उस शिक्षा के हित में हम सोचना चाहते हैं। जिसका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। यह कोई किसी गवर्नमेंट की बदनामी का सवाल नहीं, यह आपके और मेरे विचार करने का

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल है। मेरा यह फर्ज नहीं कि मैं आपको बात कहूं और आप ताना कसें और मेरे दिमाग में कुछ और बातें पैदा करें। इस लिये मैं मन्त्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कॉलेज में भाषण करें, कभी मन्त्री महोदय का भाषण कॉलेजेज़ में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कमान्ड नहीं कि कॉलेज़ेज में विद्यार्थियों के सामने भाषण दे सकें, उनका व्यक्तित्व कमजोर हो चुका है। लेकिन क्या करें यहां तो उन्हें ग्रामीणों में बोलना है, जो कुछ नहीं समझते। कुछ मंत्री अच्छे होते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : वेष बदल कर जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) जब मनुष्य का व्यक्तित्व कमज़ोर होता है, उसका व्यक्तित्व गिर जाता है तो वह शासन नहीं कर सकता। शासन करने वाले का कमान्डिंग व्यक्तित्व होता है। जब कमान्डिंग व्यक्तित्व नहीं होता है, व्यक्तित्व गिर जाता है तो फिर छल-कपट, कुनबा परस्ती जिनका कि ज़िक्र अखबारों में पढ़ने को मिलता है, कुनबा परस्ती और छल-कपट के आधार पर शासन करते हैं। चलाने वाले भी भूल जाते हैं, कि हमें क्या करना है ? इसी लिये तो विरोधी दल-वाले कहते हैं कि इस युग में जहां व्यक्तिवाद पनप चुका है वहां हम सामुहिकवाद को पनपा नहीं सकते। उनका क्या दृष्टिकोण है ? उनका यही तो दृष्टिकोण है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि इस स्वार्थी युग में सामुहिक-वाद पनप नहीं सकता, इसीलिये तो उनका कहना है, उनका विद्रोह करना है। एक दफा मैंने पूछा जसवन्त कॉलेज में विद्यार्थियों से, उन्होंने कहा कि मन्त्रीजी तो हमारे प्रेसिडेन्ट से भी हल्का बोलते हैं, मैंने कहा कि आप उनकी बातें समझ नहीं सकते होंगे, वे तो सीधी और ऊंची बातें कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसी बातें कह गये कि हम कह नहीं सकते।

तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सत्तारूढ़ होना चाहता है, सत्ता संदरी पर आसीन होना चाहता है, और किसी पद पर आसीन होना चाहते हैं तो फर्ज हो जाता है कि अध्ययन ज़ारी रखें। एक दफा श्रम मंत्री पाली में गये, पाली मिल के मैनेजर ने कहा कि चाय पीजिये, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं मजदूरों के लिये आया हूं, मैं मजदूरों के यहां चाय पीऊंगा। इस चीज़ ने बड़ा असर किया मजदूरों पर और उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं आया जो मिल मैनेजर के यहां खाना खाये बगैर गया हो। क्या आज तक कहीं मंत्री जी को रिक्शा वालों ने बुलाया है ? मोहनलाल दूगड़ या बड़ी-बड़ी कम्पनियों वाले बुला लेंगे। जिस दिन गरीब लोग अपनी झोंपड़ियों में आपको बुलाने लगेंगे, आपका आदर करने लगेंगे, अपने हृदय के आसन पर आपको बिठलाने लगेंगे, उस वख़्त हमारा मन्त्री-मण्डल और हम गर्व के साथ राज्य कर सकेंगे। पर आज हमारा स्वागत करने वाले पूंजीवादी हैं, हम बैठते हैं पूंजीपतियों की गाड़ियों में और आप चाहते यह हैं कि गरीब लोग आपका आदर करें।

मैंने एक जगह पढ़ा था कि खूबसूरत लड़की को कलाकार होने की जरूरत नहीं।

(हंसी)

(श्री मूलचन्द डागा)

दिमाग की जरूरत नहीं, इसी प्रकार सेक्रेटेरियेट के ऊंचे पद पर सेक्रेटरी होना चाहिये, गुणों की आवश्यकता नहीं। कोई लड़की खूबसूरत तो हो परकलाकार न हो, उसमें दिमाग न हो, केवल उसमें खूबसूरती होनी चाहिये। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम ऊंचे पदों पर आसीन हों, पद के काम की गुणों की परवाह नहीं, क्योंकि आप पद पर आसीन हैं। इसीलिये कहा जाता है कि पदयात्रा मत कीजिये, हम तो सारे के सारे पदों की यात्रा करते हैं, पथ यात्रा रखिये। हम, पदयात्रा के अच्छे उद्देश्य हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं।

मैंने व्यक्तित्व की बात कहीं, सारे राजस्थान के वातावरण में मंत्री मण्डल के व्यक्तित्व की छाप पड़ती है, और वह अमिट छाप होती है और लोगों के दिलों पर उसके निशानात होते हैं, उसके परिणाम होते हैं। राजस्थान के दिमाग में बीज बो सकता है तो बीज बोने वाला हमारा सेक्रेटेरियेट है हमारा मन्त्री मण्डल है, इसलिये हमारे अन्दर वह चीज है तो डंके की चोट से कह सकते हैं, कि एक मदारी लाखों पर कन्ट्रोल कर सकता है, महात्मा गांधी को भी लोग मदारी कहते थे उन्होंने चिमटी में धूल ले कर जवाहरलाल और सुभाष पैदा कर दिये। अगर हमारे मन्त्री-मण्डल में भी कमॉन्डिंग व्यक्तित्व हो तो १७६ को अपने में मिला कर, अपने साथ ले कर राजस्थान की काया पलट कर सकते हैं। तो इस नक्शे को सुन्दर बनाने की एक बात मैंने रखी। मैंने शिक्षा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया। तकावी का तरीका, क्योंकि आपका बड़ा प्रिय विषय है, अभियान चल रहा है, आपका योग, श्रम कीर्ति सभी इसमें मिली हुई हैं। क्या है, आप क्या चाहते हैं देश में? क्या आप चाहते हैं कि देश के किसान ऊपर उठें, जिंदगी भर ही आपत्ति के पापड़ ही नहीं बेलते रहें, आखिर उनको भी आराम मिले। लेकिन श्रीमान् आप जो तकावी देना चाहते हैं, उस प्रोसीज़र पर भी कभी आपने ध्यान फरमाया है? एक किसान जिसके पास जमानत देने वाला नहीं हो तब तक उसे तकावी नहीं मिल सकती। उसे ५ बार तहसील का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, मंजूरी होने पर एम, एल. ए. के मुंह की ओर ताकना पड़ता है, पटवारी के दरवाजे पर नाक रगड़नी पड़ती है, सरपंच की खुशामद करनी पड़ती है। और इतना करने के बाद उसको मिलता है, २५० रु० बैल जोड़ी के लिये और ४००) रु० कुंएं के लिये। वह गरीब समझता है दुनियां के किसी कोने में उसे रुपया नहीं मिल सकता, इस लिये उसे तहसीलों और पटवारियों के द्वार खटखटाने पड़ते हैं, एम. एल. एज़. का मुंह देखना पड़ता है, तहसीलदार के दफतर के बाहर चपरासी के धक्के खाने पड़ते हैं।

आप समझते हैं, जानते हैं फिर क्यों नहीं यह रुपया पंचायतों को दे देते। शायद आपको हंसी मालूम होगी कि पंचायतों को रुपया दे देंगे तो यह करप्शन फैला देगा। आप उनको अधिकार भी देना चाहते हैं और फिर उनमें विश्वास भी नहीं करना चाहते तो यह अलग बात है।

मैंने भाषण को पढ़ा, एक्सपेन्डीचर का क्या हिसाब है, आपकी किताब निकाली हुई है उसकी दो-दो लाइनें पढ़ना हूं, कितना खर्च आता है और कितना आप कम करना

Page No.89

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहते हैं । मुख्य सचिव तो गलती को फौरन एड्मिट करते हैं । यह नहीं कि वे अपनी गलती मंजूर नहीं करते हों । वे अपनी गलती फौरन मंजूर कर लेते हैं । यह भी एक कार्य करने का तरीका है । मुख्य सचिव ने प्राक्कलन समिति में बताया है गाड़ियों पर कितना खर्चा हमें करना चाहिये । उन्होंने बताया कि जहां तक गाड़ियों पर होनेवाले खर्चे का संबन्ध है, मुख्य सचिव ने बताया कि १९५३ में गाड़ियों का खर्च ९,८५,००० रुपये बताया गया था और अब यह करीब २२,८६,००० रुपये हो गया है । जहां गाड़ियों की संख्या में केवल ४० प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है वहा खर्चा लगभग १५० प्रतिशत बढ़ गया है और ऐसा क्यों हुआ इसका भी मुख्य सचिव कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सके । यह तो हमारे यहां पर जो गाड़िये चलती हैं और दौड़ती है उसका हाल है । सड़कें बड़ी लम्बी २ बनी है । गाड़ियें इसलिये है कि समय की बचत हो । समय पर पहुंच कर कहीं पर अपना काम कर सकें । मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता । समय की पाबन्दी नहीं की जाती है । मोटरें होते हुए भी मैंने एक स्थान पर गृह मंत्रीजी के भाषण में देखा है कि उनके भाषण को सुनने के लिये एक लाख की जनता खड़ी है और आप समय पर वहां नहीं पहुंचते हैं । एक घंटे बाद वहां पर पहुँचते हैं । एक लाख आदमियों का एक घन्टा यानि १ लाख घन्टे योंही उनकी इन्तज़ार में खर्च हुए । इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कलेक्टर कभी भी दफ्तर में समय पर आना जानता है, हरगिज़ नहीं । गाड़ी होते हुए भी यह हाल है कि समय पर नहीं पहुँच सकते । आपने उनको गाड़ियें दे दी है । इस संबन्ध में आपके मुख्य सचिव कहते हैं, मैं आपकी निकाली हुई किताबों के आधार पर ही यह कहता हूं । आपकी निकाली हुई चोपड़िये हैं । यह नहीं कहदें कि यह आपकी निकाली हुई नहीं है । यह आपकी ही लिखी हुई है और इसमें मुख्य सचिव महोदय ने स्वीकार किया है कि गाड़ियों का दुरूपयोग होता है । मुख्य सचिव ने स्वीकार किया है कि यह सही है कि गाड़ियों का दुरुपयोग होता है, इस संबन्ध में आवश्यकता से अधिक उपयोग होता है, गैर सरकारी कार्यों के लिये उपयोग होता है, इस संबन्ध में ज़ारी किये गये नियमों का सम्यक पालन नहीं होता । आप यह कहते हैं कि हमारी आदत हो गई है । हम तो आदत के आदमी है । हम करते हैं और करते चले आ रहे हैं । यह आपकी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है उसमें बताया है ।

दूसरा पुलिस का खर्चा, १९५०–५१ में जो खर्चा होता था उससे यह स्पष्ट है कि अब खर्च में भी बढ़ोत्तरी हुई है । १९५०–५१ में बजट था २ करोड़ और कुछ लाख और अब हो गया है ३ करोड़ ९३ लाख आप यह कहते हैं कि चोरियें डकैतियें कम हो गई है । इसलिये पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है । मगर फिर भी आप कहते हैं कि यह खर्चा डाकुओं के पीछे दौड़ने से बढ़ा है । फिर यह खर्च ३ करोड़ ९३ लाख बजट में बढ़ा है । चोरियों की कमी हुई है और आपका खर्चा बढ़ा है । समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं । यह प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है जो श्री मोतीलालजी चौधरी की अध्यक्षता में हुई है । यह आपकी ही कमेटी है । इसमें और भी बहुत लम्बी चौड़ी बातें

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं पढ़ूंगा तो काफी समय लगेगा। एक स्थान पर मैं गया और मैंने वहां के गांव के लोगों से कहा कि तुम्हारे यहां पुलिस चौकी नहीं है लगवा दी जावे तो वे कहने लगे बाबूजी माफ करिये। भगवान इनसे बचावे। गांव वाले इन लोगों से इतने घबराते है कि उनके ऑफिस तक को वहा रखना नहीं चाहते। जिन भाइयों से हमारी और हमारे देश की रक्षा होती है और जो हमारी जान और माल की रक्षा करने वाले कहलाते है और गांव वाले तो उनको मां बाप कहते हैं, उनको अपने गांव में देखना नहीं चाहते। गांव वाले कहते हैं कि पुलिस वाले तो हमारे मां बाप हैं। मगर फिर भी वह पुलिस एजेन्सी को अपने गांव में रखना नहीं चाहते। वे यह कहते हैं कि हमारे गांव में और भी कई अधिकारी आते हैं। उन गांवों में तहसीलदार का दौरा १० दिन हो जाता है। माननीय राजस्व मंत्री कहेंगे कि दौरे करना तो बहुत जरूरी होता है और दौरा करना ही चाहिये मगर मैं यह कहूंगा कि एस० डी० ओ० साहब शुक्रवार को दौरे पर चले जाते हैं और तीन दिन वहां पर रहते हैं। वहां पर उनको दूध दही और घी खाने को मिलता है। आप जाकर पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारे के सारे अधिकारी दौरा करने चले जाते हैं। एग्ज़िक्युटिव इंजीनियर को पूछो तो आपको मालूम होगा कि वह दौरे पर गया है। वेटरनरी ऑफिसर को पूछो तो मालूम होगा कि वह ऑफिसर भी गांव में है। लोग कहते हैं कि ऑफिसरों की तादाद बढ़ गई है। सेठ लोगों के यहां दूध की खीर बनती है और सेट यों ही रह जाते हैं खीर मुनीम लोग ही खा जाते हैं। आपने ऑफिसरों को गांव में ढेर के ढेर पैदा कर दिये हैं। वे लोग सारे टी० ए० और डी० ए० उठाते हैं और खाना दूसरों के मकान पर खाते हैं। समझ में नही आता एस० डी० ओ० क्यों दौरे पर जाते हैं? पटवारी हर महीने की १, २, ३ और ४ तारीख को तहसील के हैड क्वार्टर में रहता है। वहां पर सारे पटवारियों का रहना जरूरी है। एस० डी० ओ० तहसीलदार, नायब तहसीलदार, दरोगा सब ढेर के ढेर आपने लगा दिये हैं। आपने अफसरों का ढेर लगा दिया है। आपने उनको बैठने के लिये अच्छी जगह दे रखी है, एक टेबल दे दी है और अच्छी सी दवात दे दी है और जब उनसे पूछते हैं कि यह कौनसा दफ्तर है तो वे कहते हैं कि यह इन्डस्ट्रीज़ का दफ्तर है। क्या काम करते हो तो कहते हैं कि दिन भर में तीन चार कागज़ निकाल कर चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ पूछते हैं कि यह कौनसा दफ्तर है तो मालूम होता है कि यह भेड़ और ऊन का महकमा है। क्या काम करते हैं तो उत्तर मिलता है कि काम कुछ नहीं है सुबह दफ्तर आते हैं और शाम को आराम से घर चले जाते हैं। यह मैंने देखा है। जब मैंने यह देखा तो मेरे दिल में दर्द हुआ। समझ में नहीं आता कि आपके एस० डी० ओ० तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, दरोगा ये सब गांव गाव में एक छोटी सी तहसील में घूमते हैं समझ में नहीं आता कि आखिर आप चाहते क्या हैं? जांच करना चाहते हैं तो यह भी कुछ नहीं होती है। मगर मैं यह कहूंगा कि आपका कानून टी० ए० और डी० ए० का ऐसा है कि अगर रात को गांव में नहीं रहे तो टी० ए० और डी० ए० नहीं मिलेगा। इसलिये बेचारों को पाहुनों की तरह रहना ही पड़ता है और यह

(श्री मूलचन्द डागा)

बातें हमारे सामाजिक जीवन को अनुचित कर देती है। क्योंकि जो सरपंच उनकी खातिर करता है या जिस सरपंच पर अफसरों का धामा होता है, जो सरपंच तहसीलदार और वेटरनरी डॉक्टर और दूसरे लोगों की थालियें साफ करता है वह कोई अपने घर से खर्च थोड़े ही करता है। वह तो गांव वालों से ही लेता है। वहां पर तहसीलदार साहब, एस० डी० ओ० साहब आदि का बड़ा स्वागत होता है, उनके स्वागत के लिये नारे लगते हैं तो फिर वह मनमानी क्यों न करेगा। अगर कोई बात हुई तो तहसीलदार, एस. डी. ओ. साहब से कहेंगे एस, डी. ओ. साहब कलेक्टर से कहेंगे और उनको सलाम बोलेंगे। इस तरह से सारे चापलूसी का सर्कल या यों कहिये कि चापलूसी के सर्कल में पनपने वाले हैं उनका बोलबाला रहेगा। हम हिन्दुस्तान में भूमि सुधार के लिये पंचायतों को अधिकार देने वाले हैं। इसलिये जब तक इस मशीनरी की जांच करने वाले निष्पक्ष ऑफिसर न हों जिसे इस बात का ख्याल न हो कि यह देश मेरा है और देश से उसको प्रेम हो, और मैं जो राज्य करता हूं वह जनता की भलाई के लिये करता हूं तब तक कोई सुधार नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि वे यह समझें कि यह आये दिन की बातें हैं इन पर क्या ध्यान दिया जाए। हमारे यहां पर जिनको नगाडे के ऊंट कहना चाहिये, उनके लिये कई भाषण हो गये हैं। वहां पर तो आप देखेंगे कि सब पूरा जमा जमाया काम है। जो लोग वोट लेकर आते हैं और कुछ कहते हैं उनका कोई असर नहीं होता और सब दूसरे लोग मनमानी करते हैं। पटवारी अपनी मनमानी करेगा और अगर कोई एम. एल. ए. उसके लिये कहेगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या एक एम. एल. ए. पटवारी से गया गुजरा है ? उसकी डायरी में लिखा है। उस डायरी में जिसमें लिखा होगा कि मेम्बर पटवारी से नीचा है, वह मुल्क डेमोक्रेसी के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमान्, कुछ बातें मैंने आपको गांवों की तरफ की, तकावी की कहीं और अब मैं आपका ध्यान दूसरी ओर लेजाना चाहता हूं।

श्रीमान् एक बात बहुत जोरों से हर जगह सुनाई देती है और नागपुर कांग्रेस का जब से रिज़ोल्यूशन बना और लोगों के दिमाग में आया कि सहकारी समितियां कायम की जांय और सहकारी समितियों के आधार पर हम पंचायतों को भूमि देना चाहते हैं और उसके आधार पर नयायुग बनाना चाहते हैं। एक इतना छोटा मसला है और उस मसले को कई रूप से कहा, नेताओं ने अलग अलग रूप से कहा। इसको श्री राजगोपालाचार्यजी ने और ढंग से रखा, पहले के जो भूतपूर्व गवर्नर थे यू. पी. के प्रान्त के उन्होंने अपने ढंग से रखा। अब सवाल है कि जब मेरठ में नेहरू जी बोलने लगे तो और उन्होंने इसको और ढंग से रखा। क्योंकि एक बात यह है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सवाल जबरदस्ती से थोपा नहीं जावेगा, सारा ही मामला खत्म हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे एक बात रख दी है कि हम इस मामले को जबरदस्ती से थोपना नहीं चाहते। इसका मतलब भी सही है। हमारे देश में हर कुंए पर, खेती पर पहले से ही कुछ लोग अपने आप मिल कर काश्त करते हैं, कोई यह बात कहे कि सहकारिता की भावना हमारे में नहीं है, मैं उसको नहीं मानता, कई युग से यह है, हम जहां पढ़े

(श्री मूलचन्द डागा)

लिखे हो जाते हैं तो हमारे एक दूसरे की बातें टकराती हैं और बातें टकराने के कारण खुजली पैदा हो जाती है और जब खुजली पैदा हो जाती है तो हम अपने आपको बहुत होशियार समझने लग जाते हैं।

(हंसी)

उनका अपना दिमाग है लेकिन काश्तकार का अपना दिमाग है। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था कि किसी आदमी से यह ख्याल करके न चले कि वह नाराज हो गया है। जब आदमी साथ बैठते हैं तो एडजस्टमेन्ट होता है, उनके विचारों में मेल बैठता है। लेकिन अलगाँव रखने से दूर दूर रहने से मनुष्य को दूर दूर ही कर देता है। हम अपने खेतों में जबरदस्ती के आधार पर नहीं, सब की भावनाओं में एकीकरण है तो उस एकीकरण के आधार पर यहां हम काम करना चाहते हैं। तो इस पर हमें कोई यह कहे कि कांग्रेस ने यह शुरु कर दिया है, कांग्रेस की कोई चीज़ को समझने की, उस पर विचार करने की और उसकी जो आधारशिला है उस पर मैं विचार करना चाहता हूँ।

राजस्थान में खाद्य समस्या ने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। मैंने सोचा कि अधिकारियों के दिमाग में आखिर क्या बात थी। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि पाली जिले में अन्न की कमी है, मैं कहता हूँ कि जो तहसील ऐसी है कि जहां कितना मन अनाज है, मंत्री महोदय बैठे हैं जो पाली में रहते हैं वे कह सकते हैं कि कितना अनाज है। लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि वहां पर किसी पार्टी के चक्कर में आकर पर्मिट सिस्टम कर दिया, जो आपके सेक्रेटेरियेट में नहीं है। मंत्री महोदय ने ऑर्डर्स दिये होंगे, वह इश्यु कर दिया, पर्मिट दिया जाय और राजनैतिक पार्टी ने उसका फायदा उठाया उन्होंने क्या किया। एक दुकान पर १०) के अन्न के पर्मिट बांट दिये, कंट्रोल की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। आप बार बार कहना चाहते है कि हम बनियों को खत्म करना चाहते हैं, काला बाज़ार करते हैं, कांग्रेस की भाषा यह नहीं है। शासक वर्ग को ऊंचा लेकर उन लोगों को दबाने की कोशिश की है। बिना किसी कसूर के हथकड़ी डालकर चालान कर दिया और वह भी शनिवार को ताकि रविवार को तो रखा ही जाय। अब तो अन्न का अभाव कम होना चाहिये था, लेकिन सुमेरपुर में एक सेर और १॥ सेर का मिल रहा है, आप कहते हैं कि हम पाली में दो सेर से कम नहीं बिकने देंगे। सारे काश्तकारों ने अपनी ताकत लगा कर दूसरी मंडियों को ढूंढा जहां कि अनाज मंहगा मिलता था। जितने कानून हैं उनमें आपके अधिकारियों का अधिकार रहना चाहिये। पाली में दो सेर का धान बिकता रहे, कांग्रेसियों को लोग गालियां देते रहें, बदनाम करते रहें, कोई वकील नहीं चाहेगा कि चार घंटा लाइन में खड़ा रहे फिर दो रुपये का आस्ट्रेलिया का गेहूँ उसको मिले, मैं बेहतर समझूंगा कि जैसे जो कुछ जिस भाव मिलता है जल्दी लेकर चला जाऊं। उन लोगों को दूकानें मिल गई जिनकी पहुँच है। पहली बार मैंने असेम्बली में कहा। कहा गया कि जांच करा ली। उसके बाद दी गई सी. आई. डी, डिपार्टमेन्ट को, उसकी रिपोर्ट अच्छी है। लेकिन फिर भी हमारे अधिकारी वर्ग कोटा से धान लाने के लिए पर्मिट देते है। लोग कहते हैं इस सरकार में तरीके से कमाते जाओ, मौका है। आप होर्डिंग को चेक करिये लेकिन यह कहा कि दो सेर का बेचा जाय। अलग

Page No.93

(श्री मूलचन्द डागा)

अलग तहसीलों में अलग अलग भाव से बिक रहे हैं और यहां तक कि सवा सेर का बिक रहा है। छोटी २ गलतियो में हथकड़ी डाल कर चालान कर देते हैं, वह भी शनिवार को पुलिस वाले ले जाते हैं और रविवार को खोड़े में पड़े रहे। इससे तो राज्य के प्रति घृणा पैदा होती है, शासन के प्रति घृणा पैदा होती है। मैं यह प्रार्थना करूं कि यह फूड की जो प्रोब्लेम है उसको जिस कानून के आधार पर आपने पहले चलाई उसी आधार पर इसको चलाना चाहिये।

अब मैं दो लाख की जमीन के बारे में, जिस रोज मैं मौजूद नहीं था, कहना चाहता हूँ। चाहे कोई मेम्बर हो एक जमीन जो चार हजार रुपये में तो काश्तकार से ली और जो दो लाख की जमीन है उसको बेच दें ? वह दो लाख रुपयों को जमीन, प्रेसिडेन्ट म्युनिसिपल बोर्ड ने यह लिख कर दे दिया कि १४ आदमियों को दे दी जाय। म्युनिसिपल बोर्ड ने रिज़ोल्युशन पास कर दिया कि प्रेसिडेन्ट ने गलत आज्ञा दी है और मंत्री महोदय को सैंकड़ों आदमियों ने रिपोर्ट दी और तार दिये कि जमीन दी गई है वह गलत दी गई है। रेवेन्यु मिनिस्टर बतायें कि आबादी में कन्वर्ट करने के लिए तीन हज़ार, चार हज़ार में जमीन जो दो लाख की थी काश्तकार से ले ली और किन आदमियों को दी गई, मैं बताऊंगा। उनकी बड़ी शानदार दर्ख्वास्त है। सारे देश भक्त इकट्ठे हो गये हैं। बड़ी सुन्दर दर्ख्वास्त लिखी है। १४ आदमियों ने दर्ख्वास्त लिखी उसकी लैंगवेज़ मैं आपको सुनाता हूँ।

श्री सभापति : Do you want to place it ?

श्री मूलचन्द डागा : Yes Sir. मैंने पहले पेश कर दी है, कॉपी होगी और मैं फिर तैयार हूँ। वहप्रार्थना-पत्र इस प्रकार हैं :

श्री अध्यक्ष नगरपालिका पाली।

प्रार्थी गण,

१. कालूराम वल्द अनोपचन्द पोरवाल साकिन पाली। जिनके पास करीब दो लाख रुपये की दौलत होगी, वे भी इस प्रार्थीगण में है।

२. शंकरलाल वल्द सोहनदास वैष्णव साकिन पाली जो हमारी विधान सभा के मेम्बर हैं।

३. बरकतअली वल्द ईलाही बक्स सीरवर साकिन पाली। जिनके पास हजारों बीघा जमीन होगी।

४. धनराज वल्द भुरालाल वर्मा साकिन पाली।

५. सुमेरराज वल्द वीरचन्द डागा साकिन पाली। जो मेरे बड़े भाई साहब हैं जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है। बड़े साहूकार आदमी हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): क्या आपका उनसे झगड़ा है ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे और उनके क्या लड़ाई ? वे मेरे बड़े भाई हैं तो क्या मैं उनका नाम न लूं ? लानत है उन

(श्री मूलचन्द डागा)

लोगों पर जो ऐसे मामलों में अपने पुत्र या भाई वगैरह के नाम आने पर पक्षपात करते हैं। मुझे शर्म नहीं आती उनका नाम लेने पर।

६. वल्लभदास वल्द श्रीकिशनखत्री साकिन पाली।

७. युसुफ वल्द गफूरअली रंगरेज़ साकिन पाली।

८. वीणादेवी जोजे पी० डी० भार्गव साकिन पाली ये उन सख्श की पत्नी है जिन की हमने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार करवाया था। ये हैं उन्हीं भार्गव साहब की धर्म पत्नी।

९. भोमसिंह वल्द भगसिंह साकिन पाली। जो प्रसिद्ध वकील हैं।

१०. मोअीनदेवी जोजे मोहम्मद अमीन सोरगर साकिन पाली।

११. रामनिवास वल्द ऊबेराम धाबी साकिन पाली।

१२. देवरत्न वल्द केनीराम ब्राह्मण साकिन पाली।

१३. मनरुपरामजी वल्द मालाराम परिहार भावी : साकिन गगनीपुरा जिला पाली. ये हमारे विधान सभा के सदस्य हैं।

१४. भीकमचन्द वल्द पूनमचन्द साकिन पाली। ये काफी अर्से तक सरपंच रह चुके हैं।

इस दर्ख्वास्त का पहला सेन्टेन्स आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनन्द आयेगा वे लिखते हैं।प्रार्थीगण सार्वजनिक देश में सेवा कार्य करने वाले कर्त्ता है और पाली नगर में.. ये प्रार्थीगण सार्वजनिक सेवा कार्य करने वाले हैं। सभापति महोदय इसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में कभी पांव नहीं रखा सिर्फ तीन चार के अलावा। पाली नगर में सहकारिता के आधार पर स्वच्छ आदर्श व स्वस्थ वातावरण में मकान बनाना चाहते हैं जिसके लिये सरकार द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकार द्वारा हर प्रकार का सहयोग व सहायता प्रदान करने की घोषणा की हुई है।

मैं समझता हूं कि जिस भाषा में यह प्रार्थना-पत्र लिखा गया है शायद वैसी भाषा हमारे जन्नू भाई भी प्रयोग में नहीं लाते होंगे। स्वच्छ वातावरण में मकान बनाना चाहते हैं जिसके लिये सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा हर प्रकार का सहयोग व सहायता प्रदान करने की घोषणा की हुई है।

डॉ० चन्द्रकला ने भी कई किताबें पढ़ी होंगी और डॉक्टरेट लिया है, लेकिन ऐसी सुन्दर भाषा का प्रयोग उन्होंने भी नहीं देखा होगा।

आगे वे प्रार्थना-पत्र में लिखते हैं सभापति महोदय,

प्रार्थीगण ने पाली नगर के समीप सेशन कोर्ट के व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेट्रोल पम्प के बीच की जगह व पीछे सोजत रोड की सड़क की तरफ की जमीन मुसमीयान तारा वल्द

(श्री मूलचन्द डागा)

हरजी वल्द तारा टीकमचन्द वल्द गेना सोनी बेवा गेना राजु वल्द तारा से खसरा नं० ६१४ रकबा बीजा दसरा नं० ६१५ रकबा बीगा व खसरा नं० ६१७ रकबा बीगा ५००० से खरीद-कर रजिस्ट्री करवा दी है ।

यह है कि इन्ही आसामीयान की बापी की ज़मीन सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट के लिये एक्वायर की गई और शेष ज़मीन भी आबादी के बिल्कुल उपयुक्त है। अत: श्री कलेक्टर साहब पाली को प्रार्थीगण के उपरोक्त खरीद सुदा बापी की ज़मीन को आबादी में परिवर्तन करने के लिये प्रार्थीगण को मकान बनाने की स्वीकृति दिलावें।

इसके नीचे उन सब के हस्ताक्षर हैं हैं जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। इस ज़मीन के सम्बन्ध में श्री शिवपुरी के ऑर्डर्स है। पी० डब्लु० डी० का नंबर भी मैं दे सकता हूं जिसमें इस ज़मीन को नहीं देने के लिये कहा गया है लेकिन फिर भी कलेक्टर ने उस ऑर्डर को पास किया है यह सब म्युनिसिपल चेयरमेन को मालूम है। मेरे ख्याल में उस जमीन को नाथूरामजी भी देख चुके हैं। उनको मालूम होगा सेशन कोर्ट के पास दोनों तरफ मेटल्ड रोड हैं। सोजत रोड की सड़क की तरफ उसके लिये कहा गया है कि प्रार्थीगण को आबादी में परिवर्तन करने के लिये वह मकान बनाने के लिये स्वीकृति दिलावें। उस पर म्युनिसिपल बोर्ड बिना बोर्ड को लिखे हुए रिज़ोल्युशन स्वीकृत कर देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो मेम्बर हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे भी कमेटी के चेयरमैन बुलाते हैं लेकिन जब बुलाते हैं जब कि मैं असेम्बली के कार्य के सिलसिले में जयपुर में होता हूं मेरा टिकट जयपुर के लिये कट गया होता है, उन दिनों में मिटिंग की जाती है।

एक माननीय सदस्य : क्या वह ऑर्डर आपके पास है ?

श्री मुलचन्द डागा : I got the order.

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री मूलचन्द डागा : उस पर हमने भी एक प्रस्ताव पास कराया जो इस प्रकार है :—

सेवा में सभापतिजी, नगरपालिका पाली।

हम सदस्यगण यह प्रस्ताव करते हैं कि सेशन कोर्ट के पास जो १४ व्यक्तियों को ज़मीन दी जा रही है उसे रोका जावे। ज़मीन आबादी में परिवर्तित होने के पश्चात् वह नगरपालिका की सम्पत्ति हो जाती है। उसे अलॉट, नगरपालिका जिन व्यक्तियों को चाहेगी, करेगी। जो रकम उन्होंने दी है वह नगरपालिका देने को तैयार है। कलेक्टर महोदय को व राजस्थान सरकार को यह पत्र बोर्ड की ओर से लिखा जावे कि यह भूमि जो आबादी में परिवर्तित की गई व योजनाबद्ध के रूप में नगरपालिका विक्रय करेगी। इस–लिये केवल १४ व्यक्तियों को नहीं दी जावे, क्योंकि उनमें से करीब सभी के पास एक से अधिक मकान हैं और वे पाली के समृद्धि–शाली व्यक्ति होने के कारण सस्ती कीमत पर

Page No.96

[redacted]

(श्री मूलचन्द डागा)

अलॉट की ज़मीन पाने के हकदार नहीं हैं इसलिये यह भूमि किसी तरह अलॉट नहीं की जावे और भूमि का कब्ज़ा नगरपालिका को शीघ्र योजना बद्ध रूप में विक्रय करने के लिये दिलाया जावे। ज़मीन का मुआवज़ा आबादी में परिवर्तित करने का प्रीमियम नगरपालिका देने को तैयार है। कलेक्टर महोदय को नगरपालिका की ओर से विशेष निवेदन किया जावे कि ज़मीन पर किसी भी व्यक्ति को कब्ज़ा नहीं करने देने बाबत शीघ्र आज्ञा जारी करें।

इकबालसिंह

मूलचन्दडागा

नारायण

मांगीलाल बौरा

मांगीलाल आर्य

मोहम्मद सदीक

शिवजी

चिमनी रामजी

मोहम्मद हुसनेजी।

यह रिज़ोल्युशन संबन्धित अधिकारियों व मन्त्री महोदय के पास भी आ चुका है लेकिन भगवान जाने अभी तक सफेद निशान लगाये जा रहे हैं, इन्जिनीयर लोग दौड़ कर रहे हैं। उनसे आप कहिये दौड़ धूप कम करें। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होने के बाद भी, राजस्व मन्त्री महोदय, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अभी तक वहां खड्डी का निशान लगाया जा रहा है और वे लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम इस ज़मीन को लेकर ही रहेंगे। वे सीना ताने जा रहे हैं न मालूम उनको इतना ग़रूर किस बात का है। मेरा कर्तव्य था वह मैंने पूरा कर दिया, आपके सामने हालात को रख दिया क्योंकि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सही बात को रख दे उसके बाद उसका असर होना न होना दूसरी बात है। इसके लिये आप हारजीत का सवाल मत बनाइये। सौदेबाजी आप कर सकते हैं लेकिन देश के लिये सौदेबाजी करने वालों से सावधान रहिये। आप देश के लिये सौदेबाजी न करे यही आपसे अपील है।

अब मैं म्युनिसिपेलिटी की बात कहकर अब पंचायतों की बात पर आता हूं। पंचायतों में हमने एक बात देखी वहां शिक्षित लोगों का बिल्कुल अभाव है। पंचायतों में काम करने वाले व्यक्तियों के शिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध है। आप जहां आर० ए० एस० की ट्रेनिंग के लिये लोगों को जोधपुर में कई महिनों की ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं जो पहले ही एल० एल० बी० पास होते है उनके लिये तो आप हजारों रुपया महिना खर्च करके शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। लेकिन पंचायतों के जो पंच होते हैं मैं आपसे अपील करूंगा पंचों के लिये भी कुछ शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिये जहां उनको मोटी मोटी बातों का ज्ञान कराया जा सके। इसकी व्यवस्था होना आवश्यक है। सेशन कोर्ट में जितने भी रिवीज़न आते हैं वे सब पंचायतों के सिलसिले में होते हैं। आज पंच यह समझते हैं कि आज हमारा ही राज है। इस प्रकार पंचों में यह बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वह आज घर घर में घुस गई है, जो चाहे वह मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। रिवीज़न में आपने चीफ़ पंचायत ऑफिसर को सेक्शन २७ के अन्तर्गत यह

(श्री मूलचन्द डागा)

अधिकार दिया है कि जो ऑर्डर वहां से हो गया वह फाइनल है। अगर उस पर किसी को एतराज़ हो तो वह हाई कोर्ट में जाय, वकीलों की जेब गरम करे और मुकद्दमा लड़ने वाले डी० ए० पकावे। और पंचायतों की इज्जत यह हुई कि हाई कोर्ट के जज उसके आर्डर को सैट असाइड करे।

श्रीमान्, आखिर में आप २४। २५ धारा के अन्तर्गत भी तो कुछ अधिकार देते हैं। वह आपने क्यों लगा दिया। जहां पर एक पार्टीकुलर क्लास है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और वहां जो आपका इन्टरफीयरेन्स है वह कहां तक है, यह पंचायत में सारे सैशन जज यह बात कहते हैं। इसके लिये अर्ज़ है कि जहां आपने सारी जूडीशियरी में बड़े-बड़े योग्य कर्मचारी दे रक्खे हैं वहां पंचायतों में भी यू० डी० सी० के केडर के क्लर्क देने चाहिये। सारी व्यवस्था उनको सिखाई हुई होनी चाहिये। म्युनिसिपैलिटी तक में आप २५०) पाने वाले आदमी भेजते हैं तो आप पंचायों में क्यों नहीं भेजते। जब आप पंचायतों को काफी अधिकार देने जा रहे हैं तो उनको कम से कम यू. डी. सी. केडर के क्लर्क भी तो दीजिये। आज तो उनके पास ऐसे क्लर्क हैं जो चौथी पांचवीं क्लास तक पढ़े लिखे होते हैं। मेहरबानी करके पंचायतों को अच्छा काम करने की नीयत से अपनी ओर से ऐसे काबिल और यू. डी. सी. ग्रेड के आदमी दें ताकि उनका भी स्तर ऊपर आ सके।

एक वकालत और करनी है। मेरे खिलाफ़ भी पर्चेबाजी हुई। बीड़ का मैं उदाहरण देता हूं। जब कभी मैं सोजत जाता हूं तो वहां के एस. डी. ओ. कहते हैं कितने मरडर केस हो गये हैं। आप स्टाल फीडिंग होंगे। चराई का प्रबन्ध क्या किया आपने। मुझे ही ताना देते हैं। सरकार की तरफ से काम वे करते हैं। ताना मुझे देते हैं। अगर उनके लिये सरकार के पास प्रबन्ध नहीं हैं, तो उनको आबू के पहाड़ों में भेज दीजिये। आखिर में आप इस बर्निंग प्रोब्लेम का क्या करेंगे गांव-गांव में झगड़ा होता है। कतल के मुकद्दमे चलते हैं। एस. डी. ओ. कहता है कहिये आपके राज में क्या है? मनमें नफरत करते हैं। जो चाहे ताना कस देते हैं। काम वे ही करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज यह जगह-जगह का एक बर्निंग प्रोब्लेम बन गया है। सरकारी हुक्म बड़ी सफाई से आते हैं। कहते हैं हम चराई उसी आधार पर लेना चाहते हैं जिस आधार पर हमारे से पहले जागीरदार लेते थे। राजस्वमन्त्री इससे सन्तुष्ट नहीं। उत्तर देंगे तो गोल माल ढंग से देंगे। खुद जानते हैं उनके अन्दर की कमजोरी है। हम नहीं चाहते अपनी कमजोरी वे ऊपर दिखावें। पर आपकी कमजोरी आपको खुद को मजबूर कर देती है। एक ऑर्डर निकाल दिया पहले जैसे वसूली की जावे। हमारा हक तो यह है कि चराने को जगह देते। जागीरदार के वक्त जमीन का काश्तकार हर खेत में घूमता था और चराई लेता था तीन रुपया चार रुपया। अब आप कहते हैं हम क्या करें हमने तो निर्णय कर लिया। प्रोब्लेम आपके सामने है।

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information, Sir. what is the Suggestion. वे क्या सुझाव देते हैं। पाली

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिले की उनकी तकलीफ किस तरह से मिट सकती है। आपके क्या सजेशन हैं इसके लिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् मैं आप को पांच मिनट में बताता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैंने कई बार बारीकी से सारे टिनेन्सी रूल्स पढ़ने थे, पढ़ लिये। मैंने काश्तकारों के साथ बैठकर बातें की। वे दो बातें चाहते हैं। एक तो यह कि खेत काटने के बाद, धान काट लेने के बाद उनके खेतों में चरने को छोड़ दिया जावे और इसकी एक फीस ले ली जावे। काश्तकार भी इसके लिये तैयार हैं। एक बात यह चाहते हैं।

दूसरी बात, यह चाहते हैं आपसे वे कि जिन जगहों पर आपके ग्रास फार्म्स हैं वहां कोई जगह नहीं है उस जगह आप गोसवारा बन्द करिये और आस–पास का कोई एरिया मुकर्रर करिये कि उसमें जाकर चराएं और उसकी एक चराई मुकर्रर कर दी जावे।

तीसरा सुझाव अगर आप चाहते हैं तो यह है कि जो पंचायतों के पास गोचर जमीन मुकर्रर है उनके लिये भी आप यह इजाज़त दें कि वे पंचायतें लोंग पापड़ी नीलाम न करें। बबूल के पेड़ को छांगने की इजाजत भी दी जावे। छांगने से पेड़ का नुकसान नहीं होगा। और वे छोटे छोटे मेमने होते हैं उनको इससे वे भरण पोषण कर सकते हैं। यह चाहते हैं वे। अगर इस पर भी आप कहते हैं कि हमारे आस पास जैसलमेर में ज़मीन ज्यादा है, आबू के पहाड़ में ज्यादा है तो मैं कहता हूं कि वहां जाने में मुश्किल होगी उन गडरियों को, कि वे पर्मानेन्टली वहां से हट जावें। आप चाहें तो हटा दीजिये। कोई तकलीफ नहीं होगी हमको। हम चाहते हैं एक सुलह समझौता, एक आपस का परस्पर का समझौता, बातचीत। हम नहीं चाहते कि तनातनी हो और इस तनातनी में वकील और थानेदार सभी अपनी अपनी जेबें गरम करें और हर जगह यह सवाल पैदा हो।

गोचर भूमि का सवाल है। सीलिंग का टाइम आने वाला है मौका अब आ गया है सीलिंग का। इसमें जो जमीन निकले उसमें सबसे पहले गोचर की जमीन मुकर्रर की जावे और इसके बाद में दूसरों को अलॉटमेन्ट करें। एक अमेन्डमेन्ट आ रहा है उस वक्त हमारे राजस्वमन्त्री इस बात का ध्यान रक्खें कि उस समय जिस गांव में गोचर नहीं हैं वहां गोचर जमीन मुकर्रर पहले की जावे बाद में और को अलॉट की जावे।

फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के पास कुछ ऐसी जमीन है जिसका उपयोग नहीं होता है और वे लोग चराई डबल लेते हैं। उसकी मेहरबानी करके जांच कराएं और सर्वे करके पता लगाएं, अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो उसे चराई के लिये दिया जावे।

फिर एक फीस तय करिये। किसी में १२। कहीं ५) सैंकड़ा और कहीं ७) यह फर्क क्यों ? एक जगह की एक तरह की जमीन फिर यह अलग–अलग फीस क्यों ? फिर उसका भी निर्णय करने वाला कौन ? पटवारी। और पटवारी किस आधार पर करता है, जिसकी वह जेब गरम कर देता है उसके हक में निर्णय होता है। आपने इस तरह से छोड़ा कि पहले के ज़माने में जिस तरह लेते थे, वह ले लें। १२) लेते थे जागीरदार। अपने कोष में

(श्री मूलचन्द डागा)
लिखा दिया। कलम घिस दी आपके दफ्तर ने और वह कलम ही अब तलवार बन गई उन लोगों के लिये। तो श्रीमान् अगर जूडीशियल निर्णय आपको लेना है तो मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके इसके लिये कुछ करिये और अगर पशुधन आप बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी नस्ल के सांड, बैल, भेड़ आदि बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे मुल्कों में देना चाहते हैं तो इस तरफ ध्यान दीजिये। राजस्थान की यह नस्ल अगर चली गई तो राणा प्रताप जैसे वीर नहीं पैदा होंगे।

(हंसी)

अच्छी बात है कि हम अच्छे जानवर दूसरी जगह देना चाहते हैं पर उनको भूखों तो मत मारिये यह हमारा कहना है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनूं) : अब आप कल रिज्यूम कर लें।

श्री सभापति : मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब समाप्त कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् आपकी इच्छा और उम्मीद मेरे साथ हैं।

श्री सभापति : दूसरों की इच्छाओं का भी ख्याल रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कल दस मिनट ही लूंगा, साहब। तो मैंने प्रार्थना की, आपने जमीन के बारे में जो पूछा उसका संक्षेप में उत्तर दिया, जैसा मेरे दिमाग में था।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : टाइम हो गया, साहब।

श्री सभापति : असेम्बली की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर ५ बजे, कल दिनांक २० फरवरी, १९५९ को पूर्वान्ह ११ बजे के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, १९ फरवरी, ५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर २५०

काम दिलाऊ विभाग

आयुर्वेदिक औषधियों का बजट

चम्बल बांध से पैदा होने वाली बिजली

जयपुर-भरतपुर सड़क को नेशनल हाई वे की कोटि में लाना

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमेन के विरुद्ध शिकायत

तहसील देवली और उनियारा में एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालयों की मांग

रतनगढ़ निवासी सीताराम व अगरी बेवा की मोहनलाल सारस्वत के खिलाफ़ रतनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज

देवली तहसील की ग्राम पंचायत आवां के गलत वार्ड होने के बावजूद चुनाव

पुलिस हैड क्वार्टर्स में परेड ग्राउन्ड के निर्माण में अनियमितता

टोंक से उनियारा एवं सवाई माधोपुर से उनियारा तक सड़क की पुलियाओं का निर्माण

प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर (जयपुर) के भवन निर्माण में सरकार द्वारा सहायता

स्कम्भ

टोंक डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के तालाबों की मरम्मत

पंचायत पीलीबंगा तहसील सूरतगढ़ के सरपंच का अवैध चुनाव

बीकानेर जिले में सड़कों का निर्माण

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम का लागू होना

जसरासर से सूडसर तक सड़क

बीकानेर टाउन हाल का सार्वजनिक उपयोग

जयपुर शहर की सफाई की योजना

एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज बीकानेर

शहर विकास कमेटी की सदस्यता

राजस्थान नहर पर काम की प्रगति

बीकानेर जिले में मर्डर केसेज़ की बढ़ोतरी

समाचार पत्रों को मान्यता

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री अमृतलाल पायक, सदस्य विधान सभा, को दिनांक २०-२-५९ से १५-३-५९ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की गई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ३००

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

Page No.101

पर श्री हरिदेव जोशी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद विवाद प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया।

(१) श्री मदनसिंह दांता
(२) श्री जनार्दनराय नागर
(३) राजा श्री मानसिंह
(४) श्री मोतीलाल चौधरी
(५) श्री जयसिंह राणावत
(६) श्री रावल नरेन्द्रसिंह
(७) श्री होतीलाल
(८) श्री मूलचन्द डागा

शुक्रवार, दिनांक २० फरवरी, ५९ का कार्य विवरण—

१. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

२. (a) राजस्थान फारेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५९

(b) राजस्थान अनुशासिक कार्यवाही, तथा विधेयक, ५९.

(c) राजस्थान सेकेन्डरी—

एज्युकेशन (संशोधन) विधेयक, ५९.

नाथद्वारा मंदिर विधेयक ५९

३. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

उन संस्थाओं की विवरण सूचिका जिन्होंने टाउन हाल का उपयोग किया।

सरकारी संस्थायें

७।।≈)/ऑफिसर कमांडिग, एन० सी० सी०।

२५) रु० प्रिन्सिपल डूंगर कालेज बीकानेर।

५) रु० टिड्डी विभाग बीकानेर।

१२) रु० म्युनिसिपल बोर्ड बीकानेर।

५) रु० श्रम विभाग बीकानेर।

५) रु० जी० जी० जे० म्युजियम बीकानेर।

२०) रु० प्रिन्सिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर

१५) रु० जन सम्पर्क विभाग बीकानेर।

१५) रु० कलेक्टर बीकानेर।

२५०) रु० समाज शिक्षा विभाग जयपुर।

५) रु० डायरेक्टर कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज बीकानेर।

५) रु० नेशनल सेविंग आफिसर बीकानेर।

५) रु० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस बीकानेर।

---

३७५ रु० कुल रुपया

गैर सरकारी संस्थायें

३०८) रोटेरी क्लब बीकानेर।

१५) रु० भारत चीन मैत्री संघ बीकानेर।

५) रु० लोक कला मंडल उदयपुर।

२५) रू० नेशनल थियेटर बीकानेर

५) रु० ड्रामाटिक क्लब रोशनीघर बीकानेर।

१५) रु० रामकृष्ण कुटीर बीकानेर

५) रु० राजस्थान सोशल एण्ड इकोनोमेटिक कान्फरेन्स बीकानेर

५) रु० राजस्थान कला केन्द्र बीकानेर।

१५) रु० सेक्रेटरी इलेक्ट्रिक एण्ड वाटर वर्क्स यूनियन बीकानेर।

१५) रु० सेक्रेटरी एम० जे० परिषद बीकानेर।

५) रु० शंकरदत्तजी वैद्य बीकानेर।

५) अमरनाथजी बीकानेर।

५) रु० कैलाशनाथजी बीकानेर।

१५) रु० सादुल राजस्थानी रिसिर्च इन्स्टीट्यूट बीकानेर।

१०) रु० वीमेन नेशनल हॉकी

सरकारी संस्थाएं

गैर सरकारी संस्थाएं

चेम्पियन शीप ।

१०) रु० सेक्रेटरी आल इन्डिया लेको ट्रेनिंग स्टाफ ।

१०) रु० प्रिन्सिपल बाल भारतीय बीकानेर ।

२०) रु० बीकानेर शिक्षक संघ बीकानेर ।

१०) रु० मदनगोपाल दम्माणी बीकानेर ।

२०) रु० हिन्दी विश्वभारती बीकानेर

१०) रु० प्रजा सोसलिस्ट पार्टी बीकानेर ।

१०) रु० प्रोग्रेसिव फ्रेन्डस सोसल फंड बीकानेर ।

५३३।) रुपया

१०) रु० पंजाब क्लब बीकानेर ।

१०) रु० कला निकेनत बीकानेर ।

१०) जिला कांग्रेस बीकानेर ।

१०) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ बीकानेर ।

१०) रु० युवक कलाकार परिषद बीकानेर ।

---

५८३) रु० कुल रुपया ।

आय सरकारी	३७५) रु०
आय गैरसरकारी	५८३।) रु०
कुल आय	६५८।) रु०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिए)

LIST SHOWING THE NUMBER OF ADVERTISEMENT RELEASED TO NEWSPAPERS AND THE AMOUNT OF VERIFIED BILLS DURING 1957-58.

Name of Paper	Number of advertisement released.	Bills verified.	Amount of verified Bills.
1	2	3	4
1. Lokvani	263	236	12,893-00
2. Navyug	368	324	26,055-75
3. Rashtradoot	259	227	14,089-50
4. Rajasthan Patrika	224	212	11,333-75
5. Navjyoti	120	114	5,676-00
6. Amar Jyoti	76	74	6,857-50
7. Mashal	20	16	957-00
8. Adhikar	30	29	875-00
9. Rajasthan Affairs	3	2	315-00
10. Nai Shiksha	4	4	462-50
11. Rajasthan Chamber Patrika	1	1	142-12
12. Alwar Patrika	26	23	840-00
13. Rajasthan Times	18	18	514-75
14. Navyug Sandesh Bharatpur	42	39	1,627-00
15. Awaz Bharatpur	19	18	647-50
16. Gramvani Hindaun	6	6	264-00
17. Ayojan	55	42	7,212-00
18. Mira Ajmer	37	35	1,612-50
19. Jwala Ajmer	7	5	186-00

1	2	3	4
20. Hindwani Ajmer	5	3	90-50
21. Azad Ajmer	19	18	684-00
22. Hindu Ajmer	12	6	82-00
23. Nav Bharat Ajmer	1	1	30-00
24. Darbar Ajmer	8	8	177-00
25. Rashtra Vani Ajmer	2	2	159-00
26. Hindustan Ajmer	1	.	—
27. Praja Sewak Jodhpur	5	5	245-00
28. Jwala	95	91	5,829-00
29. Lalkar Jodhpur	74	74	4,083-20
30. Lok Jeewan Jodhpur	57	54	1.864-00
31. Prerna ,,	2	1	250-00
32. Marwar Times ,,	1	1	960-00
33. Rajasthan Directory Jodhpur	8	8	2,200.00
34. Senani Bikaner	79	74	3,277-37
35. Gan Rajya ,,	22	13	486-00
36. Lokmat ,,	42	35	1,444-00
37. Vartman ,,	17	15	445-50
38. Lok Jeewan ,,	6	6	183-00
39. Seema Sandesh Sri Ganganagar	24	19	839-00
40. Gram Sandesh ,,	7	5	153-50
41. Nav Jeewan	137	124	9,578-50
42. Arawali Udaipur	100	90	2,890-00
43. Pandrah August ,,	59	55	1,469-00
44. Kolahal ,,	71	65	2,055-00
45. Lok Jeewan Bhilwara	53	48	2,426-50
46. Lalkar Chittor	60	55	2,646-15
47. Pragati Udaipur	90	80	3,117-00
48. Pratap ,,	51	46	1,719-00
49. Rajasthan ,,	11	6	171-68
50. Kishan Sandesh Kota	99	93	4,314-50

1	2	3	4
51. Jan Vani ,,	74	69	5,002·54
52. Rajasthan Bundi	68	66	4,725·00
53. Dharti ke Lal Kota	17	14	533·00
54. Janta ki Awaz	9	9	396·50
55. Swadesh Kota	17	15	431·47
56. Rajasthan Chronical Jaipur	3	3	78·75
57. Marwar Times Jodhpur	6	6	210·00
58. Ahuti Sri Ganganagar	9	6	175·74
59. Karam Chari Sandesh Bikaner	3	2	74·25

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक १६ फरवरी, १६५६)

स्कम्भ संख्य	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२५३	नीचे से ६	मुस्स्सिल	मुकिसल
२५७	१५	स्थिापित	स्थापित
२५६	नीचे से ६	ग्रम	ग्राम
२६६	,, ११	तालबों	तालाबों
२६८	१५	चुचाव	चुनाव
२६६	१६	मूलप्रति भी में	मूलप्रति में भी
२७१	नीचे से	चुका हैं ?	चुकी हैं ?
२८३	४	मंउपत्री	उपमंत्री
२८६	१२	श्री गिरधीलाल	श्री गिरधारीलाल
२८६	नीचे से ११	एडर्वाटाइज़मेन्ट	एडवर्टाइज़मेन्ट
२६८	८	महदोय	महोदय
३०४	नीचे से १५	कार्यो शिथिलता	कार्यों में शिथिलता
३१६	१	दनसह	(श्री मदनसिंह)
,,	नीचे से ६	भुर्गों को	मुर्गों को
३१७	,, २	मालिकों के लडाया	मालिकों को लड़ाया ।
३२६	३	छत्म	खत्म
,,	६	शौषण	शोषण
३३६	१	(श्री जर्मादनराय नागर)	(श्री जर्नादनराय नागर)
३४४	१	(श्री जनार्तनराय नागर)	(श्री जर्नादनराय नागर)
३४८	१८	justifg	justify
३५०	७	Public funp	Public fund
३५५	१५	Certaih	Certain

१	२	३	४
३५६	१३	Govern mor	Governor
३५८	८	Forum	For
३६१	३	क्लैक्टिव	कलैक्टिव
,,	५	प्रत्येकें	प्रत्येक
३६८	नीचे से ११	महसस	महसूस
३७२	२	ब्राद्वान	आह्वान
३८२	७	निश्यात्मक	निश्चयात्मक
३८४	१०	ऑडर	ऑडिट
३८५	२	छिछालेदारी	छिछालेदरी
३८८	नीचे से ७	कॉन्युनिस्ट	काम्युनिस्ट
४३६	१३	जिनकी	जिनको
,,	नीचे से ११	धावी	धोबी
४३७	६	स्वस्थ	स्वस्थ्य